Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi
Ranchi ● Wednesday, 12 February 2025 ● Year : 03 ● Issue : 30 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

सुविचार

मन का मैल धोने के लिए नयन जल से अधिक उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है।

–प्रेमचंद

Rashmika Mandanna Seek Blessings...

SHARE

सेंसेक्स	:	76,293.60
निफ्टी	:	23,071.80

SARAFA

सोना	:	8,235
चांदी	:	107.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

जेईई मेन सत्र-1 का जारी हुआ रिजल्ट

NEW DELHI : जेईई मेन के 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों के परिणाम एनटीए ने जारी कर दिए हैं। सोमवार शाम से ही सोशल मीडिया पर जेईई मेन सत्र-1 परिणाम का लिंक वायरल हो रहा था। हालांकि, इसकी मदद से अभ्यर्थी परिणाम चेक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब एनटीए ने परिणाम लाइव कर दिया है। जो भी छात्र जेईई मेन सत्र-1 के पेपर-1 की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। जेईई मेन सत्र-1 पेपर-1 (बीई,बीटेक) की परीक्षा में 14 छात्रों ने 100 फीसदी अंक हासिल किए हैं। पेपर-1 की परीक्षा के लिए कुल 13,11,544 छात्रों ने पंजीकरण किया था। इनमें से 12,58,136 (95.93 फीसदी) छात्र परीक्षा में शामिल हुए। पेपर-1 की परीक्षा 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी, 2025 को कुल 304 शहरों में स्थित 618 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

एसटीएफ की नींव के पत्थर रहे अजय शर्मा का निधन

LUCKNOW : उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की नींव के पत्थर रहे वरिष्ठ आईपीएस अजय राज शर्मा का नोएडा में निधन हो गया। 1966 बैच के आईपीएस अजय राज शर्मा लंबे समय से बीमार थे। उनकी उम्र 80 वर्ष के करीब थी। उत्तर प्रदेश में कुख्यात गैंगस्टर श्रीप्रकाश शुक्ला के एंकाउंटर के लिए बनाई गई एसटीएफ टीम को वरिष्ठ आईपीएस अजय राज का नेतृत्व मिला था। इसके अलावा प्रदेश के तमाम नामचीन डकैतों एवं अपराधियों का भी अजय राज के नेतृत्व में एंकाउंटर किया गया था। उप्र के मिजार्पुर जनपद के मूल निवासी अजय राज शर्मा ने ग्रेजुएशन की शिक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ली थी और आईपीएस बनने के बाद उनके कार्यकाल को बेहतरीन कार्यकाल के रूप में जाना जाता है।

विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी ममता बनर्जी

KOLKATA : कुछ दिन पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के आए नतीजे में आम आदमी पार्टी की हार के बाद 'इंडिया' गठबंधन की एकता पर कई प्रकार से सवाल उठ रहे हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि 2026 में होने वाला पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की मदद नहीं की। हरियाणा में आप ने कांग्रेस की मदद नहीं की। इसी वजह से भाजपा दोनों राज्यों में जीत गई। सभी को एक साथ होना चाहिए, लेकिन बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। इसलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इस पर शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हमेशा अकेले लड़ती आ रही हैं। लेकिन, मेरा मानना है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 'इंडिया' ब्लॉक से नाता तोड़ लिया है।

11 लाख ने देखी 'स्वच्छ सुजल गांव' की तस्वीर

PRAYAGRAJ @ PTI : प्रयागराज के महाकुंभ मेले में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा बसाए गए 'स्वच्छ सुजल गांव' को अब तक 11 लाख से अधिक आगंतुकों ने देखा है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, यहां आने वाले श्रद्धालुओं ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार में आए बदलाव के बाद उत्तर प्रदेश के समृद्ध गांवों की कहानी देखी। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अतिथि देवो भवः की परंपरा का भी निर्वहन कर रहा है। स्वच्छ सुजल गांव में आने वाले आगंतुकों को 'जलप्रसाद' भी दिया जा रहा है। गांव में प्रतिदिन शाम को गंगा जल आरती भी हो रही है। महाकुंभ में 'जल मंदिर'भी बनाया गया है। 'जल मंदिर' में प्रदर्शित झांकी में भगवान शिव की जटा से गंगा धरती पर आ रही है। इसके जरिए संदेश दिया जा रहा है कि जल प्रसाद है, जल जीवनदायी है।

'जल मंदिर' में प्रदर्शित झांकी में भगवान शिव की जटा से धरती पर उतर रहीं मां गंगा

ग्रामीण जलापूर्ति विभाग कर रहा 'अतिथि देवो भवः' की परंपरा का भी निर्वहन

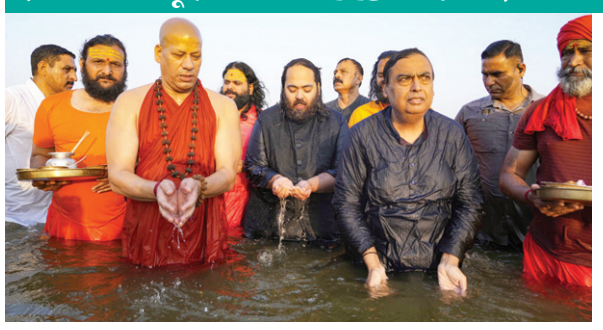

अंबानी की चार पीढ़ियों ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी

मंगलवार को रिलायंस इंड्रस्टीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी ने अपनी मां, बेटों और पोते-पोतियों के साथ प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान करते हुए पवित्र डुबकी लगाई। अंबानी के साथ उनकी मां कोकिलाबेन, बेटे आकाश और अनंत, बहुएं श्लोका और राधिका, पोते पृथ्वी और वेदा और बहनें दीप्ति सालगांवकर और नीना कोठारी ने एक साथ डुबकी लगाई। उनके साथ अंबानी की सास, पूनमबेन दलाल और भाभी, ममथाबेन दलाल भी थीं।

बदले बुंदेलखंड की गाथा का दीदार

जल जीवन मिशन के जरिए बुंदेलखंड के गांव-गांव में हर घर जल पहुंचाने की नई तस्वीर से भी आगंतुक रूबरू हो रहे हैं। वे यहां 2017 से पहले बदहाल और इसके बाद बदले बुंदेलखंड के बदलाव की गाथा का भी दीदार कर रहे हैं। देश-दुनिया से आए श्रद्धालु 40 हजार वर्गफीट क्षेत्र में बसे गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ग्राम पंचायत, सौर ऊर्जा के जरिये समृद्ध उत्तर प्रदेश की नई कहानी भी देख रहे हैं। राज्य सरकार के नेतृत्व में ग्रामीण जलापूर्ति एवं नमामि गंगे विभाग ने महाकुंभ-2025 में स्वच्छ सुजल गांव बसाया है।

बजट बनाने में समावेशी विकास पर दिया गया है ध्यान : निर्मला सीतारमण

NEW DELHI : वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को राष्ट्रीय विकास आवश्यकताओं का राजकोषीय प्राथमिकताओं के साथ संतुलन कायम करने वाला बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट के पीछे कई घरेलू और वैश्विक कारण हैं। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विश्व का परिदृश्य 180 अंश घूम गया है और बजट बनाना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह बजट अत्यंत अनिश्चितता और बदलते वैश्विक परिदृश्य में आया है, इसलिए इसे तैयार करने में कई चुनौतियां रहीं। उन्होंने कहा कि बजट बनाते समय समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात, रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक जीडीपी में स्थिरता जैसे वैश्विक कारकों का असर इस बजट पर भी पड़ा है।

राजनाथ सिंह ने वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में साझेदारी पर दिया जोर

BENGALURU @ PTI : अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 'एयरो इंडिया' में हिस्सा लेने आए 81 देशों के 162 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इसका विषय अंतरराष्ट्रीय रक्षा और वैश्विक जुड़ाव के माध्यम से लचीलापन निर्माण (ब्रिज) रखा गया। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक समुदाय से उन्नत प्रणालियों के सह-विकास और सह-उत्पादन में भारत के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में नवीन दृष्टिकोण और मजबूत साझेदारी की आवश्यकता है। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में 81 देशों के 162 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें 15 रक्षा मंत्री, 11 उप रक्षा मंत्री, 15 स्थायी सचिव और 17 सेवा प्रमुख शामिल थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के बीच का अंतर धुंधला हो रहा है, क्योंकि हाइब्रिड युद्ध में शांति के समय में भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की क्षमता है। साइबर स्पेस और आउटर स्पेस संप्रभुता की स्थापित परिभाषा को चुनौती दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक, हाइपरसोनिक और निर्देशित ऊर्जा जैसी विध्वंसकारी तकनीक युद्ध के चरित्र को बदलकर नई कमजोरियां पैदा कर रही हैं।

- 'एयरो इंडिया' में 81 देशों के रक्षा मंत्रियों का हुआ सम्मेलन, वैश्विक समुदाय से जुड़ने का आह्वान
- हाइब्रिड युद्ध में शांति के समय में भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की क्षमता

रक्षा मंत्रालय के प्रयासों की सराहना

सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्रियों ने एयरो इंडिया के आयोजन और विश्वस्तरीय निमार्ताओं को एक ही छत के नीचे नवीनतम नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अपनी रक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए भारत के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। प्रतिनिधियों ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवीनतम उपकरणों और उत्पादों के सह-विकास और सह-उत्पादन की अपनी इच्छा व्यक्त की और भारत को लचीली आपूर्ति शृंखला में भागीदार बताया। उन्होंने शांति स्थापना में भारत की भूमिका और रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई देशों की क्षमताओं को उन्नत करने की दिशा में इसके प्रयासों को स्वीकार किया। विचार-विमर्श के दौरान साझा सुरक्षा चिंताओं पर भी चर्चा हुई, जिसमें मंत्रियों ने सर्वसम्मति से सशस्त्र संघर्ष से बचने पर सहमति जताई। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने, आतंकवाद और साइबर अपराध जैसी विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करके इन खतरों के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया गया।

पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी ने कृत्रिम मेधा सम्मेलन को किया संबोधित

इस सदी में मानवता के लिए कोड बना रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

PARIS @ PTI : मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले स्रोत पर आधारित कृत्रिम मेधा (एआई) के लिए एक वैश्विक ढांचा स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयासों का पुरजोर समर्थन किया, जो विश्वास एवं पारदर्शिता बढ़ाने के साथ पूर्वाग्रहों से मुक्त हों। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वैश्विक एआई सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करते हुए कहा कि एआई राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज को बदल रहा है और इस सदी में मानवता के लिए व्यवस्था (कोड) बना रहा है। मोदी ने कहा, शासन और मानकों को स्थापित करने के लिए ऐसे सामूहिक वैश्विक प्रयासों की जरूरत है जो हमारे साझा मूल्यों को बनाए रखें, जोखिमों का ध्यान रखें और विश्वास पैदा करें। शासन केवल जोखिमों और प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह नवाचारों के प्रोत्साहन और उन्हें वैश्विक भलाई के लिए तैनात करने के बारे में भी है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाना चाहिए और आम लोगों पर केंद्रित एप्लिकेशन बनाने चाहिए। हमें साइबर सुरक्षा, गलत सूचना और डीप फेक से संबंधित चिंताओं का भी समाधान करना चाहिए।

राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज को बदलने में निभा रहा भूमिका

- इतिहास गवाह है कि तकनीक नौकरियां नहीं लेती, एआई से नई नौकरियां होंगी पैदा
- मानव समाज के लिए हर स्तर पर प्रौद्योगिकी को बनाया जाना चाहिए लोकतांत्रिक
- साइबर सुरक्षा, गलत सूचना और डीप फेक से संबंधित चिंताओं का किया जाए समाधान

शासन और नवाचारों पर हो खुलकर चर्चा

मोदी ने कहा कि एआई से जुड़ी सीमाओं और पूर्वाग्रहों को भी समझने की जरूरत है। हमें नवाचारों और शासन के बारे में गहराई से सोचना चाहिए और खुलकर चर्चा करनी चाहिए। खासकर वैश्विक दक्षिण में शासन सब लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में भी है। यहां पर क्षमताओं की सबसे अधिक कमी है, चाहे वह कंप्यूटिंग हो, बिजली हो, प्रतिभा हो, डेटा हो या वित्तीय संसाधन हों। उन्होंने कहा कि एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में बहुत कुछ बेहतर करके लाखों लोगों का जीवन बदलने में मदद कर सकता है। यह एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद कर सकता है, जिसमें टिकाऊ विकास के लक्ष्यों की यात्रा आसान और तेज हो। इसके लिए संसाधनों और प्रतिभा को एक साथ लाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई का इस्तेमाल बढ़ने पर नौकरियां जाने की आशंकाओं का जिक्र करते हुए कहा, इतिहास ने हमें दिखाया है कि प्रौद्योगिकी की वजह से काम कहीं जाता नहीं है। सिर्फ इसकी प्रकृति बदल जाती है और नई तरह की नौकरियां पैदा होती हैं।

गुणवत्तापूर्ण डेटा समूहों का विकास

पीएम ने पूर्वाग्रहों से मुक्त गुणवत्तापूर्ण डेटा समूहों के विकास पर जरूरत पर बल देते हुए कहा कि मुक्त स्रोत वाला ऐसा एआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाए।

सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा का रहा पुख्ता इंतजाम

10वीं-12वीं के वोकेशनल विषयों का लिया गया एग्जाम

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार से जैक बोर्ड मैट्रिक-इंटर की परीक्षाएं शुरू हो गईं। पहले दिन वोकेशनल विषयों का एग्जाम हुआ। दो शिफ्ट में हो रही बोर्ड परीक्षा के पहले शिफ्ट में 10वीं के परीक्षार्थी शामिल हुए। दूसरे शिफ्ट में इंटर के वोकेशनल विषयों की परीक्षा ली गई। सभी केंद्रों पर परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम था। परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रत्येक केंद्र पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पहले शिफ्ट की परीक्षा 9:45 बजे से दोपहर 1

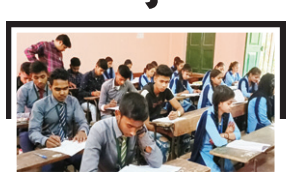

- कदाचार रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे

सुप्रीम कोर्ट से हेल्थ मिनिस्टर इरफान ने वापस ली याचिका

RANCHI : मंगलवार को झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर डॉ. इरफान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान उनकी ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। इरफान अंसारी ने झारखड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा 21 दिसंबर 2022 को इरफान अंसारी के विरुद्ध चार्ज फ्रेम किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने वर्ष 2018 में दुष्कर्म की शिकार एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ संज्ञान लिया था।

6 महीने में झारखंड सरकार को नया विज्ञापन जारी करने का दिया आदेश

चतुर्थ श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया असंवैधानिक : SC

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 2010 की भर्ती प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया निरस्त हो गई है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीने में उक्त पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करने और नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया कि उम्मीदवारों को उनकी बात सुनने का अवसर दिए बिना बर्खास्त करने का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि असंवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से की गई नियुक्तियों को संरक्षित नहीं किया जा सकता, भले ही उम्मीदवारों ने वर्षों तक काम किया हो और उनकी नियुक्ति रद्द करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई हो।

शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

नियुक्त लोगों को नहीं मिली राहत

बता दें कि 29 जुलाई 2010 के विज्ञापन के तहत अमृत यादव और अन्य कई लोगों की नियुक्ति चतुर्थ पद पर की गई थी। बाद में नियुक्ति के लिए किया गया विज्ञापन रद्द कर दिया गया। इसके बाद नियुक्त हुए लोगों ने पहले हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब यहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

न्यू स्टडी — विशेष प्रकार का रसायन पैदा कर तेजी से फैलते हैं विषाणु

स्किन को मच्छरों के काटने के अनुकूल बनाता है जीका वायरस

PHOTON NEWS, RESEARCH DESK : आंतरिक और बाहरी लक्षणों के अनुसार वायरस यानी विषिणु न तो पूर्ण रूप से सजीव है और न पूर्ण रूप से निर्जीव। यही कारण है कि जीव वैज्ञानिक इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। स्पष्ट रूप से यह देखा गया है कि अगर वायरस किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है, वह सजीव जैसा व्यवहार करने लगता है। अगर वह सजीव के शरीर के बाहर रहता है, तो निर्जीव की स्थिति में आ जाता है। उसकी प्रति प्रकृति क्रिस्टल जैसी हो जाती है। सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु मनुष्य में रोग पैदा करते हैं, इसलिए हानिकारक हैं। कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं, जो मनुष्य के लिए फायदेमंद हैं। वातावरण में नाइट्रोजन का फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इससे दाल उत्पादन में मदद मिलती है। दूध से दही बनाने का काम भी बैक्टीरिया ही करते हैं, लेकिन वायरस हमेशा हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये तरह-तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। हाल में हुए रिसर्च में यह पता चला है कि जीका वायरस इंसानी त्वचा को मच्छरों के काटने के अनुकूल बना देता है।

एडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से डेंगू या चिकनगुनिया जैसी पैदा होती है बीमारी

मानव कोशिकाओं में मौजूद जीन और प्रोटीन पर तेजी से असर डालता यह वायरस

- सामान्य रूप से दिन में ही काटते हैं इस विषाणु को फैलाने वाले मच्छर
- मच्छरों के काटने के तीन से 12 दिनों के बाद ही दिखाई पड़ते हैं रोग के लक्षण
- लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन से जुड़े शोधकर्ताओं ने किया है विशेष अध्ययन

भारत सहित दुनिया के लगभग 90 देशों में अब तक फैल चुका है यह वायरस

उपलब्ध नहीं है कोई निश्चित इलाज

शोध के निष्कर्ष की पुष्टि के लिए मेटा-प्रोटिओम विश्लेषण विधि का उपयोग किया गया जो यह अध्ययन करती है कि शरीर में जीन और प्रोटीन किस प्रकार समन्वय के साथ कार्य करते हैं। शोध में यह विस्तार से जानकारी दी गई है कि जीका वायरस सबसे पहले 1947 में युगांडा के बंदरों में पाया गया था।

त्वचा में आता है मेटाबॉलिक बदलाव

लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन से जुड़े शोधकताओं की ओर से किए गए अध्ययन से पता चला है कि इंसान की त्वचा पर स्थापित होकर जीका वायरस ऐसे रासायनिक संकेत भेजता है, जो मच्छरों को अधिक आकर्षित करते हैं। इससे वायरस को तेजी से फैलने में मदद मिलती है। जीका वायरस मानव त्वचा में मेटाबॉलिक बदलाव लाता है। इस वजह से त्वचा शरीर की रक्षा करने के बजाय और अधिक मच्छरों को आकर्षित करने लगती है। अंतरराष्ट्रीय जर्नल कम्युनिकेशन्स बायोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जीका वायरस त्वचा की कोशिकाओं (फाइब्रोब्लास्ट) में मौजूद जीन और प्रोटीन को परिवर्तित कर देता है। इस बदलाव के कारण त्वचा से अधिक मात्रा में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) निकलने लगते हैं जो मच्छरों को आकर्षित करने और उन्हें अधिक काटने के लिए प्रेरित करते हैं।

रामपुरहाट में 16 हजार किलो विस्फोटक जब्त

KOLKATA : पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट में पुलिस ने एक ट्रक से 16 हजार किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया है। यह विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट से भरे 320 बोरों में रखा गया था। पुलिस ने इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक कहां और किस मकसद से ले जाया जा रहा था, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सोमवार रात करीब 10 बजे रामपुरहाट से तारापीठ जाने वाली सड़क पर मुनसुबा मोड़ के पास एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में अमोनियम नाइट्रेट से भरे 320 बोरे बरामद हुए। प्रत्येक बोरे का वजन 50 किलोग्राम था, जिससे कुल विस्फोटक मात्रा 16 हजार किलोग्राम हो गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि यदि यह विस्फोटक इस्तेमाल किया जाता तो पूरा तारापीठ क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो सकता था। ट्रक के चालक और सहायक से पूछताछ में विस्फोटक से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले।

आईजी सिक्योरिटी के पद पर की गई है नियुक्ति

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए आईपीएस संजय लाठकर

PHOTON NEWS RANCHI : केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है कि झारखंड कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी संजय आनंद लाठकर को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का आईजी सिक्योरिटी नियुक्त किया गया है। आईपीएस संजय आनंद लाठकर मुंबई स्थित परमाणु मुख्यालय में योगदान देंगे। संजय आनंद के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद झारखंड में एडीजी रैंक के अधिकारियों की कमी हो जाएगी। इससे पहले झारखंड पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाने वाला स्पेशल ब्रांच भी एडीजी के बिना ही चल रहा है। राज्य में अभी भी कई महत्वपूर्ण विभागों में एडीजी रैंक के अधिकारी नहीं हैं।

- केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग में सुरक्षा का दिया महत्वपूर्ण दायित्व
- राज्य में एडीजी अभियान के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे लाठकर

BRIEF NEWS

सम्मेद शिखर में 12 मार्च को जुटेगा आदिवासी समाज

GIRIDIH : जैन धर्मावलम्बियों के 20 तीर्थंकर के निर्वाण सम्मेद शिखर और प्राकृतिक उपासक आदिवासियों के प्रधान मारंग बुरु जुग जाहेरथान पारसनाथ पर्वत को लेकर प्राकृतिक उपासकों ने एक बार फिर बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। पारसनाथ का अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए संथालियों के पूजन स्थल मरांग बुरु दिशोम मांझीथान के सुधीर बास्के ने कहा कि आदिवासियों के पूजन स्थल मरांग बुरु का अतिक्रमण सहन नहीं होगा। आंदोलन के प्रथम चरण में 12 मार्च को देश के कई राज्यों के आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों का जुटान मधुबन में होगा। इसमें आंदोलन की रूप रेखा तय होगी । हालांकि अतिक्रमण का आरोप किन पर है ये सुधीर बास्के ने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन 12 मार्च को एक बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि चार साल पहले भी सम्मेद शिखर मधुबन के पारसनाथ पहाड़ को लेकर विवाद हुआ था। एक तरफ जैन समाज ने बड़े व्यापक पैमाने पर आंदोलन करते हुए देश भर में प्रदर्शन किया था । दूसरी तरफ झारखंड, बिहार, ओड़िशा और बंगाल के हजारों की संख्या में आदिवासी नेताओं के साथ युवाओं का जुटान मधुबन में हुआ था। इस दौरान मामले की गंभीरता को समझते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण माहौल में दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर विवाद बढ़ने से रोक दिया था। लेकिन एक बार फिर चार साल बाद 12 मार्च को संताली समाज आंदोलन का बिगुल फूंकने की तैयारी में है।

एमबीएनएस के शिविर में 50 यूनिट रक्तदान

JAMSHEDPUR : एमबीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में संस्थान के छात्रों, स्टाफ और अभिभावकों ने भाग लेकर 50 यूनिट रक्तदान किया। इस अवसर पर एमबीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन विवेक सिंह ने कहा कि रक्तदान एक महान कार्य है, जो मानवता की सेवा करने में मदद करता है। हमें गर्व है कि हमारे छात्र, स्टाफ और अभिभावकों ने इस शिविर में भाग लेकर रक्तदान किया।

'प्रमंडल स्तर का होगा आदिवासी विकास महाकुंभ'

PALAMU : पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के तत्वावधान में दो दिवसीय राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला मंगलवार से शुरू हुआ। मेदिनीनगर सदर प्रखंड के दुबियाखाड़ में लगे मेले का वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इसका शुभारंभ किया। मेले में परिसंपतियों का वितरण किया गया। योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों के 46 स्टॉल लगाए गए थे। मेला 12 फरवरी तक आयोजित है। मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि समाज का हर वर्ग आगे बढ़े। आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज का भी उत्थान हो। इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। झारखंड में आदिवासी समाज का साक्षरता दर 52 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से नीचे है। ऐसे में शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। शिक्षित होने से आदिवासियों के बच्चे विधानसभा एवं लोकसभा के सदस्य बनेंगे। इससे गर्व की अनुभूति होगी। उन्होंने हर वर्ग-समुदाय के शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एकजुट रहेंगे,तो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से यह मेला प्रमंडल स्तर पर होगा। इसमें तीनों जिले पलामू, लातेहार व गढ़वा जिले के आदिवासी समाज भाग लेंगे, इसके लिए सरकार के स्तर पर तैयारी की जा रही है। उन्होंने मंईया सम्मान योजना के लाभ से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सम्मान राशि से महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा कर रहीं हैं। बच्चों की पढाई में खर्च कर उन्हें आगे बढ़ा रहीं हैं। इस अवसर पर कल्याण मंत्री ने कहा कि समाज की बेहतरी के लिए शिक्षा जरुरी है। विकास के लिए समाज को एकजुट रहना भी महत्वपूर्ण है।

लोहरदगा में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, एक गंभीर

सेन्हा थाना क्षेत्र में चारपाई बेचकर लौट रहा था व्यक्ति, बाइक ने मार दी मोपेड में टक्कर

AGENCY LOHARDAGA : सेन्हा थाना क्षेत्र में बाइक और लूना (मोपेड) की टक्कर में कोराम्बे निवासी एतवा उरांव का पुत्र प्रवीण उरांव (25) का पैर टूट गया। प्रवीन शहर से अपने गांव जा रहा था जबकि दूसरा व्यक्ति बंसी बंजारा चारपाई बेचकर लौट रहा था। इसी दौरान दोनों बाइक में जोरदार टक्कर हो गयी, जिसमें प्रवीण उरांव का पैर टूट गया। जबकि बंसी बंजारा जो की जिला नीमच गांव मोरन मध्यप्रदेश का रहने वाला था। अस्पताल में इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। लोगों ने बताया कि उसके सर में गंभीर चोट लगी थी। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। सड़क दुर्घटना में मृत एवं घायल दोनों लोगों ने हेलमेट नहीं पहनी थी। यदि हेलमेट पहनते तो जान बच सकती थी। थोड़ी सी लापरवाही ने एक की जान ले ली और दूसरे को अपंग बना दिया।

घटनास्थल पर गिरा व्यक्ति

बाइक और लॉकेट चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार

AGENCY PALAMU : बाइक और सोने की लॉकेट चोरी की घटना का मेदिनीनगर शहर थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक लुटेरे और एक ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया है। बाइक और सोने का लॉकेट बरामद किया है। लुटेरे की पहचान हमीदगंज बीएन कॉलेज के पास रहने वाले संजीत ओझा और ई-रिक्शा चालक पप्पू कुमार के रुप में हुई है। रांची रोड रेड़मा के जितेन्द्र कुमार सोनी ने 10 फरवरी को घर के पास खड़ी स्पेलेंडर प्लस बाइक (जेएच03एपी 4920) चोरी हो जाने का मामला दर्ज कराया था। तेजी से अनुसंधान करते हुए गुप्तचरों से मिली सूचना पर बीसफुटा पुल के पास से चोरी गई बाइक पर सवार चोर संजीत ओझा को गिरफ्तार किया गया। संजीत ओझा पूर्व में ड्रोन कैमरा लूट मामले में जेल जा चुका है। साथ ही पुलिस ने पांच फरवरी को बेलवाटिका गुरूद्वारा के समीप पूंजय कुमार गुप्ता के पांच वर्षीय पुत्र के गले से सोने का लॉकेट निकाल लेने वाले ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया । आरोपित के द्वारा बच्चे के गले से सोने का लॉकेट निकालने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। अनुसंधान के दौरान आरोपित की पहचान की गयी और उसे गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर सोने का लॉकेट बरामद किया गया। ई-रिक्शा चालक पप्पू वर्ष 1998 में हत्या मामले एवं वन विभाग की लकड़ी चोरी कांड में जेल जा चुका है। शहर थाना स्थित इंस्पेक्टर कार्यालय में थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने इस संबंध में पूरी जानकारी दी।

मामले की जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी ● फोटोन न्यूज

पुलिस ने 10.5 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट

CHAKRADHARPUR : अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने मंगलवार को जिला में करीब 10.5 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। जानकारी के अनुसार, मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के टेबो थाना अंतर्गत ग्राम जराकेल में करीब 3 एकड़, बंदगाव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिंदुरिबेडा, गुंडई में करीब 4 एकड़ में फसल लगी थी। इसके अलावा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निरंतर जागरूकता अभियान से प्रभावित होकर टोकलो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हतनाबेड़ा में ग्रामीणों ने लगभग 3.5 एकड़ सहित जिला में करीब 10.5 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया।

जनता की समस्या दूर करना प्रशासन की प्राथमिकता : डीसी

महिला की समस्या सुनते उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ● फोटोन न्यूज

LATEHAR : उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण का आयोजन किया गया। इसमें जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी समस्या सुनाई। उपायुक्त ने सभी लोगों से एकझएक कर उनकी समस्या सुनी एवं आश्वासन दिया कि उनकी सभी शिकायतों का जल्द से जल्द जांच कराते हुए समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्या दूर करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। वृद्धा पेंशन को लेकर मनिका प्रखंड के कईल मियां ने 4 महीने से पेंशन नही मिलने के कारण हो रही समस्या बताई। इसी प्रकार अन्य लोगों ने भी अपनी समस्या रखी। लोगों से प्राप्त आवेदन के आलोक में उपायुक्त ने समस्या निदान के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया।

इचाक स्वास्थ्य केंद्र पूरे झारखंड में अव्वल

स्वास्थ्य विभाग ने उपायुक्त व उपविकास आयुक्त को दी बधाई

PHOTON NEWS HAZARIBAG : एनएचएसआरसी, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनक्यूएएस (नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड) मूल्यांकन के परिणाम घोषित किए गए हैं।

गर्व की बात है कि हजारीबाग में सभी सुविधाओं को पूर्ण प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर करियातपुर, ब्लॉक इचाक ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए झारखंड में सबसे अधिक 93.12 अंक प्राप्त किए हैं।

उपायुक्त नैन्सी सहाय ने स्वास्थ्य विभाग एवं डीएमएफटी हजारीबाग की टीम को बधाई दी है।

जिला को यह उपलब्धि प्राप्त होने पर स्वास्थ्य विभाग ने उपायुक्त के पूर्ण सहयोग तथा उल्लेखनीय सोच का परिणाम बताया एवं उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को बधाई दी। जिले के 28 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को डीएमएफटी द्वारा आईपीएचएस मानकों के अनुसार उपकरण, दवाएं और कंज्यूमेबल्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो एनक्यूएएस के राष्ट्रीय प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान में, 17 केंद्रों के लिए सक्षम पोर्टल पर राष्ट्रीय प्रमाणीकरण के लिए आवेदन किया गया है, जिनमें से 10 सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय प्रमाणीकरण कार्यक्रम का परिणाम जारी किया गया है। इनमें से 4 का प्रमाणीकरण हो चुका है, 4 का परिणाम लंबित है, और 2 का मूल्यांकन इसी महीने होना है।

हजारीबाग में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान शुरू

HAZARIBAG : समाज को नशे की चपेट से मुक्त कराने और युवाओं को एक सुरक्षित भविष्य देने के उद्देश्य से हजारीबाग जिला प्रशासन और हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से एक नशा मुक्ति जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इस अभियान को समाहरणालय परिसर से उपायुक्त नैन्सी सहाय ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने कहा कि यह अभियान सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज के लिए एक नई उम्मीद है, जो आने वाले समय में हजारीबाग को नशामुक्त जिला बनाने में सहायक साबित होगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना और पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से उन लोगों की मदद करना है, जो पहले से नशे के शिकार हो चुके हैं।

मैट्रिक व इंटर की परीक्षा शुरू डीसी-एसपी ने किया निरीक्षण

RAMGARH : मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। रामगढ़ जिले में 12669 छात्र मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए हैं। जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 12300 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया है। इन दोनों परीक्षाओं के लिए 93 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए 53 परीक्षा केंद्र बने हैं। इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

परीक्षा शुरू होने के बाद डीसी चंदन कुमार और एसपी अजय कुमार ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। डीसी एवं एसपी ने राधा गोविंद पब्लिक स्कूल सहित अन्य विद्यालयों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया । उन्होंने केंद्र पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और सीसीटीवी कैमरे का जायजा लिया। डीसी ने केंद्राधीक्षकों सहित परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों एवं शिक्षकों को पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने झारखंड अधिविध परिषद द्वारा जारी नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमारी नीलम सहित अन्य उपस्थित थे।

परीक्षा केंद्र पहुंचे डीसी व एसपी

अब बिजली के खंभे पर भी विधायक लिखवाएंगे अपना नाम : सरयू राय

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में लगाए जा रहे विद्युत ट्रांसफॉर्मरों के ऊपर पहले से विधायक बन्ना गुप्ता का नाम मोटे अक्षरों में पेंट किया हुआ है। मानगो के शंकोसाई रोड नं-5 का ट्रांसफार्मर सोमवार से खराब था। विधायक सरयू राय के समर्थकों एवं जनसुविधा प्रतिनिधियों की पहल पर मंगलवार की शाम खराब ट्रांसफार्मर को बदलकर लगाने के लिए नया ट्रांसफार्मर आया तो लोगों का ध्यान इस ओर गया कि ट्रांसफार्मर के ऊपर मोटेमोटे अक्षरों में विधायक की जगह पूर्व विधायक बन्ना गुप्ता का नाम पेंट किया हुआ था। इसका विरोध हुआ तो ट्रांसफार्मर लगाने वाले उस ट्रांसफार्मर को लेकर जाने लगे। लोगों ने कहा कि जब तक दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं आ जाता, तब तक इस ट्रांसफार्मर को नहीं ले जाने देंगे। विधायक सरयू राय ने कहा कि यह छिछोरी हरकत है। ऐसे में अब तो बिजली के खंभे पर भी विधायक अपना नाम लिखवाने लगेंगे।

उपायुक्त के जनता दरबार में फरियादियों ने लगाई गुहार

PHOTON NEWS HAZARIBAG : समाहरणालय सभागार में मंगलवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें दूरदराज से आए फरियादियों ने समस्या दूर करने की गुहार लगाई। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आमजनों की समस्या सुनी तथा इसके त्वरित समाधान के निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया। शहरी सहित विभिन्न प्रखंड से आए आवेदकों ने पीडीएस दुकान, मारपीट, आवास योजना का लाभ दिलाने, दाखिल खारिज, पेंशन, भूमि अतिक्रमण, तिपहिया साइकिल दिलाने, भूमि पर अवैध कब्जा आदि से संबंधित आवेदन देकर समाधान की मांग की।

कोलघट्टी सदर की जीनत खातून ने उपायुक्त को बताया कि उनका दिव्यांगता पेंशन कई महीनों से रुका हुआ है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उपायुक्त ने तत्काल सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी को समाधान का निर्देश दिया। वहीं चुटियारो के संतोष कुमार ने जनवतिरण प्रणाली दुकान फिर से चलाने, कटकमदाग की रुखसाना खातून ने घर में घुस कर मारपीट करने वाले पर कार्रवाई करने, टाटीझरिया के प्रभु रविदास ने आवास दिलाने, चौपारण के राजू पासवान ने दाखिल-खारिज के संबंध में, बड़कागांव के जगतपाल महतो ने जमीन का खतियान और रसीद ऑनलाईन चढ़ाने, चलकुशा के दिव्यांग अजय कुमार वर्णवाल ने बैट्री साइकिल उपलब्ध कराने, पम्मी कुमारी ने सरकारी स्टाम्प बिक्रय के लिए जगह मुहैया कराने, सदर के शुभम कुमार खंडेलवाल ने भूमि पर अवैध कब्जा हटाने, रामचंद्र कुमार केरेडारी ने बीट के अनुसार परीक्षा फल निर्गत करने आदि से संबंधित आवेदन दिए।

लोगों की शिकायत सुनतीं उपायुक्त नैन्सी सहाय ● फोटोन न्यूज

सुरक्षित इंटरनेट डे पर पूरे राज्य में हुई कार्यशाला, दी गई खतरों से बचने की जानकारी

प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मियों को किया गया साइबर थ्रेट से सचेत

PHOTON NEWS HAZARIBAG : उपायुक्त नैन्सी सहाय के निदेर्शानुसार जिला सूचना एवं विज्ञान विभाग हजारीबाग के तत्वधान में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर कार्यशाला हुई। इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों व अन्य कर्मियों को सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारी दी गई।

कार्यशाला में डीआईओ संदीप कुमार और डीपीओ यूआईडी प्रवीण कुमार सुमन ने इंटरनेट डे के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। कार्यशाला में उपस्थित लोगों को कॉमन साइबर थ्रेट जैसे फिशिंग, विशिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, लॉटरी स्कैम, फेक एप्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, साइबर हाइजिन, पब्लिक वाई-फाई, वीपीएन, यूजिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूपीआई, हाउ टू सिक्योर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस, डिजिटल अरेस्ट, टू स्टेप वेरीफिकेशन, डीप फेक वीडियो आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उपविकास आयुक्त ने कहा कि इंटरनेट एक तरफ वरदान है तो दूसरी तरफ अभिशाप, इसलिए इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इंटरनेट का दुरुपयोग करने से हम सबका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इंटरनेट का सही इस्तेमाल कैसे हो, इसका प्रचार-प्रसार करना आवश्यक है।

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी संदीप कुमार ने सर्वप्रथम इंटरनेट के उद्भव एवं विकास के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस वैश्विक रूप से मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि साइबर स्वच्छता की प्रक्रिया के तहत आमजन एवं अधिकारियों को उनके कंप्यूटर उपकरणों एवं उसमें रखी गई व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा बनाए रखने में मदद करती है। इससे डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि पूरे जिले के प्रज्ञा केंद्र और पंचायत भवन में वीएलई द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। कार्यशाला का उद्घाटन उपविकास आयुक्त इश्तियाक अहमद, प्रशिक्षु आईएएस लोकेश बारंगे, प्रशिक्षु एसडीपीओ अमित आनंद, डीपीओ पंकज तिवारी, डीडब्ल्यूएसो शिप्रा सिन्हा, डीआईओ संदीप कुमार, डीपीओ यूआईडी प्रवीण कुमार सुमन सहित कई पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते प्रशासनिक पदाधिकारी ● फोटोन न्यूज

इंटरनेट का दुरुपयोग खतरे को देता न्योता : डीसी

RAMGARH : सुरक्षित इंटरनेट दिवस (सेफर इंटरनेट डे) पर मंगलवार को न्यू टाउन हॉल में कार्यशाला हुई, जिसमें उपायुक्त चंदन कुमार व पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने साइबर अपराध से बचाव व इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी दी। डीसी, एसपी व डीडीसी ने बताया कि इंटरनेट का दुरुपयोग खतरे को न्योता देता है। साइबर अपराधी फर्जी एप डाउनलोड कराकर खाता खाली कर देते हैं। लॉटरी लगने का झांसा देकर चपत लगाते हैं। गूगल में कुरियर सर्विस के नाम पर ठगी होती है। ओएलएक्स में सामान बेचने के नाम पर ठगी हो रही है, तो बड़ी कंपनी के नाम पर भी लोगों को झांसा दिया जाता है। आजकल ऑनलाईन शॉपिंग के नाम पर खूब फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड आपको आपके किसी परिजन की गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे ऐंठ लेते हैं। किशोर व बच्चे ऑनलाईन गेम में फंस रहे हैं। साईबर फ्रॉड होने के बाद 2-3 घंटे बहुत ही अहम होते है, जिसमें आपके पैसे बचाए जा सकते हैं। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। इस मौके पर गुरुनाक पब्लिक स्कूल, रामगढ़ के बच्चों ने नाटक के माध्यम से इंटरनेट, सोशल मीडिया एवं साइबर अपराध के संबंध में जागरूक किया। कार्यशाला में उपविकास आयुक्त, रामगढ़, प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), पुलिस निरीक्षक, यातायात, गुरुनाक पब्लिक स्कूल, रामगढ़, डीएवी पब्लिक स्कूल, रामगढ़ के शिक्षक व बच्चे एवं अन्य आम जनता उपस्थित रहे।

अनजाने लिंक या कॉल से बचने की दी गई सलाह

छात्रों को संबोधित करते एसएसपी किशोर कौशल ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : उपायुक्त अनन्य मितल के निदेर्शानुसार सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर मंगलवार को करीम सिटी कॉलेज में कार्यशाला की गई, जिसमें प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी के अलावा कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षक एवं छात्र शामिल हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, एडीएम अनिकेत सचान, एसडीएम धालभूम शताब्दी मजूमदार, प्राचार्य करीम सिटी कॉलेज समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया । राष्टीय सूचना विज्ञान केंद्र, पूर्वी सिंहभूम के तत्वधान में आयोजित कार्यशाला में इंटरनेट का उपयोग, साइबर क्राइम से बचने के तरीके, साइबर क्राइम के विरूद्ध कानूनी प्रक्रिया आदि को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई।

साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल करें 1930 पर कॉल

CHAIBASA : सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर मंगलवार को प्रखंड सभागार, सदर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर कार्यशाला हुई, जिसका उद्घाटन सहायक समाहर्ता-सह-प्रशिक्षु आईएएस अर्नव मिश्रा, डीआईओ संजीव कुमार, एडीआईओ मनिष जांगीड़, ईडीएम साकिब सलाम खान सहित अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में जिला स्तरीय अधिकारियों, कार्यरत प्रधान लिपिक, सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर,वीएलईएस, आईसीटी प्रशिक्षक व अन्य कर्मियों को सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारी दी गई। साइबर अपराध से संबंधित किसी भी शिकायत को अविलंब हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर बताएं।

न्यूज इंपैक्ट... वसी जफर इकबाल, वसीम जफर कैफी व वसीम कमल के खिलाफ दर्ज किया गया मामला

एसएसपी की फटकार के बाद अरगोड़ा थानेदार ने की एफआईआर

CRIME REPORTER RANCHI : रांची में एक युवक से पांच लाख रुपये ठग लिए गए। तीन युवकों ने बिजनेस में पैसे लगाने के नाम पर यह ठगी की। रांची एसएसपी की फटकार के बाद अरगोड़ा थाना में मामला दर्ज किया गया। पीड़ित सुहैल अंसारी की शिकायत पर वसी जफर इकबाल, वसीम जफर कैफी व वसीम कमल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। गौरतलब है कि पीड़ित पिछले एक साल से अरगोड़ा थाना का चक्कर लगा रहा था। थाने में मौजूद पुलिस पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। 'द फोटोन न्यूज' ने इस मुद्दे को उठाया। 09 फरवरी के अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लिया। एसएसपी ने अरगोड़ा थानेदार को फटकार लगाई। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। बता दें कि अरगोड़ा पुलिस के रवैए से परेशान होकर पीड़ित ने रांची एसएसपी से भी न्याय की गुहार लगाई थी।

पिछले एक साल से अरगोड़ा थाना का चक्कर लगा रहा था युवक, पीड़ित के साथ किया जा रहा था दुर्व्यवहार

'द फोटोन न्यूज' ने उठाया था मुद्दा, प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी खबर, एसएसपी ने जांच कराने की कही थी बात

पांच लाख की ठगी का है मामला

एफआईआर में बताया गया है कि 2016 से 2023 तक वसी जफर इकबाल व उसका भाई वसीम जफर कैफी उसके घर के पास रहते थे। इस दौरान उन्होंने अप्रैल 2022 में उनकी मुलाकात वसीम कमल से कराई थी। वसीम कमल डोरंडा थाना क्षेत्र के परस टोली का रहने वाला है। वसीम कमल ने पीड़ित युवक को बिजनेस में पैसा लगाने व इससे आने वाले मुनाफा के बारे में बताकर झांसे में लिया। वसीम कमल और वसी ने पीड़ित युवक को एक लाख रुपये में हर महीना 10 प्रतिशत मुनाफा देने का लालच दिया। इसके बाद वसीम और वसी ने पीड़ित युवक से चार लाख रुपये लिए। वसीम और वसी ने पीड़ित की मौसी को भी झांसा देकर एक लाख रुपये ले लिया। वसी जफर और वसीम कमल ने पीड़ितों को एक लाख पर 10 प्रतिशत महीना मुनाफा देने का एग्रीमेंट भी किया। इसके बाद 4 से 6 महीनों तक मुनाफा भी मिला। आरोप है कि इसके बाद आज तक न कोई मुनाफा दिया, न ही उनके द्वारा दिए गए रुपये वापस किए गए।

आरोपी वसी जफर इकबाल

आरोपी वसीम कमल

जान से मारने की मिल रही धमकी

एसएसपी को दिए आवेदन में बताया था कि 2023 में बिजनेस में पैसे लगाने के नाम पर तीन युवकों ने उनसे पांच रुपये ठग लिए। रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़ित ने बताया है कि वह पिछले एक साल से अरगोड़ा थाना के चक्कर काट रहे हैं। आज तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। थाना जाने पर वहां मौजूद पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार करते हैं। पुलिस कह रही है कि ठगा गए हो तो पुलिस वाले तुम्हारे पैसे देंगे क्या। पीड़ित ने बताया है कि एफआईआर करने को कहने पर ऑफिसर के छुट्टी पर होने का हवाला दिया जाता है। पुलिस कहती है यह थाना है, यहां सिर्फ क्राइम से संबंधित केस दर्ज किया जाता है। कोर्ट जाकर केस करो। पीड़ित ने इस मामले में ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज कराई है। लेकिन, वहां से भी उसको कोई मदद नहीं मिली। पीड़ित ने लिखा है कि वह थाना जा-जाकर थक गया है। परेशान होकर वह एसएसपी की शरण में आया है।

BRIEF NEWS

मंदिर निर्माण के लिए किया पांच लाख का सहयोग

RANCHI : सिमडेगा में बने श्री श्याम मंदिर में खाटू वाले श्याम बाबा के भक्त अजय मयंक जैन और आनंद गोयल (नेहा ट्रैक्टर) वाले रांची से मंगलवार को सिमडेगा पहुंचे और श्याम मंदिर का अवलोकन किया और बाबा की मोर छड़ी का मोर पंख जो अपने साथ लाए थे उसका पूजन किया। अजय मयंक जैन परिवार द्वारा अपने हाथों द्वारा पांच लाख रुपए मंदिर निर्माण में सहयोग दिया और मंदिर निर्माण में और सहयोग करने का आश्वासन दिया। मोहन दास महाराज खाटू वाले से फोन पर स्वीकृति भी मिल गई है उनके सानिध्य में ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कराया जाएगा। उनका बहुत जल्द आगमन सिमडेगा में होगा।

वाटर क्राइसिस से निपटने को लेकर बना समर एक्शन प्लान

RANCHI : रांची में आगामी गर्मी को देखते हुए जलापूर्ति से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार को उप प्रशासक गौतम कुमार साहु की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें जलापूर्ति शाखा के सभी इंजीनियर, पाइपलाइन निरीक्षक, पेयजल एवं स्वच्छता के विभिन्न प्रमण्डलों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। उप प्रशासक ने आगामी गर्मी के मौसम में पेयजलापूर्ति की समस्या से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि गर्मी में भू-गर्भ जल का कम से कम दोहन किया जाए और इसके लिए सरफेस वाटर से टैंकर फीलिंग की व्यवस्था की जाए। इस उद्देश्य के तहत, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जानी है। जैसे लटमा हिल्स, कांके डैम, यूजीआर 1 और यूजीआर 2, सिरम टोली सम्प, कांटोटाली बस स्टैंड सम्प, कर्बला चौक सम्प, पिस्का मोड़ सम्प, कुसई कॉलोनी सम्प सहित अन्य क्षेत्रों में सरफेस उपलब्ध कराया जाएगा।

फरवरी में ही 36 डिग्री पर पहुंचा राज्य का पारा

RANCHI : राज्य में फरवरी माह में ही तापमान बढकर 36 डिग्री हो गया है। मंगलवार को सरायकेला में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अभी फरवरी का महीना आधा भी खत्म नहीं हुआ है। देश भर में झारखंड की पहचान एक हरे भरे राज्य के रूप में होती है, लेकिन राज्य गठन के बाद से राज्य में वनों की तेजी से कटाई हो रही है। गांव से लेकर शहरी इलाकों में भी सड़क, पुल और आवास निर्माण समेत अन्य जरूरी विकास कार्यों के लिए हर दिन हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है।

भू-राजस्व, भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ ने की विभागीय समीक्षा, कहा-

सीओ ने दाखिल-खारिज का आवेदन बेवजह रिजेक्ट किया तो होगी कार्रवाई

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि अंचलों में तकनीकी कारणों का हवाला देकर रैयतों के आवेदनों को बेवजह रिजेक्ट करने पर अंचलाधिकारी (सीओ) पर अब कार्रवाई होगी। साथ ही अंचलों में दाखिल खारिज संबंधित मामलों पर आवेदनों की अस्वीकृत या आपत्ति के कारणों को सीओ को 50 शब्दों में ठोस बातें लिखकर स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य है। मंत्री प्रोजेक्ट भवन में भू-राजस्व, भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में मंत्री के अलावा सचिव चंद्रशेखर, विशेष सचिव शशि प्रकाश झा, भूमि निदेशक भोर सिंह यादव समेत जिलों से आए एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बिरुआ ने कहा कि कई बार तकनीकी कारणों से झारभूमि साइट नहीं खुलने की बातें लिखकर अंचल अधिकारी आवेदनों को रिजेक्ट करने का बहाना बनाते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। जमीन मामले में अंचलों में कई गड़बड़ियां हैं। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। इसलिए सभी अंचल अधिकारी पदाधिकारी सचेत हो जाएं और ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करें।

आवेदन नामंजूर करने पर अंचलाधिकारी को 50 शब्दों में बताना होगा ठोस कारण

आरओबी बनाने पर ग्रामीण सड़कों पर दें ध्यान

एनएचएआई कार्य परियोजना को लेकर मंत्री ने दो टूक कहा कि जहां-तहां आरओबी बनाने के चक्कर में ग्रामीण सड़कों को छोड़ दिया जाता है, जो गलत है। आरओबी ऊपर में बनने और नीचे जगह छूटने से आमजनों को परेशानियां होती है। उन्होंने लैंड एक्वीजिशन को लेकर समय पर मुआवजा दिलाने की बात कही। साथ ही कहा कि एनएचएआई की जिम्मेवारी है कि पदाधिकारी लैंड एक्वीजिशन संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान करें। विभागीय सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि राजस्व संग्रहण का वार्षिक लक्ष्य के तहत कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि कमजोर प्रदर्शन करनेवाले अंचलों की समीक्षा कर सुधारात्मक रणनीति अपनाई जाएगी। उन्होंने एलआरडीसी और एसी को अंचलों में लगनेवाले कैंप की विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया।

मॉडर्न रूम को करें दुरुस्त, समय पर कार्य निपटाएं सभी कर्मचारी

बिरुआ ने कहा कि कई मॉडर्न रिकॉर्ड रूम से खतियान निकालने पर सही छपाई नहीं होती। खतियान फोटो कॉपी नहीं दिखता है। ऐसी विसंगतियों को दुरुस्त किया जाए। स्पष्ट स्कैनिंग नहीं होने पर रैयतों को अपने जमीन की सही जानकारी नहीं मिल पाती। खतियान निकालने के बाद भी रैयतों को परेशानी नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि मॉडर्न रूम में कैथी और बंगला भाषा में लिखे खतियान को ट्रांसलेट करने सुविधा देने की आवश्यकता है। मौके पर भू-राजस्व विभाग के निदेशक भोर सिंह यादव ने दाखिल खारिज के

अनुचित कारणों और इसके अद्यतन स्थिति, वेब पीएन की सुविधा दिलाने, जिलों में भू-लगान के निर्धारण और ऑनलाइन भुगतान करने, भूमि सीमांकन के लंबित मामलों की स्थिति समेत अन्य विभागीय कार्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सभी कर्मी ससमय सभी कार्यों के निष्पादन के लिए समन्वय स्थापित कर काम करें।

1996 से बंद पड़ी बेकन फैक्ट्री का कृषि मंत्री ने किया निरीक्षण

- शेड की गुणवत्ता देख हुईं नाराज
- मात्र 25 हजार रुपये के लिए बंद हो गई थी फैक्ट्री, सरकार शुरू करने की तैयारी में
- सूकर पालन करने वालों को मिलेगी राहत

PHOTON NEWS RANCHI : रांची के कांके में स्थित 1996 से बंद पड़ी बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने की पहल अब जोर पकड़ने लगी है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मंगलवार को इस फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फैक्ट्री को फिर से चालू करने के संबंध में सकारात्मक चर्चा हुई है। एक समय में यह फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी बेकन फैक्ट्री मानी जाती थी। लेकिन महज 25 हजार रुपये के कारण यह बंद हो गई थी। इस फैक्ट्री में सूकर मांस के विभिन्न रेडी-टू-इट व्यंजन तैयार होते थे और इसे रैनबेक ब्रांड के नाम से बेचा जाता था। मंत्री ने बताया कि फैक्ट्री के फिर से चालू होने से सूकर पालन से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे हर चीज को छोड़ना सही नहीं है। हमें अपनी इच्छाशक्ति से काम करते हुए सकारात्मक परिणाम निकालने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पशु धन योजना के तहत वितरण किए जा रहे पशुओं के बारे में भी बात की और सुझाव दिया कि अगर विभाग के फॉर्म सेंटर में तैयार पशु उपलब्ध हो तो यह अधिक लाभकारी होगा।

पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि

सबका साथ, सबका विकास था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना : मुंडा

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को रांची में भाजपा रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर दीनदयाल नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पंडित दीनदयाल के विचारों और उनके अंत्योदय के सिद्धांत को याद करते हुए कहा कि उनका सपना सबका साथ, सबका विकास को साकार करने का संकल्प हम सभी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भाजपा प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. रविंद्र राय ने कहा कि पंडित

दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम होना चाहिए। उनका उद्देश्य जनकल्याण और राष्ट्र निर्माण था। रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने पंडित जी के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि दीनदयाल जी जातिवाद और भेदभाव के विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज में समान अधिकार और सम्मान की बात की थी। कार्यक्रम में विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरी लाल, सुबोध सिंह गुड्डू, शोभा यादव,बलराम सिंह, जितेंद्र वर्मा, राजू सिंह, बसंत दास, रौशनी खलको, अनिता वर्मा, पायल सोनी, जितेंद्र सिंह पटेल, विकास रवि, रवि मुंडा, रणधीर सिंह, इंद्रजीत यादव एवं रांची महानगर के सम्मानित कार्यकर्ता मौजूद थे।

शहर की साफ-सफाई देखने के लिए सड़क पर उतरे नगर प्रशासक

अतिक्रमण करने वालों को संदीप सिंह ने दी चेतावनी, कहा- नहीं हटाने पर होगी कार्रवाई

PHOTON NEWS RANCHI : रांची नगर निगम क्षेत्र के मुख्य मार्ग, कनेक्टिंग पथ को स्वच्छ, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए निगम लगातार प्रयास कर रहा है। इस दिशा में निगम की टीम द्वारा लगातार स्वच्छता और अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे में शहर की सफाई का हाल जानने के लिए नगर प्रशासक संदीप सिंह खुद राजधानी की सड़कों पर निकल पड़े। इस दौरान उनके साथ स्वच्छता शाखा के पदाधिकारी भी थे। उन्होंने शहर के प्रमुख मार्ग कचहरी चौक, सर्कुलर रोड, लालपुर, डंगराटोली, कांटाटोली, सिरमटोली चौक, सुजाता होते हुए मेन रोड की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रशासक ने सफाई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए पदाधिकारियों को कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। साथ ही कहा कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाया जाए, ताकि शहर की सफाई दुरुस्त रहे। निरीक्षण के दौरान उप प्रशासक रविंद्र कुमार, सहायक प्रशासक निहारिका तिर्की, नगर प्रबंधक और संबंधित वार्ड के सुपरवाइजर उपस्थित थे।

दो दिनों के झारखंड दौरे पर रांची आ रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

सहायक प्रशासक रखेंगे नजर

प्रशासक ने कहा कि 14-15 फरवरी को राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर एयरपोर्ट से लेकर सभी मुख्य मार्गों पर सफाई कार्यों को 24 घंटे मुस्तैदी से किया जाए। इसमें झाड़ू लगाना, डंप कूड़े का उठाव और जाम नालियों की सफाई शामिल हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सफाई व्यवस्था का निरीक्षण नगर प्रबंधक और सहायक प्रशासक की गठित टीम द्वारा फील्ड विजिट करते हुए किया जाए।

नहीं चुकाई गई 63 लाख की फाइन, अब चल रही वसूली की तैयारी

धरा का धरा रह गया रांची नगर निगम का चालान

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने और अतिक्रमण करने पर रांची नगर निगम लोगों से फाइन वसूलता है। इसके लिए लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन, राजधानी में 500 से अधिक लोगों ने रांची नगर निगम द्वारा लगाई गई फाइन को नहीं भरा है। इससे नगर निगम को 63 लाख नहीं मिले हैं। इसके लिए रांची नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को रसीद भी थमाई थी। इतना ही नहीं, उन्हें एक तय समय के अंदर फाइन जमा कराने का निर्देश भी दिया था। इसके बावजूद लोगों ने गंभीरता नहीं दिखाई। अब नगर निगम उनसे पेनाल्टी के साथ फाइन वसूलने की तैयारी में है। इतना ही नहीं इसे लेकर नगर निगम फाइन नहीं भरने वालों को नोटिस जारी करेगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

500 से अधिक लोगों का निगम की एनफोर्समेंट टीम ने पहले ही काटा था चालान

तीन नोटिस के बाद भी फाइन नहीं भरने वालों पर अब की जाएगी कड़ी कार्रवाई

प्रतिष्ठानों की लिस्ट तैयार

रांची नगर निगम बकाएदारों से फाइन वसूलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पहले रांची नगर निगम नोटिस जारी करेगा। इसके बाद दूसरा और फिर तीसरा रिमाइंडर नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी नियमों की अनदेखी करने वालों के द्वारा अगर फाइन नहीं भरा जाता है तो संबंधित प्रतिष्ठानों को नियमों के तहत सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसकी पूरी लिस्ट रांची नगर निगम ने तैयार कर ली है। दुकानदारों और भवन मालिकों को अब नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

टीम में घट गए थे अफसर

नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम शहर में अतिक्रमण करने या नियमों का उल्लंघन करने पर फाइन काटती है। ऐसे में टीम ने कुछ महीने पहले अतिक्रमण करने, नियमों का उल्लंघन करने पर राजधानी में 500 से अधिक लोगों पर फाइन लगाई थी। इसकी रसीद भी लोगों को थमाई गई थी। लेकिन, इस बीच टीम में से अफसरों को हटा दिया गया। इसका कारण बताया गया कि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में मात्र 17 अफसर ही टीम में बच गए थे। इस कारण एनफोर्समेंट टीम न तो ठीक से अभियान चला पा रही थी और न ही फाइन की वसूली हो पा रही थी। अब फिर से 28 अफसरों की टीम में वापसी हो गई है। 45 लोगों की पूरी टीम बन गई है। टीम को अब फाइन वसूलने के साथ एनक्रोचमेंट ड्राइव भी चलाने का निर्देश दिया गया है।

रात में भी अभियान चला रही टीम

45 लोगों की टीम को चार जोन में बांटा गया है। इसके अलावा रात के लिए भी एक टीम बनाई गई है। अब ये टीम रात में शहर में जांच अभियान चला रही है। रोड पर बिल्डिंग मैटेरियल, अतिक्रमण और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर फाइन लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि राजधानी को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। बता दें कि रांची नगर निगम में कुल 53 वार्ड हैं। सवा दो लाख से अधिक हाउस होल्डर रजिस्टर्ड हैं।

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मिला झारखंड जनाधिकार महासभा का प्रतिनिधिमंडल

RANCHI : मंगलवार को झारखंड जनाधिकार महासभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात की। संगठन के सदस्यों ने पेसा के सभी जरूरी नियमों के अनुरूप झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को संशोधित करने की मांग की और इससे संबंधित संलग्न पत्र सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी शामिल थीं। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी के सुझावों को लेते हुए इस प्रक्रिया को मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्री के समक्ष अपनी बात रखते हुए झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पेसा के मूल कानून के मुताबिक अनुसूचित क्षेत्र में त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था के प्रावधानों की बात कही गई है। लेकिन, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत इसमें पेसा के अनुरूप ग्राम सभा और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था संबंधित अनेक प्रावधान नहीं हैं।

जांच के लिए दाखिल रिट पर हियरिंग स्थगित

ईडी के नाम पर वसूली केस में 6 मार्च को होगी सुनवाई

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के अधिकारियों को मैनेज करने के कथित आरोपों की जांच के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई स्थगित हो गई। अब हाईकोर्ट इस मामले पर 6 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध पीडक कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इससे पहले राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था। जिसमें उसने रांची पुलिस को पंडरा ओपी,

सुखदेव नगर थाना, जगन्नाथपुर थाना, अनगडा थाना, मोरहाबादी टीओपी, नामकुम थाना और देवघर थाना के 4 अक्टूबर 2024 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 तक की सीसीटीवी को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। दरअसल रांची के पंडरा ओपी में पिछले वर्ष कांड संख्या 507/2024 और 508/2024 दर्ज की गयी थी। पहली प्राथमिकी में अधिवक्ता सुजीत कुमार ने रंगदारी की मांग कर अपहरण करने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

समाचार सार

अफीम खेती के दुष्प्रभाव बताएगा जागरूकता वाहन

CHAIBASA : जिला समाहरणालय से मंगलवार को डीआईजी मनोज रतन चौथे ने जागरूकता वाहन रवाना किया, जो जिले भर में घूम-घूम कर अवैध अफीम की खेती के दुष्प्रभाव बताएगा। इस मौके पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, और डालसा के सचिव ने भी एलईडी जागरुकता वाहन को झंडी दिखाई।

भाजपा ने मनाई पं. दीनदयाल की पुण्यतिथि

JAMSHEDPUR : भाजपा, जमशेदपुर महानगर ने एकात्म मानववाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की 57वीं पुण्यतिथि को 'समर्पण दिवस' के रूप में मनाया। मंगलवार को साकची स्थित जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के वरीय नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पं. दीनदयाल के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे एवं भारत माता की जय से कार्यालय परिसर गुंजायमान रखा। इस अवसर पर वक्ताओं ने पंडित जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। भाजपा महानगर अंतर्गत सभी 28 मंडलों में पं. दीनदयाल को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष रामबाबू तिवारी, दिनेश कुमार, डॉ. राजीव कुमार, कुलवंत सिंह बंटी, रमेश हांसदा, बबुआ सिंह, राजीव सिंह, संजीव कुमार, बिनोद सिंह, उज्ज्वल सिंह, अप्पा राव, धर्मेंद्र प्रसाद, नीतीश कुशवाहा, सागर राय, रमेश बास्के, बिनोद राय, पवन सिंह, अमित मिश्रा, कमलेश सिंह, रमेश नाग, अजय सिंह, रॉकी सिंह, राहुल तिवारी, प्रकाश दुबे, दीपक तिवारी समेत कई अन्य कार्यकर्तागण मौजूद रहे।

बीआईएस ने बंच्ड केबल पर किया मंथन

JAMSHDPUR : भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) कार्यालय में मंगलवार को कॉन्फ्रेंस हॉल में मानक मंथन का आयोजन किया गया। इसमें 11,000 वोल्ट तक वर्किंग वोल्टेज के लिए एरियल बंच्ड केबल के लिए भारतीय मानक के मसौदे पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक की अध्यक्षता बीआईएस जमशेदपुर के निदेशक और प्रमुख कुणाल कुमार ने की। इस दौरान सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया कि भारतीय मानक मजबूत बना रहे और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप हो। सत्र के दौरान, भारतीय मानक का विस्तृत अध्ययन किया गया और प्रतिभागियों ने मसौदा मानक के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और सुझाव दिए। मानक मंथन उद्योग के हितधारकों के लिए चर्चा में शामिल होने और मसौदा मानकों पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। यह विचार-मंथन सत्रों को बढ़ावा देता है, जहां मानक निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उद्योग विशेषज्ञों सहित हितधारकों के इनपुट को ध्यान में रखा जाता है। कार्यक्रम में विभिन्न केबल निर्माण इकाइयों, लाइसेंसधारी और गैर-लाइसेंसधारी दोनों के 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कल उलियान में लगेगी रेडियो प्रदर्शनी

JAMSHDPUR : विश्व रेडियो दिवस पर 13 फरवरी को उलियान, कदमा के निर्मल महतो रोड पर रेडियो प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसे लेकर गाइड इंटरनेशनल रेडियो लिसेनर्स क्लब के संस्थापक चिन्मय महतो ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान सुबह 11 बजे से रेडियो पर परिचर्चा भी होगी। प्रदर्शनी में पुराने से लेकर अब तक के सैकड़ों रेडियो, ट्रांजिस्टर, रिकॉर्ड प्लेयर आदि प्रदर्शित किए जाएंगे।

रेल जीएम ने किया बंडामुंडा का दौरा

CHAKRADHARPUR : दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा मंगलवार को बंडामुंडा पहुंचे। महाप्रबंधक अपने विशेष सेलून से सुबह करीब छह बजे राउरकेला रेलवे स्टेशन आए। इसके बाद सुबह करीब 9 बजे बंडामुंडा रवाना हो गए। जीएम ने सबसे पहले बंडामुंडा ए-केबिन का दौरा किया, जहां उन्होंने तमाम विभागीय अधिकारियों से रेल यार्ड से जुड़े तमाम जानकारी ली। उन्होंने ए-केबिन से बंडामुंडा रेल यार्ड तक के बीच रेल ट्रैफिक को जाम मुक्त करने के लिए कई दिशा-निर्देश दिए। यहां से वे डिपार्चर यार्ड गए, जहां उन्होंने रेल यार्ड समेत रेलवे ट्रैक,पाथ वे का जांच की। उन्होंने कैरेज एंड वैगन विभाग का भी निरीक्षण किया। इस दौरान चक्रधरपुर के डीआरएम तरुण हुरिया समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

गरीब कैदियों को मिलेगी वित्तीय सहायता : डीसी

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के समाहरणालय में मंगलवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई। इसमें गरीब बंदियों को वित्तीय सहायता पहुंचाने की योजना पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कारा अधीक्षक को निर्देश दिया कि जुर्माना राशि देने में असमर्थ गरीब बंदियों को चिह्नित कर प्रस्ताव इम्पावर्ड कमेटी को उपलब्ध कराएं।

बिष्टुपुर बाजार में बना दी गई अवैध दुकान, एसडीओ ने दिए जांच के आदेश

दुकान बनवाने वाले का नाम नहीं बता रहे दुकानदार, जेएनएसी करेगी इन्क्वायरी

PHOTON NEWS JSR: बिष्टुपुर बाजार में सरकारी जमीन पर रातों-रात दुकान बना दी गई है। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद एसडीओ शताब्दी मजूमदार मामले की जांच के लिए मौके पर गई थीं। मगर, बाजार में किसी ने उन्हें यह जानकारी नहीं दी कि यह दुकान किसने बनवाई है। एसडीओ ने कई दुकानदारों से पूछताछ की, मगर यह अवैध दुकान बनवाने वाले के खिलाफ कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद एसडीओ ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) को मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

अब इस मामले की जांच जेएनएसी करेगी। जुस्को से भी जानकारी ली जा रही है कि उसने किसी को यह जगह आवंटित तो नहीं की है।

डस्टबिन की जगह खड़ा दुकान का ढांचा ● फोटोन न्यूज

कचरा फेंकते थे लोग

दुकानदारों का कहना है कि यहां जिसने दुकान बनवाई है, वह जुगसलाई का रहने वाला है। दुकानदारों का कहना है कि जब दुकान बन रही थी तो इसकी शिकायत बिष्टुपुर थाना और जेएनएसी से भी की गई थी। मगर, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके चलते कूड़ा फेंकने वाले स्थल पर टिन की यह बड़ी गुमटी टाइप बना कर दुकान रख दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि यहां डस्टबिन रखी होती थी। अब डस्टबिन हटा दी गई है। अब उनके सामने कचरा फेंकने की दिक्कत हो रही है।

बिना आवंटन दुकान बनाना अवैध

शहर की बाजारें अब सैरात की जमीन में हैं। यहां बिना आवंटन कराए दुकान बनाना अवैध है। बिष्टुपुर बाजार में जितनी भी दुकानें बनी हैं सब को जगह आवंटित की गई है। इसी के बाद दुकानें बनी हैं। बिष्टुपुर में अवैध दुकान बनाने का यह पहला मामला नहीं है। पहले भी यहां अतिक्रमण कर दुकानें बनाई गई हैं। इसके चलते जेएनएसी तक को यहां कार्रवाई करनी पड़ी है।

एनएच पर सड़क दुर्घटना में मजदूर की मौत

JAMSHEDPUR : सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर निवासी लक्ष्मण घटवाल की सोमवार रात को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। यह हादसा चांडिल थाना क्षेत्र के चिलगू स्थित नेशनल हाईवे-33 पर हुआ था। यहां एक ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी। 48 वर्षीय लक्ष्मण मूल रूप से पुरुलिया जिले के नवाडीह का निवासी था। वह आदित्यपुर में रहकर मजदूरी करता था। में था। सोमवार को वह बाइक से अपने गांव नवाडीह जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लक्ष्मण घटवाल को तुरंत एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। लक्ष्मण घटवाल के परिवार में उसकी पत्नी वंदना घटवाल, दो बेटे और दो बेटियां हैं। परिवार पहले ही आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। घटना के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर की तलाश शुरू कर दी है।

कारोबारी बाबू दास पर फायरिंग मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

ADITYAPUR : सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर में 7 फरवरी को कारोबारी बाबू दास पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने दो आरोपियों अजय बहादुर उर्फ अज्जू थापा और आनंद दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों के पास से कांड में प्रयुक्त देसी पिस्तौल भी बरामद किया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने बताया कि घटना 7 फरवरी की रात की है, जब अजय बहादुर उर्फ अज्जू थापा और आनंद दुबे ने आदित्यपुर के सपड़ा स्थित देसी ढाबा में घुसकर बाबू दास पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में बाबू दास को 7 गोलियां लगी थीं। बाबू दास का इलाज टीएमएच में चल रहा है। हमलावर घटना के बाद एक स्विफ्ट डिजायर कार से भाग गए थे, लेकिन चिलगू के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। मामले में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उल्लेखनीय है कि अज्जू थापा कुख्यात अपराधी संतोष थापा का रिश्तेदार है और पुलिस अब संतोष थापा और देवशीष दास की तलाश कर रही है, जो घटना के बाद से फरार हैं।

चाकुलिया में प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों ने कर दिया सड़क जाम, दी चेतावनी

PHOTON NEWS CHAKULIA : पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया नगर पंचायत की मुस्लिम बस्ती के लोगों ने मंगलवार को प्रदूषण से निजात दिलाने की मांग को लेकर चाकुलिया-धालभूमगढ़ मुख्य सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि मशरूम फैक्ट्री और राइस मिल से निकलने वाला प्रदूषण उनकी जिंदगी में भारी परेशानी का कारण बन गया है। तिरपाल बिछाकर सड़क पर बैठने वाले इन ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि चाकुलिया हाटचाली रोड पर स्थित दो फैक्ट्रियों से फैलते प्रदूषण के कारण उनके जीवन में कई समस्याएं आ रही हैं। मशरूम फैक्ट्री से उठने वाली दुर्गंध के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा, राइस मिल से भी प्रदूषण फैल रहा है, जिससे आसपास के इलाके के लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। सड़क जाम की सूचना मिलने पर सीओ नवीन पूर्ति जाम स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। सीओ ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उन्होंने सात फरवरी को इस मामले में आवेदन प्राप्त किया है और जांच प्रक्रिया में 10-15 दिन का समय लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 26 फरवरी तक वरीय अधिकारियों को जांच रिपोर्ट भेज दी जाएगी, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मो साजिद ने कहा कि अगर फरवरी माह तक समस्या का समाधान नहीं होता है, तो वे एक मार्च को फिर से सड़क जाम करेंगे।

सड़क जाम करते लोग ● फोटोन न्यूज

चाउमिन ठेला संचालक को मारा उस्तरा, घायल

JAMSHEDPUR : गोलमुरी थाना अंतर्गत नामदा बस्ती में मंगलवार शाम उस्तरेबाजी की घटना से सनसनी फैल गई। इस घटना में रौशन कुमार नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार रोशन नामदा बस्ती में ही चाउमिन का ठेला लगाता है। आए दिन आसपास के दबंग युवकों द्वारा उससे रंगदारी मांगी जाती है। कभी-कभी उनके दबाव में आकर पैसे दे देता था। मंगलवार को भी उससे पैसे की मांग की गई। नहीं देने पर पास के ही सैलून से उस्तरा निकालकर अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया है।

हथियार व गांजा के साथ टेल्को के थीम पार्क से एक गिरफ्तार

पत्रकारों को मामले की जानकारी देते एसएसपी किशोर कौशल ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : टेल्को थाना क्षेत्र के थीम पार्क के पास से पुलिस ने एक युवक के पास से एक किलो 865 ग्राम गांजा और देसी सिक्सर बरामद किया है। दो कारतूस भी बरामद किए हैं। उसके पास से गांजा बरामद हुआ है। उसका नाम करमू मानकी उर्फ करण माझी है। वह घाटशिला थाना क्षेत्र के घाटीडूबा गांव के बक्सोल टोला का रहने वाला है। मंगलवार को एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टेल्को थाना की पुलिस सोमवार की रात गश्त पर निकली थी। तभी एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसे खदेड़ कर पकड़ा। उसकी तलाशी ली गई तो उसकी कमर से देसी सिक्सर और पैंट की जेब से दो कारतूस बरामद हुए। उसके बैग को देखा गया तो दो प्लास्टिक में एक किलो 865 ग्राम गांजा था।

ग्रामीण बैंक के पास लगी आग, बाइक जलकर राख

आग बुझाते दमकलकर्मी ● फोटोन न्यूज

ADITYAPUR : आदित्यपुर : आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत इच्छापुर मैदान के पास स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के पास सूखे पत्तों में आग लगने के चलते विकराल आग ने झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के भवन को भी अपनी चपेट में ले लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैंक के पास खाली भूखंड में सूखे पत्तों को किसी ने आग लगा दी थी, जिसने विकराल रूप धारण कर लिया। वहां खड़ी एक बाइक में भी आग लग गई और बाइक धू-धूकर जलने लगी। इसके बाद बैंक की बिल्डिंग में आग घुस गई। घटना के बाद अफरातफरी मच गई। सूचना पर झारखंड अग्निशमन दल का दमकल पहुंचा और उसने आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि बाइक और पास में रखे पानी के प्लास्टिक पाइपों के चलते आग ने भयावह रूप ले लिया।

घाटशिला में 986 छात्रों ने दी मैट्रिक परीक्षा, 7 अनुपस्थित

GHATSILA : झारखंड अधिविध परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा मंगलवार को पहले दिन शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त रही। घाटशिला अनुमंडल के 26 परीक्षा केंद्रों में 986 छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि 7 अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण अनुमंडल पदाधिकारी सुनील चंद्र व एसडीपीओ अजीत कुमार कुजूर ने किया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने बताया कि किसी भी परीक्षार्थी को कदाचार के आरोप में निष्कासित नहीं किया गया है। इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन अनुमंडल के 12 परीक्षा केंद्रों में 1103 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। इसमें 6 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहने के कारण 1097 छात्र शामिल हुए।

जयंती पर याद किए गए वीर शहीद बाबा तिलका माझी

PHOTON NEWS JSR : भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने वाले वीर शहीद बाबा तिलका माझी की 275वीं जयंती मंगलवार को बाबा तिलका माझी (डिमना) चौक के पास मनाई गई। सर्वप्रथम बाबा की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उनके योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर जनसभा भी हुई, जिसमें बाबा तिलका मांझी स्मारक समिति के सचिव मदन मोहन सोरेन, झामुमो के मानगो प्रखंड अध्यक्ष फतेहचांद टुडू, माझी बाबा रमेश मुर्मू व प्रह्लाद लोहरा ने अपने विचार साझा किए। मदन मोहन ने कहा कि यहां बाबा की आदमकद मूर्ति स्थापित की जाएगी। फतेहचंद टुडू ने कहा कि बाबा को अब तक इतिहास में उचित जगह नहीं मिला है। सभा का संचालन दीपक रंजीत ने किया, जबकि इस मौके पर राखाल सोरेन, छोटू सोरेन, सोनू सिंह, परमेश्वर दास, सुनील रजक, रंजीत दे, सनातन हांसदा, हैप्पी तंतुबाई, धानु टुडू,विकास गोप, विजय लेयांगी,चन्द्राई,सोरेन आदि भी उपस्थित थे।

डिमना चौक पर श्रद्धांजलि देते लोग ● फोटोन न्यूज

अंग्रेजों से लड़ने वाले पहले क्रांतिकारी थे बाबा : मंत्री

GHATSILA : पूर्वी सिंहभूम मांझी परगना महाल ने मंगलवार की दोपहर सिदो-कान्हू हुल्गारिया मैदान, कीतादीह, घाटशिला में बाबा तिलका मांझी की जयंती मनाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन उपस्थित थे। मंत्री ने प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। वन अधिकार कानून एवं जल, जंगल, जमीन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बाबा तिलका ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आदिवासी संघर्ष का नेतृत्व किया था। वे पहले ऐसे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1784 में अंग्रेजों से लोहा लिया था। उनका बलिदान देश के लिए प्रेरणास्रोत है। इस मौके पर माहाल के बहादुर सोरेन सहित पार्टी के कई वरीय नेता शामिल थे।

जब एलएंडटी लिख कर देगा, तभी शुरू हो सकेगा स्थानांतरण का काम

पानी नहीं उगल रही नए अस्पताल की बोरिंग, शिफ्टिंग रुकी

- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीब पांच माह पहले किया था उद्घाटन, नहीं शुरू हो सका अस्पताल

MUJTABA RIZVI @ JSR : एमजीएम अस्पताल की डिमना स्थित नए भवन में शिफ्टिंग का काम एक बार फिर लटक गया है। कार्यकारी एजेंसी एलएंडटी ने स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त पानी की आपूर्ति की गलत सूचना दे दी थी। इस वजह से एमजीएम अस्पताल की शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया था। मगर, आई एंड ईएनटी विभाग के ओपीडी की शिफ्टिंग के बाद पता चला कि अस्पताल में पर्याप्त पानी है ही नहीं।

यहां जो नई पांच बोरिंग हुई है वह अभी पानी नहीं दे पा रही है। इस वजह से शिफ्टिंग का काम बंद कर दिया गया है। अब निर्देश दिया है कि जब अस्पताल में पानी की व्यवस्था हो जाए तो ठेका कंपनी एलएंडटी, एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक को इस संबंध में लिख कर दे दे। इसी के बाद अस्पताल की शिफ्टिंग की जाएगी। नए अस्पताल में प्रतिदिन तकरीबन 3 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी।

कई विभागों को किया जाना है शिफ्ट

डिमना स्थित नए अस्पताल में पूरा एमजीएम अस्पताल शिफ्ट किया जाना है। इसमें इमरजेंसी के अलावा, बर्न वार्ड, मेडिसिन, गायनी विभाग आदि को शिफ्ट किया जाना है। यहां हार्ट, कैंसर व न्यूरो आदि विभाग भी संचालित किए जाने हैं।

पानी को लेकर एलएंडटी व पीएचईडी आमने-सामने

अस्पताल में पानी की व्यवस्था को लेकर कार्यकारी संस्था एलएंडटी और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आमने-सामने हैं। एलएंडटी के अधिकारी का कहना है कि उसका काम अस्पताल की इमारत का निर्माण करना था। यहां पानी की व्यवस्था करना पीएचईडी यानी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का काम है। एलएंडटी के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सरकार के कहने पर अपनी तरफ से यहां पांच बोरिंग कर दी है। अब बोरिंग से पानी निकालना और पाइपलाइन से इमारत की पाइप को जोड़ना पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का काम है। मगर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कहना है कि यहां पानी की व्यवस्था करना भी एलएंडटी का ही काम है। बताया जा रहा है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की लापरवाही से अस्पताल की शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है।

शहर के इमरान वकील ने जेईई मेन में हासिल किया 99.80 पर्सेंटाइल

JAMSHEDPUR : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने मंगलवार को जेईई मेन 2025 सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें जुस्को स्कूल साउथ पार्क के 12वीं और नारायणा कोचिंग सेंटर साकची के छात्र इमरान वकील ने 99.80 पर्सेंटाइल लाकर अपने स्कूल और संस्थान का नाम रोशन किया है। इमरान वकील के पिता मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं। उनकी मां गृहिणी हैं। इमरान वकील ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता व बहन, स्कूल की प्रिंसिपल, सभी शिक्षकों एवं नारायणा कोचिंग सेंटर के सभी फैकल्टी मेंबर को दिया है। अपनी तैयारी के बारे में इमरान ने कहा कि रेगुलर क्लास और रणनीति के साथ प्रतिदिन 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस किया। वहीं पिछले दो महीने से लगातार मॉक टेस्ट आत्मविश्वास को बढ़ाया है। इमरान का अगला लक्ष्य जेईई एडवांस्ड में बेहतर स्कोर कर टॉप 5 आईआईटी कॉलेज से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) में बीटेक करना है।

घाटशिला अनुमंडल में कम हुई महिलाओं की आबादी

अनुमंडल अस्पताल में लिंगानुपात पर चर्चा करते पदाधिकारी व अन्य

GHATSILA : अनुमंडल अस्पताल में मंगलवार को लिंगानुपात को लेकर बैठक हुई, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि व पंचायतस्तरीय स्वास्थ्य कर्मी शामिल थे। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आरएन सोरेन ने बताया कि झारखंड सहित घाटशिला अनुमंडल में महिलाओं की आबादी पुरुषों से कम है। इसके लिए पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसकी मुख्य वजह भ्रूण हत्या है। ऐसा करना कानूनी अपराध है। ऐसा न करें, वर्तमान समय में लड़का तथा लड़की में कोई फर्क नहीं है। आज लड़कियां भी पुरुषों से कम नहीं हैं। सभी क्षेत्र में काम कर रही है। बैठक में पावड़ा पंचायत की मुखिया पार्वती मुर्मू, धरमबाहाल पंचायत के मुखिया बनाओ मुर्मू, बीपीएम मयंक कुमार सहित अन्य शामिल थे।

कॅरियर गाइडेंस देश व दुनिया में आज हेल्थ सेक्टर का जितना विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आगे चलकर काबिल फिजियोथैरेपी की मांग और बढ़ेगी। फिजियोथैरेपी विज्ञान की ऐसी विधा है जिसके अंतर्गत शारीरिक व्यायाम के जरिए व्यक्ति के रोगों व व्याधियों का उपचार किया जाता है।

फिजियोथैरेपी
वक्त की मांग

फिजियोथैरेपिस्ट का काम रोगियों में किसी बीमारी, चोट, अक्षमता या बढ़ती उम्र की वजह से उपजी शारीरिक व्याधियों का उपचार करना है। आज लोग बीमारी के उपचार के लिए समग्र नजरिया अपनाने लगे हैं। इसकी वजह से दुनिया भर में फिजियोथैरेपिस्ट्स की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है।

काम का दायरा

फिजियोथैरेपिस्ट्स अस्पतालों, विकलांगों की लिए बने पुनर्वास केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए बने स्कूलों, स्वास्थ्य संगठनों के अलावा डिफेंस मेडिकल प्रतिष्ठानों और स्पोर्ट्स क्लबों में भी अपनी सेवाएं देते है। इंजुरी व फ्रैक्चर्स, जोड़ों के दर्द, खिंचाव, मोच, स्ट्रोक्स के उपचार में काबिल फिजियोथैरेपिस्ट की सेवाएं कारगर साबित होती हैं।

बढ़ती मांग

आज जिस तरह के अत्याधुनिक अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र व क्लीनिक्स खुल रहे हैं और हेल्थ सेक्टर का विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि फिजियोथैरेपिस्ट की मांग आगे चलकर और बढ़ेगा। कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खुद को फिट रखने व फिटनेस संबंधी सुझाव लेने के लिए फुलटाइम पर्सनल फिजियोथैरेपिस्ट्स की सेवाएं लेते हैं। विदेशों में और खासकर अमेरिका कनाडा व आस्ट्रेलिया जैसे देशों में पर्सनल फिजियोथैरेपिस्ट्स की जबदस्त मांग है।

योग्यता

फिजियोथैरेपी में कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए अभ्यर्थी को फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के साथ 12वीं या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अस्पताल व क्लीनिक्स अमूमन ऐसे लोगों को रोजगार देते हैं, जिनके पास फिजियोथैरेपी में बैचलर डिग्री (बीपीटी) हो। बीपीटी करने के बाद छात्र यदि चाहें तो अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। फिजियोथैरेपी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि छह महीने से लेकर दो साल तक हो सकती है। डिग्री स्तर अवधि

तीन से चार साल तक होती है। प्रतिष्ठित संस्थान कॉमन टेस्ट सीईटी के जरिए बीपीटी में छात्रों की दाखिला देते है।

व्यक्तिगत योग्यता

फिजियोथैरेपिस्ट्स बनने के चाह रखने वाले अभ्यर्थियों में लंबे समय तक खड़े रहकर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। काबिल फिजियोथैरेपिस्ट वहीं है जो मरीज की जरूरत को अच्छी तरह समझ सके, उसके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए। सफल फिजियोथैरेपिस्ट बनने के लिए व्यक्ति में इन खूबियों के अलावा मानवीय संरचना का सम्पूर्ण ज्ञान होना भी अति आवश्यक है।

पारिश्रमिक

इस क्षेत्र से जुड़े कोई फ्रेश ग्रेजुएट किसी हॉस्पिटल या क्लीनिक में ट्रेनी फिजियोथैरपिस्ट के तौर पर 8,000 से 12,000 रूपए वेतन पाने की उम्मीद कर सकता है। हालांकि प्रतिष्ठित अस्पतालों में आपको और भी अच्छा वेतन मिल सकता है। अनुभव हासिल करने के बाद आपके वेतन में खासा इजाफा हो सकता है। अनुभवी फिजियोथैरपिस्ट चाहे तो निजी क्लीनिक खोल कमाई कर सकते हैं।

डायटीशियन
कॅरियर का बेहतर विकल्प

आहार जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। हम जो आहार लेते है उसका शरीर में पाचन किया जाता है। प्रकृति ने विभिन्न खाद्य-पदार्थों को भोजन का रूप दिया है जिसे कच्चा या पका कर हम उपयोग करते हैं ऐसे पदार्थ हमारे पाचक अंगों द्वारा पचा लिए जाते हैं, जिनसे ऊतकों का निर्माण एवं पोषण होता है। चलने, फिरने दौडने या अन्य शारीरिक कार्य करते रहने से शरीर के भीतर के ऊतक टूटते-फूटते एवं घिसते रहते है। भोजन द्वारा हमारे शरीर की संरचना तथा मरम्मत के लिए विभिन्न पोषक तत्व मिलते रहते हैं, जिनसे हमें शक्ति मिलती हैऔर हमारे शीरीरिक के विभिन्न अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहते हैं।सन्तुलित आहार और सही आहार हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है लिहाजा हमारी शारीरिक जरूरतों के अनुसार कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती हैं और कौन से खाद्य-पदार्थ से सेहत को नुकसान पंहुच सकते है, इसका जवाब डायटीशियन ही बता सकता है। जीवनशैली में आ रहे बदलावों और उसके दुष्णपरिणाम के चलते डायटीशियन एक बेहतर केरियर ऑप्शन के रूप में उभरा है। यह कोर्स अपनाकर आप अपना ही नहीं दूसरो की सेहत का भी ख्याल रख सकते है। एक डायटीशियन के रूप में आप नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग, बीमार, अभिनेताओं और खिलाडियों तक की डाइट का चार्ट बना सकते हैं। डायटीशियन लोगों को सलाह देता है, कि उसे स्वस्थ रहने के लिए किस तरह का भोजन करना चाहिए। डायटीशियन का कार्य जितना आसान दिखाई देता है वास्तव में वह उतना आसान नहीं हैं, क्योंकि रोगियों के लिए व्यक्तिगत आहार योजना बनाते हुए विभिन्न क्लीनिकल घटकों को ध्यान में रखना होता है। साथ ही रोगियों की जीवनशैली, खान-पान की आदतों पर भी विचार करना होता है ।पोरेट स्तर पर डायटीशियन की मांग बढ रही है और पांच सितारा होटलों में भी डायटीशियनों की सेवाएं ली जा रहीं हैं।

कराटे- दुश्मन को बिना किसी हथियार से हराने की तकनीक

कराटे निहत्थे लडने की एक मार्शल आर्ट है। यह एक प्रकार की कला है जिसमें हाथों तथा पैरों से वार करना तथा दुश्मन के वार को रोकना शामिल होता है। जिस व्यक्ति को कराटे की तकनीक पता हो वह अपने दुश्मन को बिना किसी हथियार के हरा सकता है। एक कराटे एक्सपर्ट सामने वाले को एक ही वार में चित्त भी कर सकता है। जहां जूडो आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है वहीं कराटे में दुश्मन पर वार भी किया जा सकता है। कराटे में शारीरिक संपर्क बहुत सीमित रखा जाता है और चोट से बचने के लिए वार को नियंत्रित रखा जाता है।

कराटे एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है 'खाली हाथ'। कराटे में शरीर की ताकत स्ट्राइकिंग प्वाइंट पर केंद्रित की जाती है। स्ट्राइकिंग प्वाइंट में हाथ, पैर का अलग भाग, एड़ी, बाजू, घुटना तथा कोहनी शामिल होते हैं। इन सभी भागों को कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस से कठोर बनाया जाता है। एक कराटे एक्सपर्ट कई इंच मोटी लकड़ी को अपने हाथ या पैर से तोड़ सकता है। सही टाइमिंग, कुशलता तथा जज्बा तो इसके लिए जरूरी है ही साथ ही जरूरी होती है शारीरिक कठोरता।

कराटे के खेल में वार को शरीर के संपर्क में आने से एक इंच पहले ही रोक लिया जाता है। कराटे में मैच सिर्फ 3 मिनट के होते हैं। एक खेल के तौर पर इसमें कुशलता का स्तर परखने के लिए दोनों में नकली लड़ाई और औपचारिक परीक्षण दोनों का आयोजन किया जाता है। यदि प्रतियोगी अच्छे से वार न कर पाए तो जज अपना फैसला मूवमैंट्स और डिफेंस तकनीक के आधार पर सुना सकते हैं।जजों द्वारा खिलाडियों के प्रदर्शन को वैसे ही रेटिंग दी जाती है, जैसे जिम्नास्टिक में होता है। कराटे एशिया में विकसित हुआ जिसे कई शताब्दियां लग गईं और 17वीं शताब्दी के दशक में जाकर यह कला के रूप में व्यवस्थित होने लगा। 1920 के दशक में यह जापान में बहुत प्रसिद्ध हुआ। आज पूरे विश्व में कई स्कूल कराटे की ट्रेनिंग देते हैं। 1970 में कराटे वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल की स्थापना की गई थी।

प्राचीन चीन से शुरू और जापान में प्रसिद्ध हुआ युद्ध कौशल (मार्शल आर्ट) कराटे आज पूरे विश्व में अत्यधिक लोकप्रिय है। कराटे खेल भी, कला भी कराटे निहत्थे लडने की एक मार्शल आर्ट है। यह एक प्रकार की कला है जिसमें हाथों तथा पैरों से वार करना तथा दुश्मन के वार को रोकना शामिल होता है।

जिस व्यक्ति को कराटे की तकनीक पता हो वह अपने दुश्मन को बिना किसी हथियार के हरा सकता है। एक कराटे एक्सपर्ट सामने वाले को एक ही वार में चित्त भी कर सकता है। जहां जूडो आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है वहीं कराटे में दुश्मन पर वार भी किया जा सकता है। कराटे में शारीरिक संपर्क बहुत सीमित रखा जाता है और चोट से बचने के लिए वार को नियंत्रित रखा जाता है। कराटे एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है 'खाली हाथ'। कराटे में शरीर की ताकत स्ट्राइकिंग प्वाइंट पर केंद्रित की जाती है। स्ट्राइकिंग प्वाइंट में हाथ, पैर का अलग भाग, एड़ी, बाजू, घुटना तथा कोहनी शामिल होते हैं।

स्वरोजगार

कागज़ उद्योग

देश में सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से कागज़ उद्योग देश का सबसे पुराना और अति महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग का अनुमानित आकार 25000 करोड़ रुंपये (5.95 बिलियन डॉलर) है। विश्व के कागज और कागज बोर्ड उत्पाद में इसका हिस्सा लगभग 1.6 प्रतिशत है। इस उद्योग से 1.20 लाख लागों को प्रत्यक्ष रूप से और 3.40 लाख लोगों को परेक्ष रूप से रोजगार मिला हे। अधिकतर पेपर मिल पिछले लम्बे अर्से से कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार वर्तमान समय में इनमें पुरानी से लेकर अति आधुनिक तकनीक वाली दोनों प्रकार की प्रौद्योगिकियाँ इस्तेमाल हो रही हैं।

पिछले पाँच वर्षों से कागज़ की खपत लगभग 6 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रही है। कागज़ उद्योग को कागज के उत्पादन की किस्म के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है; जैसे क्रीमवोव, मैपलिथो, कोपलर, कोटेड पेपर, इंडिस्ट्रयल पेपर और स्पेस्लिटी पेपर। इंडिस्ट्रयल पेपर अधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है, जो कि कुल खपत का लगभग 60 प्रतिशत है। अभी तक कागज उद्योग की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद में हुई वृद्धि के बराबर रही है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें औसतन 6-7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विश्व स्तर पर भारत में कागज का बाजार तेजी से बढ़ रहा है ओर यह उत्सावर्धक स्थिति को दर्शाता है। आर्थिक संवृद्धि के साथ कागज की खपत में भी अत्याधिक उछाल आने की संभावनाएँ हैं और यह 2015-16 तक 13.95 मिलियन टन तक पहुँच सकता है। भावी अनुमान यह हे कि कागज की खपत में सकल घरेलू उत्पाद के गुणांकों में वृद्धि होगी और इस प्रकार प्रति व्यक्ति 1 किलाग्राम खपत की वृद्धि से उसकी मांग में 1 मिलियन टन की वृद्धि होगी। उद्योग के अनुमानानुसार वर्ष 2012-13 तक कागज़ उत्पादन 8.4 प्रतिशत संचयी वार्षिक वृद्धि दर(सीएजीआर) से बढ़ा है, जबकि कागज की खपत 9 प्रतिशत संचयी वार्षिक वृद्धि दर(सीएजीआर) से बढ़ी है। कम खर्च व लागत में कागज उद्योग स्वरोजगार का बेहतर जरिया बन सकता है।

पैरा-मैडीकल कोर्सेज
में संवारें कॅरिअर

यदि आपकी बारहवीं परीक्षा की श्रेणी या अंक बहुत अच्छे नहीं हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी वजह यह है कि पैरा-मैडीकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए सी.पी.एम.टी. जैसी कठिन प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती। डॉक्टर जब मरीज को देख लेता है उसके बाद (कुछ मामलों में डाक्टर से पहले भी) सारा काम पैरा-मैडीकल के लोग ही संभालते हैं।

मरीज के खून, पेशाब, बलगम, वीर्य, टिश्यू आदि की जांच करनी हो, उसका एक्स-रे, ई.सी.जी., ई.ई.जी., एम.आर.आई., अल्ट्रा साऊंड, सी.टी. स्कैन, टी.एम.टी.,पी.एफ.टी., मैमोग्राफी आदि इंजैक्शन व दवा देनी हो तथा इसके अलावा भी अनेक ऐसे काम हैं जिसे पैरा-मैडीकल स्टाफ ही करता है। आप्रेशन करते समय एक डाक्टर को असिस्ट करने के लिए पैरा-मैडीकल स्टाफ होता है। मैडीकल फील्ड का लगभग सारा टैक्निकल स्टाफ पैरा-मैडीकल के अंतर्गत ही आता है।

इसके तहत प्रमुख कोर्स व संबंधित कार्य इस प्रकार हैं- मैडीकल लैब टैक्नोलॉजी , एक्स-रे टैक्नोलॉजी एंड रेडियोलॉजी/रेडियोग्राफी, ऑप्टोमीट्री या ऑप्थाल्मिक टैक्नोलॉजी, प्रॉस्थैटिक एवं ऑथोटिक इंजीनियरिंग, फिजियोथैरिपी एंड ऑकुपेशनल थैरेपी, डैंटिस्ट असिस्टैंट, स्पीच थैरेपी एंड ऑडियोलॉजी, क्लीनिकल चाइल्ड डिवैल्पमैंट, रिहैबिलिटेशन, मैडीकल ट्रांसक्रिप्शन, कम्युनिटी हैल्थ वर्कर्स कोर्स (मेल/फीमेल/मल्टीपर्पज़) ऑप्रेशनल थैरेपिस्ट असिस्टैंट/ ऑप्रेशन थिएटर असिस्टैंट व टैक्नीशियन कोर्स, कॉर्डियोलॉजी टैक्नीशियन कोर्स, सी.टी. स्कैन टैक्नीशियन कोर्स।

इनके साथ ही फॉर्मेसी, नर्सिंग एवं मिडवाइफरी तथा साइकोलॉजी की गणना भी पैरा-मैडीकल के अंतर्गत ही की जाती है। उपरोक्त सभी कोर्सों में सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, बी.एससी., एम.एससी., बैचलर या मास्टर डिग्री विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रदान की जाती है।

संस्थान

- पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीच्यूट ऑफ मैडीकल एजुकेशन एंड रिसर्च, सैक्टर-11,चंडीगढ़-1600012
- पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीच्यूट ऑफ मैडीकल साइंसेज, रोहतक-124001, हरियाणा।
- गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110007

राजनीति में युवाओं की भागीदारी की आवश्यकता

डॉ. सत्यवान सौरभ

अगर राजनीतिक दल युवाओं को राजनीति में शामिल करने के बारे में गंभीर हैं तो उन्हें कई तरह के कदम उठाने होंगे। पहला कदम सरकार द्वारा युवा मानदंड में बदलाव करना होगा। आज 34-35 वर्ष की आयु के लोगों को भी युवा माना जाता है। इस मानदंड को कम करने की आवश्यकता होगी। अपने संगठनात्मक ढांचे में, पार्टियों को युवाओं के लिए अधिक जगह बनाने की आवश्यकता होगी। आमतौर पर यह देखा गया है कि वयस्कता के करीब पहुंचने वाले नेता प्रमुख राजनीतिक दलों की युवा इकाइयों की बागडोर भी संभालते हैं। अपने छात्र संगठनों के लिए, राजनीतिक दलों को अधिकतम आयु प्रतिबंध भी स्थापित करने की आवश्यकता होगी। बेहतर होगा कि तीस वर्ष से अधिक आयु वालों को इससे बाहर रखा जाए।

राजनीति में युवाओं की भागीदारी न केवल एक लक्ष्य है, बल्कि यह समावेशी और प्रगतिशील लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक शर्त भी है। हालाँकि, बहुत कम युवा लोग राजनीति में भाग लेना जारी रखते हैं और उनकी आवाज को अक्सर स्थापित सत्ता संरचनाओं द्वारा दबा दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में बिना राजनीतिक अनुभव वाले एक लाख युवाओं को राजनीति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव विकेंद्रीकरण, समावेशिता और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञान के भंडार वाले अनुभवी नेताओं ने पारंपरिक रूप से भारतीय राजनीति में एक प्रमुख स्थान रखा है। वे अक्सर पारंपरिक ढाँचों के भीतर काम करते हैं, जो समकालीन मुद्दों को संभालने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उनका ज्ञान अमूल्य है। युवा नेता रचनात्मक समाधान, तकनीकी जानकारी और समकालीन शासन मॉडल का योगदान देकर गतिशील और डेटा-संचालित नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करते हैं।

एक स्थायी भविष्य की गारंटी के लिए, युवा नेता हरित कानूनों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। युवा-संचालित शासन में उद्यमिता, कौशल विकास और उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्राथमिकता देकर बेरोजगारी और अल्परोजगार को सम्बोधित करने की क्षमता है। युवाओं की भागीदारी के माध्यम से, भारत पारदर्शी और प्रभावी शासन प्राप्त करने के लिए ब्लॉकचेन, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बेहतर उपयोग कर सकता है। नागरिक भागीदारी के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, युवा लोग जवाबदेही में सुधार कर सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्जीवित कर सकते हैं और राजनीतिक भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। युवा जो राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय हैं, वे गारंटी देते हैं कि लोकतंत्र जीवित रहेगा और लोगों की मांगों के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

भारतीय राजनीति में पारंपरिक रूप से वंशवादी परिवारों का वर्चस्व रहा है, जिससे योग्यता-आधारित और जमीनी स्तर

के नेतृत्व के लिए बहुत कम जगह बची है। परिवार या पैसे के समर्थन के बिना, कई युवा उम्मीदवारों को राजनीतिक मंच प्राप्त करना मुश्किल लगता है। युवाओं में अक्सर राजनीतिक प्रशासन, नीति विश्लेषण और शासन में औपचारिक प्रशिक्षण की कमी होती है, भले ही उनमें उच्च स्तर का उत्साह हो। वर्तमान राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली सलाह की कमी युवा नेताओं को खुद की रक्षा करने के लिए मजबूर करती है। चूँकि कार्यालय चलाने के लिए महत्त्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए पहली पीढ़ी के राजनेताओं के लिए अधिक अनुभवी नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना चुनौतीपूर्ण होता है। राजनीति के अपराधीकरण के साथ-साथ पैसा और शारीरिक शक्ति अक्सर शिक्षित युवाओं को सार्वजनिक सेवा में करियर बनाने से रोकती है। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, कई राजनीतिक दल युवा नेताओं को निर्णय लेने की शक्ति दिए बिना शामिल करते हैं। इस सतही समावेशन के परिणामस्वरूप युवा राजनेताओं को शासन संरचनाओं में अधिक प्रभाव या परिवर्तन नहीं दिया जाता है।

युवा नेताओं द्वारा समान आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का समर्थन करने वाली नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेरोजगारी, जातिगत भेदभाव और लैंगिक समानता जैसे सामाजिक मुद्दों के लिए प्रगतिशील नीतियों और जमीनी स्तर पर भागीदारी की आवश्यकता होती है। संधारणीय कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा पहल और पर्यावरण के अनुकूल शहरी नियोजन सभी को युवा नेतृत्व द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया (स्वच्छ भारत) जैसी पहलों के लिए अधिक मजबूत युवा-संचालित कार्यान्वयन योजनाओं की आवश्यकता होती है। आने वाली पीढ़ी को उन्नत कौशल प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों का विस्तार करना आवश्यक है। दुनिया में भारत का नेतृत्व जैव प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में इसके निवेश पर बहुत अधिक निर्भर करेगा। लोकतंत्र के पतन को रोकने के लिए, युवा सक्रियता और नागरिक जुड़ाव को खुले, जवाबदेह और लोगों पर केंद्रित शासन की गारंटी देनी चाहिए। सहभागी शासन मॉडल और सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून को मजबूत करके लोकतंत्र को गहरा किया जा सकता है।

राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों का चयन उनकी दूरदर्शिता, योग्यता और नेतृत्व की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें पक्षपात पर योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। युवा नेताओं को उनके पारिवारिक सम्बंधों के बजाय उनके प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। मेंटरशिप कार्यक्रम स्थापित करके शासन, नीति निर्माण और विधायी प्रक्रियाओं में युवा राजनेताओं को औपचारिक रूप से सलाह दें। युवाओं को प्रशासन और कानून की व्यावहारिक समझ देने के लिए, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान 'राजनीतिक नेतृत्व और शासन' पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं। युवाओं को वित्तीय बाधाओं का सामना किए बिना कार्यालय चलाने में सक्षम बनाकर, चुनावों के लिए राज्य वित्त पोषण खेल के मैदान को समतल करने में मदद कर सकता है। भ्रष्टाचार से मुक्त और निष्पक्ष वातावरण स्थापित करने के लिए राजनीतिक अपराधीकरण के खिलाफ सख्त कानून लागू करना आवश्यक है। युवा राजनेताओं की क्षमता बढ़ाने और मतदाताओं को शिक्षित करने के कार्यक्रमों को नागरिक समाज संगठनों द्वारा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। शासन में सफल होने वाले युवाओं की कहानियों को अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मीडिया में दिखाया जाना चाहिए। युवाओं की भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए, राजनीतिक दलों और शासन संरचनाओं को युवा प्रतिनिधित्व के लिए न्यूनतम कोटा लागू करना चाहिए। सलाहकार परिषदों, युवा संसदों और मंत्रालय इंटर्नशिप जैसे नेतृत्व के अवसरों को बढ़ाया जाना चाहिए। आज लिए गए निर्णय आने वाले दशकों में भारत के मार्ग को प्रभावित करेंगे क्योंकि देश अपने इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। स्वामी विवेकानंद की सलाह 'उठो, जागो और आगे बढ़ो' आज भी लागू है।

संपादकीय

मणिपुर : इस्तीफे की घुट्टी

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह से भेंट करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिंह 2017 में पहली दफा मणिपुर के मुख्यमंत्री बने थे।उनके नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का राज्य में यह दूसरा कार्यकाल था, परंतु राज्य में हो रही हिंसा पर नियंत्रण रखने में नाकामयाब रहने के आरोप लग रहे थे। इसी दरम्यान सुप्रीम कोर्ट द्वारा जातीय हिंसा में सिंह की भूमिका को लेकर आरोप लगाने वाली लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रमाणिकता को लेकर सील बंद फोरेंसिक रिपोर्ट मांगने के बाद ताजा विवाद शुरू हो गया। इतना ही नहीं, विपक्षी दल कांग्रेस विधानसभा सत्र के दौरान सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार थी। बीते दो वर्षों से राज्य में मैतई समुदाय व कुकी जनजातियों के बीच चल रहे खूनी संघर्ष से निपटने में सिंह असफल ही नहीं रहे। बल्कि उन पर मैतई विद्रोहियों के समर्थन का भी आरोप है। उनके दल के ही कुछ विधायकों के मुख्यमंत्री से खासा नाराज होने और विपक्ष के संपर्क में होने की चर्चा भी जोरों से है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए भाजपा शीर्ष नेतृत्व को आनन-फानन यह निर्णय लेने को मजबूर होना पड़ा। नाराज धड़ा यदि टूटकर विपक्ष के पाले में जा मिलता तो सरकार पर संकट आना लाजमी था। जो मोदी सरकार की फजीहत करने वाला साबित होता। इधर दिल्ली सरकार में पताका फहराने का जोश मन्दा भी नहीं पड़ा था कि हिंसा से झुलस रहे मणिपुर की सत्ता पर संकट गहराता भांपते ही स्थिर पर काबू करने के लिहाज से इस्तीफे की कड़वी दवा गले उतारी गई। मणिपुर के अकेले चर्चित फुटबॉल खिलाड़ी रहे बीरेन पत्रकारिता में भी हाथ अजमा चुके हैं। खिलाड़ी और संपादक रहने के नाते उन्हें दांवपेंच का महारथी माना जाता रहा है। कुछ ही दिन पहले उनका कथित इस्तीफा भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जिसे फटा हुआ बताकर शरारत साबित करने की कोशिशें की गई थीं। सबसे लंबे समय तक वहां के मुख्यमंत्री रहे ओकराम इबोबी के सबसे करीबी रहने और उनसे राजनीतिक दांव-पेच सीखने वाले सिंह ने न सिर्फ उनसे बगावत की बल्कि पलटवार करते हुए सत्ता भी हासिल की। आशंका की जा सकती है कि सिंह अपने तेवर फिर दिखाने से चूकेंगे नहीं और सियासी घमासान में पुराना पैंतरा आजमाने से हिचक नहीं सकते। राज्य में शांति बहाली की प्राथमिकता को स्वीकारते हुए केंद्र को भीतरघात के प्रति चौकन्ना रहने के प्रति खास तवज्जो देनी होगी।

चिंतन-मनन

दुखी चित्त के लक्षण हैं उत्सव

दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं- एक वे जो अपने को नया करने का राज खोज लेते हैं, और एक वे जो अपने को पुराना बनाए रखते हैं और चीजों को नया करने में लगे रहते हैं। भौतिकवादी और आध्यात्मवादी में एक ही फर्क है। आध्यात्मवादी रोज अपने को नया करने की चिंता में संलग्न है। क्योंकि उसका कहना यह है कि अगर मैं नया हो गया तो इस जगत में मेरे लिए कुछ भी पुराना न रह जाएगा। क्योंकि जब मैं ही नया हो गया तो पुराने का स्मरण करने वाला भी न बचा, पुराने को देखने वाला भी न बचा, हर चीज नई हो जाएगी। और भौतिकवादी कहता है कि चीजें नई करो, क्योंकि स्वयं के नए होने का तो कोई उपाय नहीं है। नया मकान बनाओ, नई सड़कें लाओ, नए कारखाने, नई सारी व्यवस्था करो। उत्सव हमारे दुखी चित्त के लक्षण हैं। चित्त दुखी है वर्ष भर, एकाध दिन हम उत्सव मना कर खुश हो लेते हैं। वह खुशी बिल्कुल थोपी गई होती है।

क्योंकि कोई दिन किसी को कैसे खुश कर सकता है? दिन! अगर कल आप उदास थे और कल मैं उदास था, तो आज दिवाली हो जाए तो मैं खुश कैसे हो जाऊंगा? हां, खुशी का भ्रम पैदा करुंगा। दीये, पटाके, फुलझड़ियां और रोशनी धोखा पैदा करेंगी कि आदमी खुश हो गया। लेकिन ध्यान रहे, जब तक दुनिया में दुखी आदमी हैं, तभी तक दिवाली है। जिस दिन दुनिया में खुश लोग होंगे उस दिन दिवाली नहीं बचेगी, क्योंकि रोज ही दिवाली जैसा जीवन होगा। जब तक दुनिया में दुखी लोग हैं तब तक मनोरंजन के साधन हैं। जिस दिन आदमी आनंदित होगा उस दिन मनोरंजन के साधन एकदम विलीन हो जाएंगे। कभी यह सोचा न होगा कि अपने को मनोरंजित करने वही आदमी जाता है जो दुखी है। इसलिए दुनिया जितनी दुखी होती जाती है उतने मनोरंजन के साधन हमें खोजने पड़ रहे हैं। चौबीस घंटे मनोरंजन चाहिए, क्योंकि आदमी दुखी होता चला जा रहा है।

हम समझते है कि जो आदमी मनोरंजन की तलाश करता है, बड़ा प्रफुल्ल आदमी है। ऐसी भूल में मत पड़ जाना। सिर्फ दुखी आदमी मनोरंजन की खोज करता है। और सिर्फ दुखी आदमी ने उत्सव ईजाद किए हैं। पुराने पड़ गए चित्त में, जिसमें धूल ही धूल जम गई है; वह नए दिन, नया साल, इन सबको ईजाद करता है। और धोखा पैदा करता है थोड़ी देर। कितनी देर नया टिकता है? कल फिर पुराना दिन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दिन के लिए हम अपने को झटका देकर जैसे झाड़ देना चाहते हैं सारी राख को, सारी धूल को। उससे कुछ होने वाला नहीं है।

संत रविदास जयंती : मानवतावादी संत थे संत रविदास

योगेश कुमार गोयल

समस्त भारतीय समाज को भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता और भाईचारे की सीख देने वाले 15वीं सदी के महान समाज सुधारक संत रविदास का जन्म वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के ही दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को है, इसीलिए इसी दिन संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। महान संत, समाज सुधारक, साधक और कवि रविदास ने जीवन पर्यन्त छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध करते हुए समाज में फैली तमाम बुराईयों के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई और उन कुरीतियों के खिलाफ निरन्तर कार्य करते रहे। उनका जन्म ऐसे विकट समय में हुआ था, जब समाज में घोर अंधविश्वास, कुप्रथाओं, अन्याय और अत्याचार का बोलबाला था, धार्मिक कट्टपंथता चरम पर थी, मानवता कराह रही थी। उस जमाने में मध्यमवर्गीय समाज के लोग कथित निम्न जातियों के लोगों का शोषण किया करते थे। ऐसे विकट समय में समाज सुधार की बात करना तो दूर की बात, उसके बारे में सोचना भी मुश्किल था लेकिन जूते बनाने का कार्य करने वाले संत रविदास ने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए समाधि, ध्यान और योग के मार्ग को अपनाते हुए असीम ज्ञान प्राप्त किया और अपने इसी ज्ञान के जरिये पीड़ित समाज एवं दीन-दुखियों की सेवा कार्य में जुट गए। उन्होंने अपनी सिद्धियों के जरिये समाज में व्याप्त आडम्बरों, अज्ञानता, झूठ, मक्कारी और अधार्मिकता का भंडाफोड़ करते हुए समाज को जागृत करने और नई दिशा देने का प्रयास किया।

संत रविदास को 'रैदास' के नाम से भी जाना जाता है। वे गंगा मैया के अनन्य भक्त थे। संत रविदास को लेकर 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' कहावत बहुत प्रचलित है। इस कहावत का संबंध संत रविदास की महिमा को परिलक्षित करता है। वे जूते बनाने का कार्य किया करते थे और इस कार्य से उन्हें जो भी कमाई होती, उससे वे संतों की सेवा किया करते और उसके बाद जो कुछ बचता, उसी से परिवार का निर्वाह करते थे। एक दिन रविदास जूते बनाने में व्यस्त थे कि तभी उनके पास एक ब्राह्मण आया और उनसे कहा कि मेरे जूते टूट गए हैं, इन्हें ठीक कर दो। रविदास उनके जूते ठीक करने लगे और उसी दौरान उन्होंने ब्राह्मण से पूछ लिया कि वे कहां जा रहे हैं? ब्राह्मण ने जवाब दिया, 'मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं पर चमड़े का काम करने वाले तुम क्या जानो कि इससे कितना पुण्य मिलता है!' इस पर रविदास जी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, हम नीच और मलिन लोगों के गंगा स्नान करने से गंगा अपवित्र हो जाएगी। जूते ठीक होने के बाद ब्राह्मण ने उसके बदले उन्हें एक कौड़ी मूल्य देने का प्रयास किया तो संत रविदास ने कहा कि इस कौड़ी को आप मेरी ओर से गंगा मैया को 'रविदास की भेंट' कहकर अर्पित कर देना।

ब्राह्मण गंगाजी पहुंचा और स्नान करने के पश्चात जैसे ही उसने रविदास द्वारा दी गई मुद्रा यह कहते हुए गंगा में अर्पित करने का प्रयास किया कि गंगा मैया रविदास की यह भेंट स्वीकार करो, तभी जल में से स्वयं गंगा मैया ने अपना हाथ निकालकर ब्राह्मण से वह मुद्रा ले ली और मुद्रा के बदले ब्राह्मण को एक सोने का कंगन देते हुए वह कंगन रविदास को देने का कहा। सोने का रत्न जड़ित अत्यंत सुंदर कंगन देखकर ब्राह्मण के मन में लालच आ गया और उसने विचार किया कि घर पहुंचकर वह यह कंगन अपनी पत्नी को देगा, जिसे पाकर वह बेहद खुश हो जाएगी। पत्नी ने जब वह कंगन देखा तो उसने सुझाव दिया कि क्यों न रत्न जड़ित यह कंगन राजा को भेंट कर दिया जाए, जिसके बदले वे प्रसन्न होकर हमें मालामाल कर देंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण राजदरबार पहुंचा और कंगन राजा को भेंट किया तो राजा ने ढ़ेर सारी मुद्राएं देकर उसकी झोली भर दी। राजा ने प्रेमपूर्वक वह कंगन अपनी महारानी के हाथ में पहनाया तो महारानी इतना सुंदर कंगन पाकर इतनी खुश हुई कि उसने राजा से दूसरे हाथ के लिए भी वैसे ही कंगन की मांग की।

राजा ने अगले ही दिन ब्राह्मण को दरबार बुलाया और उसे वैसा ही एक और कंगन लाने का आदेश देते हुए कहा कि अगर उसने तीन दिन में कंगन लाकर नहीं दिया तो वह दंड का पात्र बनेगा। राजाज्ञा सुनकर बेचारे ब्राह्मण के होश उड़ गए। वह गहरी सोच में डूब गया कि आखिर दूसरा कंगन वो कहां से लाएगा? उसे जब और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने निश्चय किया कि वह संत रविदास के पास जाकर उन्हें सारे वाकये की जानकारी देगा कि कैसे गंगा मैया ने स्वयं यह कंगन उसे उन्हें देने के लिए दिया था, जो उसने लोभवश अपने पास रख लिया। अंततः यही सोचकर वह रविदास जी की कुटिया में जा पहुंचा। रविदास उस समय प्रभु का स्मरण कर रहे थे। ब्राह्मण ने जब उन्हें सारे वृत्तांत की विस्तृत जानकारी दी तो रविदास जी ने उनसे नाराज हुए बगैर कहा कि तुमने मन के लालच के कारण कंगन अपने पास रख लिया, इसका पछतावा मत करो। रही बात राजा को देने के लिए दूसरे कंगन की तो तुम उसकी चिंता भी मत करो, गंगा मैया तुम्हारे मान-सम्मान की रक्षा करेंगी। यह कहते हुए उन्होंने अपनी वह कठौती (चमड़ा भिगोने के लिए पानी से भरा पात्र) उठाई, जिसमें पानी भरा हुआ था और जैसे ही गंगा मैया का आव्हान करते हुए अपनी कठौती से जल छिड़का, गंगा मैया वहां प्रकट हुई और रविदास जी के आग्रह पर उन्होंने रत्न जड़ित एक और कंगन उस ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार खुश होकर ब्राह्मण राजा को कंगन भेंट करने चला गया और रविदास जी ने उसे अपने बड़प्पन का जरा भी अहसास नहीं होने दिया। ऐसे थे महान संत रविदास जी, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं।

(लेखक 35 वर्षों से साहित्य एवं पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं)

चीन : ऐसे किया जाता है विकास

विनीत नारायण

हमारे पड़ोसी देश चीन ने पिछले सप्ताह एक बार फिर से सुर्खियां बनाई। इस बार भारत में घुसपैठ नहीं बल्कि भारत और दुनिया भर के लिए एक उदाहरण बना। चीन ने अपने नवाचार द्वारा एक रेगिस्तान को न सिर्फ रोका बल्कि उसे हरा-भरा भी कर दिया। चीन का यह विकास कार्य आज काफी चर्चा में है। 'मौत का सागर' के रूप में जाने जाना वाला तकलामाकन रेगिस्तान 337,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका आकार लगभग पश्चिमी देश जर्मनी के बराबर का क्षेत्र है। इसके विशाल रेत के टीलों और बार-बार आने वाले रेतीले तूफानों ने लंबे समय तक मौसम के पैटर्न को बाधित किया है। कृषि को खतरे में डाला है और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। जवाब में चीन ने एक व्यापक हरित अवरोध लागू किया है, जिसे रेगिस्तान के किनारों को लॉक करने और इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन प्रयासों ने न केवल रेलवे और राजमागरे जैसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा की है, बल्कि यह भी प्रदर्शित किया है कि टिकाऊ प्रौद्योगिकियां मरुस्थलीकरण का प्रतिकार कैसे कर सकती हैं।

सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पण्रालियों को एकीकृत करके, चीन पृथ्वी पर सबसे कठिन वातावरणों में से एक में वनस्पति को बनाए रखने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर रहा है।

तकलामाकन रेगिस्तान के इस व्यापक पहल पर चार दशकों से काम चलाया गया। ग्रीनबेल्ट का पहला 2,761 किलोमीटर का काम कई वर्षों में पूरा हुआ, अंतिम चरण नवम्बर 2022 में शुरू हुआ, जिसमें रेगिस्तानी चिनार, लाल विलो और सैक्सौल पेड़ों जैसी लचीली, रेगिस्तान-अनुकूल प्रजातियों को रोपने के लिए 600,000 श्रमिकों को एक साथ लाया गया-जो शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये पौधे कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं: वे खिसकती रेत को सहारा देते हैं, रेगिस्तान के विस्तार को धीमा करते हैं और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। यह परियोजना इतिहास में सबसे महत्त्वाकांक्षी पुनर्वनीकरण प्रयासों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है, जो दुनिया भर में भूमि क्षरण से निपटने के लिए एक नई मिसाल कायम करती है।

उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में ग्रीनबेल्ट का प्राथमिक लक्ष्य मरुस्थलीकरण को रोकना है, यह परियोजना दीर्घकालिक आर्थिक अवसर भी पैदा कर रही है। कुछ नये लगाए गए पेड़, जैसे कि रेगिस्तानी जलकुंभी में औषधीय गुण होते हैं, जो संभावित रूप से हर्बल चिकित्सा के लिए आकषर्क बाजार खोलते हैं। इसके अलावा, 2022 में, चीन ने हॉटन-रुओकियांग रेलवे का उद्घाटन किया, जो रेगिस्तान के चारों ओर दुनिया की पहली पूरी तरह से घिरी हुई रेलवे थी। 2,712 किलोमीटर लंबा रेलवे रेगिस्तानी शहरों को जोड़ता है, जिससे अखरोट और लाल खजूर जैसे स्थानीय कृषि उत्पादों को पूरे चीन के बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और विकास को और बढ़ावा मिलता है। खबरों के मुताबिक चीन पुनर्वनरोपण पर रोक नहीं लगा रहा है बल्कि तकलामाकन रेगिस्तान में एक विशाल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना भी चल रही है।

चाइना श्री गोरजेस कॉर्पोरेशन 8.5 गीगावाट सौर ऊर्जा और 4 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने की योजना का नेतृत्व कर रहा है, जिसके अगले चार वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। रेगिस्तान की बहाली को टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन के साथ जोड़कर, चीन उस चीज को हरित विकास के अवसर में बदल रहा है जो कभी एक पारिस्थितिक चुनौती थी। गौरतलब है कि तकलामाकन ग्रीनबेल्ट की सफलता मरु स्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है। इसी तरह की बड़े पैमाने की परियोजनाएं, जैसे कि अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल, का उद्देश्य पूरे महाद्वीप में 8,000 किलोमीटर लंबे वृक्ष अवरोधक लगाकर सहारा रेगिस्तान के विस्तार को रोकना है।

तकलामाकन रेगिस्तान का विकास कार्य समान पारिस्थितिक खतरों का सामना करने वाले अन्य देशों के लिए एक खाका के रूप में भी कार्य कर रहा है। यह उपलब्धि नवीन पर्यावरणीय समाधानों के प्रति चीन की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। हरित प्रौद्योगिकियों और बड़े पैमाने पर पुनर्वनीकरण का लाभ उठाकर, राष्ट्र ने न केवल अपने स्वयं के

बुनियादी ढांचे और कृषि को सुरक्षित किया है, बल्कि भविष्य की वैश्विक रेगिस्तान बहाली परियोजनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है। भारत सहित सभी विकासशील देशों को चीन से सबक लेते हुए यह सीखना चाहिए कि विषम परिस्थितियों में भी विकास कार्य किए जा सकते हैं। ओछी राजनीति करने से किसी का भी लाभ नहीं होता। यदि केंद्र में और राज्य में दो अलग दलों की सरकार भी हो तो विकास कार्य पर किसी भी तरह की रोक लगाना आम जनता के साथ धोखा है। इसलिए यदि सही सोच वाला नेतृत्व सही योजनाओं को स्वीकृति करे तो ऐसे भ्रष्टाचार से बचा जा सकता है और ताकलामाकन रेगिस्तान जैसे कई विकास कार्य दोहराया जा सकते हैं।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

US order on workforce diversity will hit Indians

Within hours of taking office as the 47th President of the United States, Donald Trump ended reservation of jobs in the US government. It took only a moment for him to take this huge step with the flourish of his calligraphic signature.

Without further ado, many US private companies hastened to follow suit. Thus ended a journey for America's diverse society that began with John F Kennedy and was extended by almost every subsequent US president.Job reservations and priority in admissions to educational institutions have been a raging issue in India for a long time. Concerns that such reservations may be terminated or reduced for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes even influenced the outcome of the Lok Sabha elections last year. Yet, this history-making decision in the world's oldest democracy has not produced even a whimper in India.Americans are very good at giving names for programmes which make them sound far nobler than what they are. So, during the Camelot-era grandeur of Kennedy's presidency, an effort to end discrimination against weaker sections of society in employment came to be officially known as "affirmative action." Kennedy's initiative, which Trump effectively reversed on January 20, was announced by him six weeks after being sworn in as President in 1961. Like Trump, Kennedy also did it through an executive order. Affirmative action was rechristened as "diversity and inclusion" by President Barack Obama formally in 2011.

Trump has now accused his immediate predecessor Joe Biden of 'DEI madness.' In the Biden years, DEI became the short form for diversity, equity and inclusion. Very recently, the letter 'A' was added to DEI to include accessibility.

Ronald Reagan was the only President since Kennedy to take a stand against affirmative action. He issued an executive order against fixing quotas in jobs and recruitment goals. But he could not reverse affirmative actions in toto because of opposition in both Houses of Congress and among trade unions. However, Reagan favoured clearly defined plans to create business enterprises owned and run by minorities.Incidentally, Reagan was the first US President to appoint an Indian-American to a federal agency in a position which required presidential nomination. In 1987, he appointed Joy Cherian as a member of the Equal Employment Opportunity Commission. This commission was established under the Civil Rights Act of 1964 to enforce laws against discrimination in places of work.Opposition to DEI — which is roughly the equivalent of reservations in India — has been steadily building up in the US. It has been much stronger than any movement against mere affirmative action, which was small in scope and scale. Republicans, in particular, have argued that affirmative action programmes have become a form of reverse discrimination in an equal society.

Opinion has been growing on the ground that DEI is against meritocracy, which the US society is supposed to uphold. These are familiar arguments in India, too, among those opposed to reservations.

Two years ago, the US Supreme Court ruled in an overwhelming 6-2 judgment that favouring a race — reservations — in college admissions goes against equal protection clauses in the US Constitution. While all this is at the federal level, several states had enacted laws against reservations in their jurisdictions.

In India, resentment against reservations in institutions of higher learning is rampant, but largely silent. The anti-Mandal Commission agitation by students in 1990 was a rare occasion when such resentment found its way to the streets. According to authoritative estimates, 200 students across India attempted self-immolation against the implementation of the commission's report on reservations.While job reservations in India do not apply to the private sector, businesses in the US, especially large companies, have embraced DEI. Most of them have done it to be politically correct. The alacrity with which several conglomerates swiftly followed up on Trump's first-day executive order showed that their support for affirmative actions was insincere. Trump has urged America's private sector also to "end illegal DEI discrimination and preferences."

Healthcare gets a booster shot with 10% budgetary hike

In a move with a far-reaching impact on out-of-pocket expenses, the Budget proposes to reduce the prices of many drugs.

The Union Budget 2025-26 has given priority to the healthcare sector with provisions for expanding medical education, promoting medical research, enhancing cancer care affordability, extending the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) to gig workers and promoting medical tourism.

The Economic Survey 2024-25, tabled in Parliament on January 31, brought out an increase in India's health spending to Rs 6.1 lakh crore in 2025 from Rs 3.2 lakh crore in 2020-21. India's share of health expenditure rose to 3.8 per cent of the GDP in 2022. Between 2015 and 2022, out-of-pocket expenses dropped from 62.6 per cent to 39.4 per cent, with the PM-JAY playing a decisive role in it.To provide universal health coverage to all citizens, the PM-JAY benefit was extended last year to all people over 70 years. The government now proposes to include gig workers under the scheme. This move will ensure financial and health security for an estimated one crore workers in the informal sector who were not covered earlier under any insurance. However, for this, the government must ensure that the aggregator companies must be transparent in sharing data on gig workers.While the proposed allocation for health has gone up by 9.7 per cent to Rs 99,858.56 crore compared to the previous year, the Ayushman Bharat Infrastructure Mission gets a 26 per cent increase while the PM-JAY has a raise of 28.85 per cent, keeping in view its increasing ambit.Though the Economic Survey has talked of the importance of health of the nation, more emphasis is required towards health promotion and disease prevention.

The FM announced 10,000 additional seats in medical colleges in the coming year and 75,000 seats in the next five years. In the last 10 years, MBBS and postgraduate seats have more than doubled to 1,18,137 and 73,157, respectively. However, there are major concerns in this regard. There is a dearth of medical teachers and the National Medical Commission has been diluting the norms for the numbers and experience of teachers. A huge disparity between undergraduate and postgraduate seats remains.Additionally, there should be a dynamic policy for the number of seats in different specialities. For example, India will need more oncologists, intensivists and trauma specialists in the coming years and fewer cardiac surgeons. The country also needs more skilled manpower, like nurses, technicians and other support staff, which needs dynamic planning.

The government has proposed major initiatives to help cancer patients. Statistics show a rising incidence of all major cancers in the country. According to the National Cancer Registry Programme Report 2020, one in nine persons is likely to develop cancer in their lifetime. The government will facilitate the setting up of day-care cancer centres in all district hospitals in the next three years, with 200 centres to be established in 2025-26. Such centres are typically used for chemotherapy. They will facilitate access to cancer treatment, which is now available at tertiary care centres only. It is proposed to use the PPP mode for this initiative. However, there is a shortage of trained manpower and infrastructure, like advanced imaging and cancer diagnostics, both of which need to be addressed.In a move with a far-reaching impact on out-of-pocket expenses, the Budget proposes to reduce the prices of many drugs. To provide relief to patients suffering from cancer, rare diseases and other chronic diseases, 36 lifesaving drugs have been fully exempted from basic customs duty. Six additional lifesaving medicines will now attract concessional customs duty of 5 per cent. Concessions will also be granted to bulk manufacturers of the above classes of drugs to promote local companies.Another proposed thrust area is medical tourism. With the availability of expert medical professionals and infrastructure in the country, a multitude of private hospitals in India already attracts patients from South-East Asia, Africa and West Asia. It is estimated that some 1.4 crore people travel to different countries for better medical treatment every year. India has over 35 hospitals accredited by the JCI (Joint Commission International), which ensures adherence to global norms.The government had proposed a medical tourism initiative, 'Heal in India', in 2022 to be promoted in partnership with the private sector. But it was a non-starter. It was proposed to have a nodal agency, the Medical Value Travel Council, co-chaired by the health and tourism ministries to streamline the integration of all stakeholders. The government has re-emphasised the scope of medical tourism. It needs to ensure that steps are taken to tap the huge potential of medical tourism by streamlining access to patients and facilitating ancillary support units.

The Budget proposals are likely to boost pharmaceutical infrastructure by providing impetus to MSME units. The government has allocated Rs 2,445 crore to production-linked incentive in the pharma sector. A substantial sum of Rs 20,000 crore has been earmarked for private sector-driven research, development and innovation. As was seen during the Covid-19 pandemic, there is a need to indigenise drug discovery and production as well as the manufacture of medical equipment. India needs to go to the next level in medical innovation with emphasis on precision medicine, gene therapies and newer biologics.

Other notable proposals are allocation of funds for mental health and emphasis on providing nutrition to children and pregnant women. Allocation for medical research has been hiked by 18.14 per cent. The proposal to have 100 per cent FDI in insurance is a welcome step.

However, increasing tax exemption for preventive health check-ups, integrating outpatient diagnostics into insurance packages and rationalising GST in healthcare are among the measures needed.

The Budget proposals envisage a bigger role of the private sector. More stress must be laid on primary care and disease prevention and more discussions should be held on education and skill development of healthcare workers. The full potential of digital health records, telemedicine and AI needs to be realised.

The provision of internet facility at primary health centres can be leveraged to enhance digital health and telemedicine services. However, the National Health Mission gets only a 3.77 per cent raise.

BJP all the way

Delhi triumph a new high for saffron party

The BJP juggernaut, which was looking rusty and creaky after the party's underwhelming show in the 2024 Lok Sabha elections, is at its rampaging best once again. And that is ominous news for the Opposition's INDIA bloc, or whatever is left of it. After its superb victories in Haryana and Maharashtra last year, the BJP has finally captured the Delhi citadel — ending a painfully long wait of over 26 years. It has managed to topple the Aam Aadmi Party (AAP), arguably the most promising outfit to have emerged on the Indian political scene in the past decade or so. AAP had decimated the BJP and other rivals in the 2015 and 2020 Assembly elections, but this time it found itself weighed down by anti-incumbency and corruption charges against its top leaders, particularly Arvind Kejriwal. Itself a product of Anna Hazare's anti-corruption movement, AAP failed to shake off the graft taint. Moreover, the fledgling party's decision to go solo instead of joining hands with the Congress proved disastrous. As the voting day neared, Kejriwal's desperation was palpable: he saw demons everywhere, but ignored the dire need to set his own house in order.

Interestingly, the BJP beat AAP at its own game by offering freebies to women and other key groups of voters. The 2024 Lok Sabha verdict was a wake-up call for the ruling party. It realised that voters simply could not be taken for granted. The BJP shunned its one-size-fits-all strategy and instead focused on a state-specific agenda. It found an unlikely ally in the Congress, a spent force in the Capital that went hammer and tongs at Kejriwal.The Delhi mandate has triggered an existential crisis for AAP, which now only has Punjab in its kitty. And the BJP, with its well-oiled election-winning machine, will go all out to reverse its fortunes in Punjab as well as West Bengal, two states which have stubbornly resisted Modi's magic and the saffron surge.

How the AAP bubble burst

BJP went for the jugular by targeting Kejriwal and others over corruption charges

Facing its stiffest challenge in Delhi so far, the Aam Aadmi Party (AAP) was trounced by the BJP in the Assembly elections. The outcome ended a long run of the party led by Arvind Kejriwal, a former bureaucrat who won the hearts and minds of Delhi's voters in 2015 with his messianic zeal to fight corruption. His curious amalgam of politics that blended civic activism and pro-poor welfare programmes with a subtle play on religion and caste saw his party win the 2020 polls as well, with the BJP and the Congress failing to dent his popularity.

Keen on expanding his party's footprint, Kejriwal led AAP to victory in the 2022 Punjab elections as well. His success rattled his rivals, who grudgingly recognised his potential to tower above discredited or lacklustre regional leaders who were largely legatees. He could justifiably claim to be self-made. This claim, as also others that gave him an outsized standing in national politics, dissipated as the Delhi verdict came out on February 8. Kejriwal lost his own seat to a BJP dynast, Parvesh Verma, son of former CM Sahib Singh Verma.

Arrested in a money laundering case linked to the Delhi excise policy scam, Kejriwal remained behind bars for several months. After his release on bail, he stepped down as the CM with an air of martyrdom that he hoped would help him in the 2025 elections. His close aide, Manish Sisodia, who piloted AAP's flagship health and education programmes, was also arrested and kept in custody, as was another ex-minister, Satyendra Jain. Sisodia and Jain lost, while another former minister, Kailash Gahlot, who jumped ship and joined the BJP, ended on the winning side. The only AAP top gun to win was the outgoing CM, Atishi, who was not named in any graft case. Virtually the entire AAP leadership was wiped out, a reflection of the party's loss of credibility.

In the maelstrom of a bitterly contested poll between the BJP and AAP, the Congress upped the ante against Kejriwal but was unusually reticent about the BJP.

Indeed, its Delhi leaders spoke the BJP's language in assailing Kejriwal. Sandeep Dikshit, son of former Congress CM Sheila Dikshit, led from the front, giving the impression that he was more interested in avenging his late mother's defeat by AAP than winning seats for the grand old party. Rahul Gandhi acceded to the wishes of the party's Delhi leaders when they threatened him with an ultimatum: Confront Kejriwal or face a revolt.

Kejriwal's tenures, particularly the one that ended last year, were turbulent as the Centre decided to get tough with him and challenged every policy of his, bringing his governance to a grinding halt. The situation would not have been different had he won another term, perhaps a reason why some of his voters opted for the BJP, persuaded by the double-engine narrative.

Delhi may look tiny compared to bigger states that seem more precious to the BJP. But the Capital is significant because it is the centre of authority and power that can hold states like Uttar Pradesh and Maharashtra in thrall.

The BJP's sweep was all the more significant because in keeping with the Modi regime's reluctance to nurture regional leaders, the party did not announce its CM candidate in Delhi. Not that it lacked local leaders in the Capital. It identified those with pockets of influence so that various communities could be wooed. Manoj Tiwari focused on Brahmins, Parvesh Verma and Gahlot reached out to Jats, Dushyant Gautam catered to Dalits and so on. It was nearly impossible to crack this caste construct that did away with the vexatious problem of factionalism.Privately, the BJP never underestimated Kejriwal's potential to become a national leader. The message from the Punjab victory was not lost on the party. The Delhi triumph can boost the BJP's prospects of wresting Punjab from AAP with a regional ally in the 2027 elections.

Prime Minister Narendra Modi led the attack on corruption-tainted AAP. The focus was on Kejriwal's 'Sheesh Mahal', the CM's official bungalow on whose renovation crores of rupees were spent. Charges of financial irregularities in civic works undertaken both by the state government as well as AAP-controlled municipal bodies further undermined Kejriwal's probity.The BJP also deftly appropriated Kejriwal's welfare programmes, equalling his announcements measure for measure. The guarantees ran in tandem with the BJP's strategy to make its workers fan out into resettlement colonies to 'unmask' Kejriwal.

The high-decibel campaign worked. In contrast, Kejriwal's tactic to own up Hindutva in his own way fell flat. It proved that a leader's success in purloining his rival's agenda and dressing it up as his own depends on his credibility.Kejriwal's dalliance with Hindutva had another fallout. It angered and alienated Muslims, who saw AAP as a perfect foil for the BJP. Kejriwal's indifference to the plight of Muslims in the 2020 communal riots and Atishi's iterations against Rohingya migrants fuelled Muslim anger against the party.

AAP's rout could lead to more trouble for the INDIA bloc and its constituents. Bihar goes to the polls later this year and West Bengal in 2026. While the Congress' alliance with the Rashtriya Janata Dal is still intact in Bihar, Bengal presents a not-so-happy picture, with the ruling Trinamool Congress ploughing a lone furrow.

Indian oil, gas cos in talks with US for sourcing LNG

NEW DELHI. Indian companies such as GAIL, Indian Oil Corporation (IOC), and Bharat Petroleum Corporation (BPCL) are in active discussions with US companies for sourcing liquefied natural gas (LNG). Petroleum Secretary Pankaj Jain, speaking to the media on Monday, mentioned that Indian oil and gas companies would consider buying stakes in US LNG projects if the deals are attractive.

"Indian companies are looking at buying LNG from around the world, particularly from the US," said Pankaj. India, the fourth-largest LNG importer in the world, aims to increase the share of natural gas in its energy mix to 15% by 2030, up from over 6% at present. Currently, GAIL has term LNG contracts for 5.8 million tonne of US LNG. The bulk of India's long-term LNG volumes come from Qatar.

Petroleum minister Hardeep Singh Puri, speaking at a press conference, said energy could feature in the meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump. "I would be surprised if sourcing of energy (by India from the US) doesn't feature in the talks (during PM Modi's upcoming US visit)... With President Trump saying he wants to see global (energy) prices come down... for countries like India, that is a very positive development," said Puri.After taking charge last month, Trump lifted the Joe Biden administration's ban on export permits for new US LNG projects, which could further solidify Washington's position as the world's largest LNG exporter. Currently, GAIL has term LNG contracts totalling 5.8 million tonne of US LNG.

Stock Market Opens Lower As Trump Announces Steep Tariffs On Steel, Aluminium

Mumbai. The domestic benchmark indices opened lower on Tuesday, as US President Donald Trump formally announced plans to impose 25 per cent tariffs on all steel and aluminium imports coming into the United States "without exceptions or exemptions". At around 9.32 am, the Sensex was down 172.29 points or 0.22 per cent at 77,138.51 and the Nifty was down 56 points or 0.24 per cent at 23,324.80.The Indian Steel Association (ISA) has expressed deep concern over the US decision to impose tariffs on steel imports, urging the Indian government to push for the removal of long-standing anti-dumping and countervailing duties and to secure exemptions from these restrictive measures.The latest tariff is expected to slash steel exports to the US by 85 per cent. These tariffs could lead to a massive steel surplus that will likely flood the Indian market, ISA warned.

Eicher Motors and Apollo Hospitals dropped the most on the Nifty in reaction to their third-quarter financial results.The Nifty Realty and Nifty Auto declined the most on the NSE. Nifty Media and Nifty Pharma were other notable declines in early trade.According to experts, the stock market move suggests a cautious sentiment, influenced by global cues and the absence of strong domestic triggers.Investors will closely monitor global market trends, crude oil prices and institutional flows for further direction, they added.

On the daily chart, Nifty has formed a bearish candlestick, signalling negative sentiment. The index faces key resistance at 23,460, and a breakout above this level could drive further gains towards 23,550 and 23,700.Institutional flows remain a key factor in market sentiment. On February 10, foreign institutional investors (FIIs) sold equities worth Rs 2,463 crore, while domestic institutional investors (DIIs) bought equities worth Rs 1,515 crore."These transactions will be closely monitored for their impact on market direction. Overall, traders are advised to exercise caution and wait for confirmation of price action at key levels before initiating fresh positions," said Aakash Shah from Choice Broking.

Valuation, US tariff concerns weigh on mkt

NEW DELHI. Domestic stock market continues to reel under pressure despite a repo rate cut by the Reserve Bank of India (RBI) for the first time in 5 years and optimism surrounding the Union Budget. Further, a win by PM Narendra Modi's BJP in the Delhi state elections failed to lift sentiments.

Market experts feel concerns related to a possible tariff hike by the US has overshadowed the positivities. The street has also turned its focus on the valuation of the Indian market after valuation expert Aswath Damodaran in his latest blog wrote that the Indian stock market is the most expensive globally, even more than the US and China, and that no amount of optimism about India's growth story can justify its steep valuations.

Falling for the fourth straight session, the local benchmark indices – BSE Sensex and NSE Nifty – shed about 0.70% each on Monday. At close, the Sensex was down 548.39 points at 77,311.80, and the Nifty was down 178.35 points at 23,381.60. So far in 2025, the two indices are down about 1.5% each and from their 52-week high level, they are down 10-11% each.A bigger pain is being felt in the smallcap and midcap segments. On Monday, Nifty Midcap and Smallcap indices shed more than 2% each and so far in 2025 they are down 8% and 11%, respectively. "The US tariff threats continued to impact the market sentiment.Domestic yield is inching higher as investors stay cautious on riskier assets and navigate their investments to safe-haven assets like gold," said Vinod Nair, Head of Research, Geojit Financial Services.Latest reports surfaced highlighting that Trump may go for a 25% levy on steel and aluminium imports. The fresh tariff worry comes at a time when corporate earnings growth has slowed in recent quarters due to a weak demand environment, margin pressure, and a cautious near-term outlook.

Infosys mass layoffs: Fired trainees denied overnight stay on campus, left scrambling for shelter

Infosys fired around 400 trainees, with reports of forced same-day eviction and denied overnight stay requests, leaving many scrambling for transport home.

New Delhi. IT giant Infosys is facing sharp criticism after dismissing around 400 trainees at its Mysuru campus for allegedly failing internal evaluations.However, the company has come under fire for forcibly evicting them on the same day, even denying requests for an overnight stay. A Moneycontrol report detailed the ordeal of trainees let go on February 7, highlighting the abrupt nature of their removal.One of the dismissed trainees, a woman from Madhya Pradesh, tearfully pleaded with officials, saying, "Please let me stay the night. I will leave tomorrow. Where will I go right now?"Her plea fell on deaf ears, as a colleague recalled the officials' blunt response: "We don't know. You are no longer part of the company. Vacate the premises by 6 pm."The terminations were part of a mass layoff of around 400 trainees who failed to clear internal assessments after three attempts. Many, having joined Infosys over two years after graduation, were suddenly left scrambling for transport home, dreading the prospect of informing their families about their abrupt dismissal.According to Moneycontrol, the dismissals took place in a highly controlled environment, with batches of about 50 trainees being summoned early in the morning on February 7. They were reportedly ushered into a room, guarded by security personnel and bouncers, and informed under strict confidentiality not to discuss the situation with others.

The process, described by one of the dismissed trainees, involved the use of buses as shields to prevent attention from Finacle (Infosys' digital banking platform) employees and several clients from the US who were present on campus.The company's official statement clarified that its rigorous hiring process includes three assessment attempts for trainees, and those who fail to meet the criteria are let go, in line with company policy. "This process has been in existence for over two decades and ensures a high quality of talent availability for our clients," an Infosys employee had told Moneycontrol.

However, several former trainees hae raised concerns over the stricter eligibility criteria introduced for the 2024 batch. Allegedly, changes to the evaluation system made assessments more challenging, with trainers warning that many trainees would struggle.As of now, there are concerns that up to 4,500 trainees still in training may face a similar fate if they do not meet the new benchmarks.The evaluation system itself has also undergone significant changes.In the previous structure, trainees were required to clear two phases: generic and technology stream, with an overall passing rate of 50 percent. But, the current system imposes far stricter requirements, including a minimum of 65 percent in each area of evaluation.Additionally, the syllabus has been greatly expanded, leaving trainees with insufficient time to complete the required coursework, especially given the extended hours of self-study required.those in lower-paying positions.

Digitisation does not mean deregulation: CEA Nageswaran

MUMBAI. There is a "misperception" among government departments that digitisation equates to deregulation, Chief Economic Adviser (CEA) V Anantha Nageswaran said on Tuesday.Speaking at an event organised by the alternative investment industry's lobby group IVCA, Nageswaran emphasised that removing unnecessary regulations is essential, regardless of whether compliance is required online or offline."There is a misperception that the moment a government department puts something on a digital platform, they think it is deregulation. But that is not deregulation; you just made it online rather than offline," he said."Digitisation per se is not deregulation," he added, pointing out that the recent Economic Survey had highlighted the need for deregulation to boost GDP growth.

Nageswaran stressed that developed economies have achieved their status by addressing challenges faced by small businesses, particularly regulatory burdens that consume time and resources. He underlined the importance of streamlining compliance processes to support economic expansion.

He also noted that India must rely more on its domestic economy for growth, as globalisation is unlikely to deliver benefits as it did in the past. "De-globalisation is part of a cyclical trend

seen over a century," he said, adding that a shift in global economic models could emerge in the next decade.

Discussing inflation, the CEA said it is likely to remain more persistent than in the past due to diminishing efficiency gains. However, if India can lower inflation to 3-4 per cent from the 4-5 per cent seen in recent years, it would help stabilise the rupee."Over the long term, we can see that the rupee has depreciated at 3% per annum, which is the differential between the inflation rate in India and the US," he explained.

Addressing energy security, Nageswaran said India cannot afford to compromise on its energy needs while transitioning to greener sources. "We should be pragmatic and not make green energy into a 'religion' as some countries in Europe have done," he remarked.

He also emphasised the critical role of nuclear energy in the transition, highlighting the recent budget announcement allowing private sector participation in the industry.

"A country needs resources to achieve ambitious goals like energy transition, and those resources come only through sustained economic growth, which in turn depends on sufficient energy availability," he said.

India has the potential to grow at 6.5-7 per cent annually over the long term, making it one of the few major economies capable of such expansion, he noted. Additionally, the country's demographic advantage is expected to last for the next 15-20 years, further supporting its economic growth.

Why Eicher Motors shares dropped 7% despite record Royal Enfield sales in Q3

NEW DELHI. Shares of Eicher Motors fell nearly 7% in early trade on Tuesday despite reporting positive figures in its Q3FY25 results. The stock tumbled as much as 6.8% to hit an intraday low of Rs 4,966.15 after brokerage firm Goldman Sachs downgraded its target price.

Eicher Motors reported an 18% year-on-year (YoY) rise in consolidated net profit to Rs 1,171 crore, while the company's revenue from operations rose 19% to Rs 4,973 crore. Its EBITDA increased 10% YoY to Rs 1,201 crore.

GOLDMAN SACHS CUTS TARGET PRICE

While Eicher Motors put up a good show in the third quarter, the foreign brokerage cut its FY25-27 earnings per share (EPS) by 5.4%, citing higher expenses. While Goldman Sachs did maintain its 'Buy' rating, it has lowered its target price on the stock to Rs 5,900 from Rs 6,000., Goldman Sachs cut its FY25-27 EPS estimates by 5.4%, citing higher marketing expenses. The brokerage maintained a 'Buy' rating but lowered the stock's target price from Rs 6,000 to Rs 5,900.

It may be noted that Eicher Motors' commercial vehicle arm, VE Commercial Vehicles (VECV), recorded a 6% YoY rise in revenue to Rs 5,801 corer and its EBITDA climbed 16% to Rs 509 crore. Profit after tax surged 44% to Rs 301 crore. VECV recorded its highest-ever quarterly sales volume at 21,012 units, outperforming the industry despite a sluggish commercial vehicle market.In addition, the company's flagship Royal Enfield motorcycle also delivered its best-ever quarter, selling 269,039 motorcycles—up 17% YoY—driven by strong global demand. CEO B Govindarajan credited strategic groundwork and festive season sales for the record-breaking performance."Our performance in the last quarter is a result of the groundwork we put in through the year—preparing for key launches and optimising operations to ensure we were ready to deliver at this scale, especially during the festive season in India," said Govindarajan, CEO of Royal Enfield.

India, France stress on democratised access to AI at Paris roundtable

NEW DELHI. India and France have emphasised on the need for democratised access to Artificial Intelligence (AI) resources and capacity building while recognising the importance of the techno-legal frameworks.Addressing a roundtable session in Paris through videoconferencing, principal scientific advisor to the government of India, Ajay Kumar Sood, said India and France need to synergise on various policy positions and technological initiatives, fostering benefits not only at the bilateral level but also on a global scale by leveraging complementary knowledge and skill sets.The roundtable was held on the Sciences Po campus in Paris University on Monday on the margins of the AI Action Summit, which Prime Minister Narendra Modi will co-chair with French President Emmanuel Macron on Tuesday.Sood said India's priorities in global AI policy and governance include responsible AI development and deployment, equitable benefit sharing, adoption of a techno-legal framework for AI governance, interoperable data flows, and collaboration on AI safety, research and innovation.The roundtable was co-chaired by Amit A Shukla, joint secretary, cyber diplomacy division, Ministry of External Affairs, and Henri Verdier, Ambassador for digital affairs, French Ministry for Europe and Foreign Affairs.The participants highlighted the significance of sovereign AI models, ethical AI deployment and the need to define globally accepted terminologies and standards.The roundtable also shared views on multilingual LLMs, federated AI compute infrastructure, and interoperable access to AI research, datasets, and high-performance computing resources.The meeting covered key discussions on collaborations between India and France and highlighted the opportunities in creating indigenous foundation models and adopting a balanced governance approach to minimise risks.

Fund manager Naren's take on SIP sparks debate in MF industry

…I believe that investors who have started SIPs from 2023 in small and midcap, they're going to have a very bad, very bad experience.

NEW DELHI. ICICI Pru AMC's fund manager S Naren's take on systematic investment plans (SIPs) has sparked a debate in mutual fund industry. Speaking at the IFA Galaxy 2025, an event organised by a Chennai-based mutual fund association, Naren advised it is a "clear time to take out lock, stock, and barrel from small- and mid-caps."

"…I believe that investors who have started SIPs from 2023 in small and midcap, they're going to have a very bad, very bad experience. Is this a time to take out money from small and midcap? We think it is a clear time to take out lock, stock, and barrel from small and midcap," said Naren.He added that this is the time to even stop small and midcap

SIPs because they're so overvalued. He explained that SIP has to be done in volatile and undervalued asset classes. If you do SIPs in overvalued asset classes – like China three years ago, or Indian equities in 1994 or 2007-2008 – you only have yourself to blame, he said.

Naren also highlighted that 2025 could be the most dangerous year since the 2008-2010 period when investors had lost a lot of their money. He cautioned that the momentum in small and mid-cap stocks is starting to fade. Naren's remarks come at a time when the Indian equity market, especially the midcap and smallcap stocks, is going through a correction phase after 4-year strong bull run. So far in 2025 alone, Nifty midcap and smallcap indices plummeted 10-11% each.Radhika Gupta, CEO of Edelweiss Mutual Fund said that one should not fall for the fear-mongering 10-day debates. On social media platform X, Gupta said that everything including mid and small is good in balance and even an average flexi cap fund has a 30% allocation to this category. She also said that it's essential to stay invested in SIPs for the long term, ideally 10 years or more.

Aashish P Sommaiyaa, CEO of WhiteOak Capital, without taking Naren's name, wrote on social media, "If the market goes up I am a star manager. If market goes down you gave me money at wrong time and started your SIP at peak." He said,"No brownies for avoiding volatile asset classes or smoothening the journey proactively. But lot of brownies for enabling risk taking, launching one narrow sectoral NFO per month and then taking a dump on distributors, industry peers, issuer companies and investors. Conduct with contradictions and cognitive dissonance yet gaslight the world."'Momentum in small, mid-cap starting to fade'S Naren cautioned that the momentum in small and mid-cap stocks is starting to fade. Naren's remarks come at a time when the Indian equity market, especially the midcap and smallcap stocks, is going through a correction phase after 4-year strong bull run.

"12 Hours For 4 Hours Journey": Massive Traffic Jams In Prayagraj Amid Kumbh

Major highways connecting Prayagraj, Ayodhya, and Kashi are choked, with vehicles stranded for hours.

New Delhi. The roads leading to the Maha Kumbh Mela in Prayagraj are witnessing unprecedented congestion as millions of devotees continue to arrive for taking holy dip at the Triveni Sangam.Despite the completion of three significant Amrit Snans on auspicious days of Makar Sankranti, Mauni Amavasya, and Basant Panchami, the influx of pilgrims shows no signs of slowing down, leading to severe travel delays.Major highways connecting Prayagraj, Ayodhya, and Kashi are choked, with vehicles stranded for hours.

A devotee travelling from Ayodhya shared his ordeal, saying, "Since last night, we have covered only 40 kilometres. We had been stuck in traffic since 7 PM, and we had to sleep in our car. The public's impatience is making things worse."

Another pilgrim added, "There is a traffic jam, and the public is facing difficulties. Normally, this journey takes four hours, but now it's taking nearly 12 hours."The situation has severely impacted residents, who are struggling with daily commutes and a shortage of essential supplies. A Prayagraj local expressed concern, stating, "Commuting has become a nightmare. Even basic supplies like ration and milk are unavailable."

Meanwhile, Pilgrims travelling from neighbouring states, including Bihar, are also facing extreme difficulties. The congestion has now extended to the Rohtas-National Highway in Sasaram, Bihar, where a 10-kilometre-long traffic jam has forced travellers to spend both day and night on the roadside.Authorities are making efforts to manage the growing crowd, but the sheer volume of devotees continues to test the city's infrastructure. With more religious gatherings expected, traffic congestion is likely to remain a major challenge in the coming weeks.Travellers are advised to plan their journeys accordingly and stay updated with traffic advisories.Earlier in the day, Prayagraj administration issued a comprehensive traffic advisory in preparation for the Magh Purnima Snan on February 12. This advisory aims to ensure the smooth movement and safety of devotees, addressing the significant traffic issues faced by attendees.

Court summons Andhra, Delhi, J&K chief secretaries over misleading medical ads

NEW DELHI. The Supreme Court on Monday raised concerns over Andhra Pradesh, Delhi and Jammu & Kashmir's failure to comply with Rule 170 of the Drugs and Cosmetics Rules, which grants authorities power to act against misleading advertisements of Ayurvedic medicines.

The court directed Andhra Pradesh, Delhi, and Jammu and Kashmir to submit affidavits on compliance with Rule 170. It noted that the states had shown little implementation of the rule.The court ordered the chief secretaries of these three states to appear via video conference at the next hearing on March 7 to explain the lack of compliance. The court, however, did not review compliance by Goa and Gujarat, as they have submitted new affidavits.

The amicus curiae assisting the court referred to the Supreme Court's August 27, 2024, order, which had stayed the effect of the Ministry's notification omitting Rule 170. The court had ruled that the provision would remain in force.The amicus submitted that enforcement of the rule by states would address the issue of illegal advertisements of Ayurvedic medicines.

The court directed the states to file affidavits within a month and scheduled the next hearing for March.Regarding the summons to chief secretaries, the bench remarked that this was the most effective method to ensure compliance."Our long experience sitting this side is, this is the best way of ensuring compliance of orders. The moment we get chief secretaries, compliance is very smooth. It is a sufficient signal for them that it is to be taken seriously," Justice Oka said.

In January, the court had set deadlines for states to demonstrate compliance. It had also stated that if any state or union territory was found non-compliant, contempt proceedings could be initiated against the concerned officials under the Contempt of Courts Act, 1971.

"Saw People Crying": Saurabh Bharadwaj Turns Emotional After Delhi Poll Defeat

New Delhi. Outgoing Delhi Health Minister Saurabh Bharadwaj was overcome with emotion as he addressed his supporters in a choked voice, saying he has accepted defeat in the Assembly polls "in the spirit of sportsmanship".At one point in his address, the AAP leader turned away from the microphone to compose himself. Struggling to hold back tears, he admitted that seeing his supporters emotional had deeply affected him.Mr Bharadwaj lost to BJP candidate Shikha Roy by a margin of 3,188 votes. Roy secured 49,594 votes,

while Mr Bharadwaj got 46,406. Congress' Garvit Singhvi finished a distant third with 6,711 votes.

The BJP registered a landslide victory in polls with 48 seats in the 70-member Delhi Assembly, while AAP -- which had won 62 assembly constituencies in 2020 and 67 in 2015 -- saw its tally plunge to 22. The Congress drew a blank for the third consecutive time.A clip of Mr Bharadwaj addressing his supporters has been widely circulated on social media. In it, the visibly emotional outgoing minister told his supporters that everyone worked very hard, and "I am extremely proud of all of you"."I was taking it in the spirit of sportsmanship, but when I saw people crying, I became emotional too," he added.February 8 marked a major shift in the Greater Kailash constituency, where Mr Bharadwaj had secured decisive victories in the 2015 and 2020 elections.In 2020, he won by a margin of 16,809 votes, polling 60,372 votes against the BJP's Shikha Roy, who secured 43,563 votes.

'Helped Criminal Escape': Raids In Delhi To Arrest AAP's Amanatullah Khan

NEW DELHI. Delhi Police this morning conducted multiple raids to arrest Aam Aadmi Party (AAP) Amanatullah Khan, who has been accused of leading an attack on a police team in Jamia Nagar. The joint operation by the teams of Jamia Nagar and South East District police stations and Delhi Police's Crime Branch was launched a day after a case was filed against Mr Khan, who last week defeated BJP's Manish Chaudhary in the Okhla constituency in the recently concluded Delhi Assembly polls.

According to the police, the three-time MLA helped

Shabaz Khan, an accused in an attempt to murder case, escape from custody.The supporters of the AAP MLA reportedly confronted the police team due to which Shabaz fled from the spot.

Second Case Against Amanatullah Khan In A Week

Last week, a case was registered against Amanatullah Khan for allegedly violating the Model Code of Conduct (MCC) before the Delhi assembly elections.The case against Mr Khan was filed after he was seen campaigning with more than 100 supporters in Zakir Nagar Tuesday night.The case was registered under Section 223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), which deals with the punishment for disobeying orders given by public servants and Section 126 of The Representation of the People Act, 1951, which prohibits public meetings during a period of 48 hours ending with hour fixed for conclusion of poll.Mr Khan is among the Delhi MLAs with the highest number of criminal cases.

7 Kumbh returnees killed after their vehicle collides with truck in Madhya Pradesh

NEW DELHI. At least seven people, who were returning from the Maha Kumbh in Uttar Pradesh's Prayagraj, were killed after their tempo traveller collided with a truck on a highway in Madhya Pradesh's Jabalpur district on Tuesday.The accident occurred on NH-30 near Sihora and the victims who died belonged to Andhra Pradesh. An investigation is on to determine the cause of the accident.The devotees were returning after taking a holy dip at the Triveni Sangam - the confluence of the rivers Ganga, Yamuna and the mystical Saraswati - at the Maha Kumbh.

Jabalpur's Collector and Superintendent of Police (SP) reached the spot following the accident.

EARLIER ACCIDENTS INVOLVING MAHA KUMBH PILGRIMS

This is not the first instance of such accidents involving Maha Kumbh devotees.On Monday, a couple from Agra died and four others were injured when their car collided with a truck while they were returning from the Maha Kumbh. According to Station House Officer Rudra Pratap Singh, the truck was seized and the driver was detained.A man from Odisha's Rourkela died and six others were injured when a car carrying them from the Maha Kumbh to their home collided with a bus in Uttar Pradesh's Sonbhadra on Monday, police said.

The Maha Kumbh, the world's largest spiritual gathering, began on January 13. It will go on till February 26, the day when Maha Shivaratri will be observed.

According to Uttar Pradesh government data, over 44 crore devotees have taken a dip in the Triveni Sangam till February 9.On Monday, over 1.02 crore people took a holy dip till 4 pm, which included over 10 lakh Kalpwasis (devotees who stay on the banks of Ganga for a month) and 91.94 lakh pilgrims.

Not just reel estate. Where Indian Metro is adding 1000km to become world No. 2

While viral fights and dance videos on our Metro trains steal the spotlight, India's metro is silently rewriting the record books. India has 1,000 km of metro network across 17 cities, and is adding another 1,000 km to it. This is where and how the country is adding metro lines to overtake the US as the world's second-biggest Metro network.

New Delhi. Almost every other day, Metro trains in India make headlines. Sometimes due to scuffles over seats, and arguments over queue-cutting. Videos of some of these incidents are intense, while others are funny. Then there are social experiments, musical performances. More frequently these days, content creators and reel-makers have been turning Metro trains into their shoot locations. These clips with virality often steal the spotlight. But beyond these everyday incidents, a much larger Metro story is unfolding. It's one of rapid expansion, connectivity, and transformation of India's cities.

Prime Minister Narendra Modi on February 4 said it was a matter of pride that Metro networks across India had "crossed 1,000 kilometres". While emphasising the achievement in Parliament, he also revealed that work was underway to add another 1,000 kilometres.

The addition to the old Metro routes and new networks would make India the country with the second-longest Metro network in the world. India's Metro saga has been one of rapid expansions in the last 10 years.

In 2014, the total Metro network spanned just 248 kilometres. However, following the Metro Rail Policy of 2017, it has now grown to 1,000 kilometres.

With ongoing expansions of 17 existing Metro systems, several approved and under-construction projects, and at least 30 proposed Metro networks, India is on track to add another 1,000 kilometres swiftly.

"In the past 10 years, Delhi's Metro network has doubled, and now Metro networks are also reaching Tier 2 and Tier 3 cities. We can all take pride in the fact that India's Metro network has now crossed 1,000 kilometres.... Work is also underway on an additional 1,000 kilometres," PM Modi said in the Lok Sabha, during the Motion of Thanks on the President's address.

METRO RAIL IN INDIA TOOK 4 DECADES TO REACH 1,000KM

The Metro rail in India that commenced in Calcutta (now Kolkata) in 1984, took four decades to reach the 1,000 kilometre mark. With 17 Metro systems across India, the country now boasts the third-largest Metro network in the world, trailing only China and the USA. But the growth doesn't stop there.

Expansion of existing networks is already in progress -- Delhi Metro's Phase VI alone is set to add another 65 kilometres by 2026. This will take the total length of the Delhi Metro beyond 450 kilometres.

Unlike Delhi, whose Metro network is now near saturation, other existing metro systems in India, barring Kolkata's, started in the last two decades.

These Metro systems, like Agra (7 km), Bangalore (76 km), Chennai (54 km), Hyderabad (69 km), Jaipur (11 km), Kanpur (8 km), Kochi (28 km), Nagpur (38 km), Lucknow (22 km), Mumbai (59 km), and Pune (33 km), are expanding.

Women's panel seeks measures against obscene content on OTT, social media sites

NEW DELHI. The National Commission for Women has raised concerns about obscene content on streaming platforms and social media. It has urged the government to take regulatory action to address the issue.In a letter to the Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw, the commission's chairperson, Vijaya Rahatkar, called for immediate measures to curb the spread of such material.The commission said the content is widely accessible and affects

society, particularly women and children.

The panel cited violations of several laws, including the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, the Bhartiya Nyay Sanhita (BNS), the Protection of Children from Sexual Offences Act, and the Information Technology Act.It has asked the ministry to issue strict guidelines preventing platforms from streaming or allowing users to upload inappropriate content. It also called for stronger content moderation and enforcement measures.The commission has requested that the ministry inform it of any action taken to ensure follow-up on the matter.

Tirupati Laddoo Row: Report Cites How Blacklisted Dairies Sealed Ghee Deal

Claims the ghee used to make Tirupati laddoo contained animal fat made headlines last year, reaching the Supreme Court and sparking a religious and political row.

New Delhi. The four men arrested in the Tirupati laddoo row - on charges the ghee they supplied had animal fats - "hatched a conspiracy" to sell from companies blacklisted for supplying adulterated products, the police have said in a remand report that has been accessed by .

In the 14-page report, Tirupati Police said the investigation so far suggests these four men conspired to set up proxy companies and provided false documents, including those testifying about food safety standards and even the actual production process, to illegally win tenders.The four men are Pomil Jai and Vipin Jain, Directors of Bhole Baba Dairy and Vyshnavi Dairy; Apurva Chavda, CEO of Vyshnavi Dairy; and R Rajasekaran, Managing Director of AR Dairy. All four have been arrested by the special CBI team conducting this investigation.

Claims the ghee used to make the world-famous Tirupati laddoo contained animal fat made headlines last year, reaching the Supreme Court and sparking a religious and political row.The top court noted "religion and politics cannot be allowed to mix", but ordered the federal agency to fully investigate, with help from Andhra Pradesh Police and a senior official from the central government-run Food Safety and Standards Authority of India, these allegations.The remand report submitted by that team this week outlines several instances in which one or more of the four dairies mentioned manipulated documents and prices to win tenders.

One such example, the report said, was AR Dairy claiming to be able to supply at least six tonnes of cow milk fat per day from dairies within 1,500 km of Tirupati, as required by the tender.

However, the special team, or SIT, found this claim to be false, and that AR Dairy had "submitted false and fabricated documents... in collusion and conspiracy

with others" to alter butter, ghee, and milk production figures for earlier years to show they could meet future targets.The SIT claimed, "... actual procurement of cow milk fat handling per annum for AR Dairy, as per FSSAI report 2022/23 was 945.6 metric tonnes, or MT, of butter and 56.80 MT of ghee... however FSSAI report submitted with tender was altered with a figure of... 196.80 MT for ghee..."The SIT also claimed quoted ghee supply prices (per kg) in tenders were manipulated, as were figures for minimum procurement of milk per day; for 2022/23 R Rajasekaran allegedly " submitted false details... 2.52 lakh litres per day even though their average milk procurement was 1.45 lakh litres per day". The tender required a minimum capacity of two lakh litres per day.Other red flags raised by the remand report were that the ghee AR Dairy claimed to be supply was, in fact, supplied from Vyshnavi Dairy via Bhole Baba Dairy. "AR Dairy removed the seals... affixed their seals (and) prepared the documents as if the ghee was manufactured (there)".

"It is submitted that Apurva Chavda (CEO of Vyshnavi Dairy) approached Rajasekaran (MD of AR Dairy) for participating in the tender process... assuring he will take care of supply of ghee and Rs 2.75 to Rs 3 per kg commission was offered to AR Dairy", the remand report said.

NEWS BOX

Nancy Mace accuses ex-fiancé, associates of assaulting her raping others in House speech

CHAPIN. Nancy Mace of South Carolina on Monday used a nearly hour-long speech on the US House floor to accuse her ex-fiancé of physically abusing her, recording sex acts with her and others without their consent, and conspiring with business associates in acts of rape and sexual misconduct.

Mace said she was speaking out because her home state's top prosecutor didn't take action even after she alerted investigators.That same prosecutor is likely to be Mace's opponent if she runs for governor of South Carolina in 2026, which she is considering.Saying she was going scorched earth, Mace detailed how, in November 2023, she says she accidentally uncovered some of the most heinous crimes against women imaginable.We're talking about rape, non-consensual photos, non-consensual videos of women and underage girls, and the premeditated, calculated exploitation of women and girls in my district.Mace mentioned four men as being involved, including Charleston-area businessman Patrick Bryant, who was her fiancé until 2023 and went door-to-door stumping for her during her 2022 reelection campaign.

The AP wasn't able to independently verify Mace's claims.Speaking to AP, Bryant said, "I categorically deny these allegations. I take this matter seriously and will cooperate fully with any necessary legal processes to clear my name."

Mace accused South Carolina Attorney General Alan Wilson of slow-walking any investigation of Bryant and the other men after she brought the photos and video to state authorities.Did South Carolina's attorney geeral have any of these predators indicted after being provided clear cut-and-dry evidence including video, photos and witnesses??Mace asked, noting that her office had stood up a tip line for anyone with information on the allegations.In a statement after Mace's speech, Wilson's office called her comments regarding the prosecutor's conduct categorically false and said the office has not received any reports or requests for assistance from any law enforcement or prosecution agencies regarding these matters.

Eggs Worth Rs 33,000 Stolen From US Cafe Amid Soaring Prices, Probe On

World Over 500 eggs worth Rs 33,000 have been stolen from a cafe in the US amid soaring prices. The theft occurred at Seattle's Luna Park Cafe last Wednesday and the police said the robbers stole approximately $780 (Rs 67,749) worth of food, including blueberries, bacon, ground beef, and "liquid egg products."

David Park, the general manager of the eatery, said that they mostly serve egg-based dishes and were already struggling to source them. The theft has made things even more difficult, putting a serious strain on the business."We couldn't order any eggs, so we had to drive around to different markets to find them. But even if you go to Costco or some grocery stores, it's hard to get eggs, so it's been very difficult," Park said, as per The NY Post.He said that the thieves didn't steal alcohol, which is more expensive than eggs, but specifically stole eggs, meat, and egg-related products due to the price surge.

Park said that when he received news of the robbery, he rushed to the cafe immediately and saw the suspects taking food. When he tried to catch them, they fled the scene.The Seattle Police Department is investigating the case and has not yet identified or caught the suspects.The robbery comes at a time when the US is facing soaring egg prices. Last week, around 1 lakh eggs worth Rs 34,84,329 were stolen from an organic farm in south-central Pennsylvania's Franklin County.

"Egg prices are going up because of the avian flu, which has killed nearly 136 million birds since 2022. The flu is driving people to buy more eggs than they usually do because they're anticipating higher prices and reduced grocery store supply," Emory University Associate Marketing Professor Saloni Vastan said.

Indian Nelore Breed Cow Breaks World Record, Sells For Rs 40 Crore

World An Indian-origin cow, sold for Rs 40 crore at an auction in Minas Gerais, Brazil, has set the Guinness World Record for being the most expensive cattle. Viatina-19 reportedly weighs around 1,101 kg, twice the average weight of other cows of the same Nelore breed.The 53-month-old stands out for her gorgeous white fur, loose skin, and a noticeable hump on her shoulders.In addition to setting a world record, Viatina-19 won Miss South America at the "Champion of the World" competition in Fort Worth, Texas. It's a Miss Universe-style cattle contest pitting bulls and cows from various nations against one another. Her exceptional muscle structure and rare genetic lineage contributed to her victory.

The Nelore breed is well known for its ability to adapt to tropical climates and disease resistance. Due to this, Viatina-19's embryos are in high demand globally for breeding programs.

Lorrany Martins, a veterinarian, said that Viatina-19 was the closest to perfection attained so far. "She's a complete cow and has all the characteristics that proprietors are looking for," Martins added.According to Oklahoma State University data, Brazil is now the world's largest breeder of Nelore cattle, and the breed has been exported to Argentina, Paraguay, Venezuela, Central America, Mexico, the United States, and numerous other nations.

At least 80 per cent of cows in Brazil are Zebu cattle, a subspecies that originated in India and is distinguished by its hump and dewlap.

US judges challenge Trump cuts as legal battles mount

WASHINGTON. The Trump administration was on a collision course with the US courts Monday, with federal judges questioning the legality of the White House's cost-cutting onslaught of government and Vice President J D Vance warning the judiciary to back off.In his first three weeks in office, President Donald Trump has issued a flurry of executive orders aimed at slashing federal spending, appointing SpaceX and Tesla CEO Elon Musk to lead efforts that critics widely denounce as unconstitutional.Trump's sweeping plans, which have effectively shuttered some federal agencies and sent staff home, have sparked legal battles across the country. Multiple lawsuits seek to halt what opponents characterize as an illegal power grab.Musk's team has moved aggressively through federal agencies, freezing aid programs and pushing workforce reductions through controversial buyout offers and termination threats.Democrats, unions and activists, after initially struggling to respond, are now pursuing legal action and their numerous cases challenging Trump's plans have drawn sharp criticism from the White House.In a social media post Sunday, Vance argued that judges lack authority to "control the executive's legitimate power," comparing judicial intervention to a judge dictating military strategy to a general.

"Judicial tyranny is grossly improper!" Musk said, echoing the White House pushback.

Their comments followed a judge's emergency order early Saturday blocking Musk's government reform team from accessing millions of Americans' personal and financial data stored at the Treasury Department.Democratic attorneys general from 19 states filed that case Friday against the Republican president, the Treasury Department and the man who leads it, Scott Bessent.Separately, a federal judge in Rhode Island on Monday said the Trump administration had violated a previous order lifting a sweeping federal funding freeze."The broad categorical and sweeping freeze of federal funds is, as the Court found, likely unconstitutional and has caused and continues to cause irreparable harm to a vast portion of this country," the order stated.It was the first time since Trump took office and unfurled his "shock and awe" reform campaign that a federal judge accused his administration of defying a court order.

Unprecedented

In Boston, another federal judge ruled Monday that the government must extend the deadline for a controversial federal worker buyout offer that legal experts consider vague and potentially illegal.The plan, announced January 28 in an email to federal employees titled "Fork in the road" -- echoing Musk's 2022 message to Twitter employees when he acquired and renamed the platform X -- offered workers eight months' pay in exchange for resigning, or risk future termination.While the US Office of Personnel Management, now run by Musk associates, extended the original Thursday deadline to Monday at 11:59 pm (Tuesday at 0459 GMT), Judge George O'Toole ordered a further delay pending his decision.Civil service unions had filed for a preliminary injunction to pause the offer until courts could resolve the matter.

"This is an unprecedented action taken on an unprecedented timeline that is causing irreparable harm," attorney Elena Goldstein told the federal judge, according to WHDH-TV news.US media reported that at least 65,000 federal workers had accepted the so-called deferred resignation program as of last week."If people don't show up to work, we have a right to fire them," Trump told journalists at the White House Monday, emphasizing his belief that federal employees who were allowed to work from home after the pandemic will not heed his order to return to the office.Despite the legal challenges.

Six US Congressmen write to new Attorney General against Adani's indictment in bribery case

WASHINGTON. As many as six US Congressmen have written to the newly appointed Attorney General of the United States against "questionable" decisions made by the US Department of Justice (DoJ) such as the indictment against the Adani Group in an alleged bribery scam, which "jeopardises the relationship with close ally India."

Lance Gooden, Pat Fallon, Mike Haridopolos, Brandon Gill, William R Timmmons and Brian Babin on February 10 wrote to Pamela Bedi, Attorney General of the US drawing "attention to some questionable decisions made by the DOJ under the Biden administration."The billionaire industrialist has been charged by US prosecutors for allegedly being part of a scheme to pay over USD 250 million (about Rs 2,100 crore) bribe to Indian officials in exchange of favourable terms for solar power contracts. This was concealed from the US banks and investors from whom the Adani group raised billions of dollars for the project, the prosecutors have alleged.

US law allows pursuing foreign corruption allegations if they involve certain links to American investors or markets.The Adani group, however, has denied the charges."Some of these

decisions involved selectively pursuing and abandoning cases, often acting against America's interests at home and abroad, jeopardizing relationships with close allies like India," the Congressmen said in the joint letter.India, they said, has been an important ally of the United States for decades. This relationship has flourished beyond politics, trade, and economics by evolving into a continuous socio-cultural exchange between the world's two largest democracies."This historical partnership and continuous dialogue between friends, however, was put at risk due to some unwise decisions by the Biden administration," they said.

"One such decision involves a questionable pursuit of a case against the Adani group, an Indian company whose executives are situated in India. " This case rests on the allegation that preparations were made by members of this company in India to bribe Indian officials, also exclusively located in India," they wrote."Instead of deferring the case to the appropriate Indian authorities, the Biden DOJ decided to push forward and indict the company's executives without any real injury to US interests being present," the letter read.

The Congressmen said there was no compelling reason to pursue a case in a manner that could complicate relations with an ally like India unless some external factors were at play."This misguided crusade came at the risk of harming our relationship with a strategic geopolitical partner like India immediately preceding President Trump's return to the Oval Office.

Mark Zuckerberg Discusses Legal Challenges In Pakistan Over Blasphemous Content Lawsuit

World Mark Zuckerberg, CEO of Meta, recently discussed a legal battle in Pakistan, where he was sued over content deemed blasphemous on Facebook, highlighting the challenges posed by differing legal frameworks around the world.

In an interview with Joe Rogan, Zuckerberg explained how such laws, which conflict with free expression values upheld by American tech companies, add pressure on global platforms to regulate content more strictly."There are laws in different countries that we disagree with. For example, there was a point at which someone was trying to get me sentenced to death in Pakistan because someone on Facebook had a picture where they had a drawing of Prophet Mohammed, and someone said, 'That's blasphemy in our culture.' They sued me and opened this criminal proceeding. I don't know exactly where it went because I'm just not planning to go to Pakistan, so I was not that worried about it," Zuckerberg said during an interview with

acclaimed podcaster Joe Rogan.He acknowledged that the situation was unsettling, particularly in terms of personal safety. "But it was a little bit disconcerting - I was like, alright, these guys are like - it's not great (if you're) flying over that region, you don't want your plane to go down above Pakistan, if that thing goes through. That one was sort of avoidable."

More broadly, Zuckerberg highlighted the increasing pressure on tech companies from governments that seek stricter content regulation. "The point is, there are places around the world that just have different values that go against our free expression values and want us to crack down and ban way more stuff than I think a lot of people would believe would be the right thing to do. To have those governments be able to exert the power of saying they're going to throw you in prison - that's a lot of force. I think this is one of the things that the US government is probably going to need to help defend the American tech companies for abroad."Earlier, on January 7, Zuckerberg announced Meta's decision to replace its fact-checking systems on Facebook and Instagram with a "community notes" model, similar to the approach taken by Elon Musk's X. He justified the change by stating that Meta's fact-checking had resulted in "too many mistakes and too much censorship" and was "too politically biased.

Labour unions sue to block DOGE access to sensitive information at US agencies

WASHINGTON. A coalition of labour unions filed a lawsuit Monday asking a federal court to stop Elon Musk's team from accessing private data at the Education Department, the Treasury Department and the Office of Personnel Management.The suit, led by the American Federation of Teachers, alleges the Trump administration violated federal privacy laws when it gave Musk's Department of Government Efficiency access to systems with personal information on tens of millions of Americans without their consent. It was filed in federal court in Maryland.It's the latest in a flurry of legal challenges to Musk's growing influence over federal agencies he has promised to slash or dismantle. A federal judge in New York blocked Musk's team from a Treasury Department system on Saturday after 19 Democratic attorneys general sued over privacy concerns.Also Monday, DOGE cut about $900 million in Education Department contracts after concluding they were a waste of taxpayer money, a department spokesperson said. The cuts spanned 90 contracts at the Institute of Education Sciences, a research branch of the federal agency. The department did not immediately release additional details.The cuts will not affect core operations at IES, including the NAEP exam, known as the nation's report card, and the College Scorecard, which provides data about the cost and outcomes of U.S. universities, the department said.

The AFT suit warns of safety risks to personal data that has been shared with Musk's team, including an Education Department system housing information on more than 40 million Americans with federal student loans. The database includes Social Security numbers, driver's license numbers, home addresses and more."The Department is effectively one of America's biggest banks — if there was a breach of this magnitude in the private sector, it would rightly be a national scandal," said Randi Weingarten, president of the AFT.

The lawsuit accuses the Trump administration of handing over sensitive data for reasons beyond its intended use, allegedly violating the Privacy Act. Instead of carrying out the functions of the federal student loan program, the lawsuit says DOGE has been accessing loan data "for purposes of destroying" the Education Department.President Donald Trump has vowed to close the Education Department and turn over its authority to states and schools. Musk on his social media site X said Friday that the department "doesn't exist," responding to Democrats in Congress who attempted to visit the agency's headquarters but were turned away by security.The suit asks a federal court to stop Musk's team from accessing that data along with Treasury systems and an OPM database with sensitive information on all 2.3 million federal employees. It also seeks the destruction of any records that were already disclosed.

Trump will host Jordan's King Abdullah II as he escalates pressure on his Gaza resettlement plan

WASHINGTON. President Donald Trump will host Jordan's King Abdullah II at the White House on Tuesday as he escalates pressure on the Arab nation to take in refugees from Gaza — perhaps permanently — as part of his audacious plan to remake the Middle East.The visit is happening at a perilous moment for the ongoing ceasefire in Gaza as Hamas, accusing Israel of violating the truce, has said it is pausing future releases of hostages and as Trump has called for Israel to resume fighting if all those remaining in captivity are not freed by this weekend.Trump has proposed the US take control of Gaza and turn it into "the Riviera of the Middle East," with Palestinians in the war-torn territory pushed into neighboring nations with no right of return.He suggested on Monday that, if necessary, he would withhold U.S. funding from Jordan and Egypt, longtime U.S. allies and among the top recipients of its foreign aid, as a means of persuading them to accept additional Palestinians from Gaza."Yeah, maybe. Sure, why not?" Trump told reporters. "If they don't, I would conceivably withhold aid, yes."

Jordan is home to more than 2 million Palestinians and, along with other Arab states, has flatly rejected Trump's plan to relocate civilians from Gaza.

Jordan's foreign minister, Ayman Safadi, said last week that his country's opposition to Trump's idea was "firm and unwavering."In addition to concerns about jeopardizing the long-held goals of a two-state solution to the Israel-Palestinian conflict, Egypt and Jordan have privately raised security concerns about welcoming large numbers of additional refugees into their countries even temporarily.

When asked how he'd persuade Abdullah to take in Palestinians, Trump told reporters, "I do think he'll take, and I think other countries will take also. They have good hearts."The king is also meeting with top Trump administration officials during his visit, including Secretary of State Marco

Rubio, national security adviser Mike Waltz, Middle East envoy Steve Witkoff and Defense Secretary Pete Hegseth. He is the third foreign leader to hold an in-person meeting with Tump since his Jan. 20 inauguration.Trump announced his ideas for resettling Palestinians from Gaza and taking ownership of the territory for the U.S. during a press conference last week with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.Trump initially didn't rule out deploying U.S. troops to help secure Gaza but at the same time insisted no U.S. funds would go to pay for the reconstruction of the territory, raising fundamental questions about the nature of his plan.After Trump's initial comments, Rubio and White House press secretary Karoline Leavitt insisted that Trump only wanted Palestinians relocated from Gaza "temporarily" and sought an "interim" period to allow for debris removal, the disposal of unexploded ordnance and reconstruction.

But asked in an interview with Fox News' Bret Baier that aired Monday if Palestinians in Gaza would have a right to return to the territory under his plan, he replied, "No, they wouldn't."

NEWS BOX

TNTA has high hopes for tennis in the city

There is something about the Chennai Open ATP Challenger tournament. Even though it is a Challenger 100 competition, there is a certain degree of competition and there is some romance around the one of most loved sports in the city. Right from the Krishnans (senior and junior), the Amritraj brothers, Leander Paes, Somdev Devvarman, the city has a different kind of aura when it comes to the sport. Like always, tennis brings joy. It is a platform to launch one's career as well. This year is special, too. The Tamil Nadu Tennis Association (TNTA) is celebrating its centenary year.In the last ATP Challenger here, Sumit Nagal, India's top player, won the event and went on to crack into the top hundred in world ranking, eventually reaching a career-high ranking of 68 later in the year.TNTA, once again, hosted the Chennai Open with the professionalism they are known for. But they are yearning for bigger events as well. A top TNTA official said its chief Vijay Amritraj is working with the Tamil Nadu government to bring the ATP 250 event back to the city.

One of the positives this season was the run of Indian duo Ramkumar Ramanathan and

Saketh Myneni. They finished runners-up in the doubles after losing to Japan's Shintaro Mochizuki and Kaito Uesugi. Players from 14 countries participated. With a sprinkling of young talent, the draw was pretty tough. The top seed was Billy Harris of Great Britain, who ranked 127 in the world and is now among the top 8 in Great Britain. He was followed at No 2 by Lloyd Harris of the Republic of South Africa ranked 135. The others were Duje Ajdukovic (CRO-138), Shintaro Mochizuki (JPN-169), Sho Shimabukuro (JPN-191), Timofey Skatov (KAZ-194), Alexis Galarneau (CAN-198), Khumoyun Sultanov (UZB - 216), and Aslan Karatsev (222). Frenchman Kyrian Jacquet put his experience to good use — to beat Sweden's Elias Ymer and bag the singles title."The tournament went about smoothly manner and all the players from the world were happy. Since the Tamil Nadu Tennis Association has been organising the Davis Cup and the ATP events for several decades now, we have the experience to conduct professionally," said Hiten Joshi, CEO of TNTA.So this year, too, tennis aficionados were expecting an Indian would win the singles event. "We would have been happy had an Indian won.

Varun in, Bumrah out Will India make changes in final Champions Trophy squad

The deadline day for finalising squad for the Champions Trophy is here. With the ICC set to lock-in squads on February 11, Tuesday, will India make changes to its preliminary side

New Delhi. I The deadline to finalise the Champions Trophy squad has arrived. The 8 teams selected for the tournament must hand in their final 15-member squad for the ICC tournament set to begin on 19 February. The Indian team, one of the favourites to lift the trophy, is currently in a fix, given the condition of their premier fast bowler, Jasprit Bumrah.The Indian speedster has not played a single match since pulling out midway through the final Test match of the Border-Gavaskar Trophy in January. Bumrah, out of action due to a back injury, was expected to make his return in the ODI series vs. England, but no one, not even the members of the Indian team, has been able to provide any update regarding him.According to reports, the Indian team is expected to take a call on Bumrah on Tuesday, 11 February, and in case the pacer is not able to make it to the tournament, a couple of changes will be on the cards.

India's Preliminary Squad for Champions Trophy 2025Rohit Sharma (captain), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul (wicketkeeper), Hardik Pandya, Axar Patel, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammad Shami, Arshdeep Singh, Yashasvi Jaiswal, Rishabh Pant, Ravindra Jadeja.

India's Latest Debutants

Knowing well that Bumrah might be touch and go for the Champions Trophy, India handed debuts to two full-time bowlers in their ongoing ODI series against England. Harshit Rana, potentially a direct replacement for Jasprit Bumrah, has played both matches so far and has impressed in the middle overs.The other debut has come in the form of Varun Chakravarthy, the mystery spinner, who absolutely ran through England in the T20I series ahead of the ODI leg of the tour. Rana can turn out to be a decent replacement for Bumrah. The Delhi speedster has shown that he has that fast bowler's aggression in him, which could turn out to be quite handy for India.

India already has Mohammad Shami and Arshdeep Singh in the squad – two of India's most astute new-ball bowlers. The side also has Hardik Pandya for support, who has bowled with the new ball in the recently concluded T20I series.

Toss-up Between Washi & Kuldeep?

Selected for the ODI series vs. England and the Champions Trophy, Washington Sundar did not play the first two matches of the series. Sundar, who had cemented his place in the T20I side under Gambhir, remained on the bench as Axar Patel was favoured over the Tamil Nadu player.

On the other hand, there was less trust shown in Kuldeep Yadav as well, who did not set the stage on fire in the 1st ODI vs. England. Kuldeep was dropped for the next game, and Varun Chakravarthy was handed a debut.

If India are to include Varun as the X-Factor, they will have to let go of either Kuldeep or Sundar from the side.Given that India has the assurance of Axar Patel and Ravindra Jadeja in the spin-bowling allrounders' role, it is unlikely that Sundar will get the final nod for the Champions Trophy. Kuldeep, on the other hand, is likely to find a place in the final 15, given he is the only (orthodox) wrist spinner in the side.It needs to be mentioned that there are provisions to make changes after 11 February as well, but for that, teams have to get the permission of the International Cricket Council (ICC). India is expected to take travelling reserves with them and might carry the likes of Bumrah and Washington in that extended squad.

National selector Ajit Agarkar had mentioned in January that Bumrah might be fit to play ODIs after the first couple of matches in the Champions Trophy. If India carries Bumrah in the extended squad, the team has the option to shoe him into the team.

Ranji Trophy quarters: Ajinkya Rahane hits hundred to celebrate special 200 in style

Ranji Trophy 2024-25: Ajinkya Rahane celebrated his 200th first-class appearance by hitting a match-defining hundred against Haryana in the quarter-final at Eden Gardens in Kolkata.

New Delhi. Ajinkya Rahane led Mumbai from the front with the bat in their Ranji Trophy quarter-final against Haryana in Kolkata, scoring a second-innings century on Tuesday, February 11. Rahane, who was unbeaten on 88 overnight, reached his 29th first-class century during the morning session.

It was Rahane's 200th first-class match, and the seasoned batter marked the milestone in style, all but guaranteeing Mumbai's progress to the semi-final. The defending champions extended their lead beyond 300 runs before Rahane was dismissed for 108 by Anuj Thakarai. Rahane now has a total of 41 first-class centuries, including 12 in Test cricket. The right-handed batter is also closing in on 14,000 runs in the red-ball format.Rahane struck 13 boundaries during his 180-ball 108, which was his

first century of the ongoing Ranji Trophy season. The Mumbai captain forged a 129-run partnership with India's T20I captain Suryakumar Yadav on Monday before the latter fell for 70.All-rounder Shivam Dube contributed 48 as Mumbai's top and middle order stepped up after a poor first innings. Rahane's 31 had been the lone bright spot in the top order as Mumbai relied on Shams Mulani (91) and Tanush Kotian (97) to recover from 113 for 7 and post a total of 315.

With the ball, Mumbai fought back strongly. Shardul Thakur picked up six wickets to trigger a Haryana collapse, reducing them from 257 for 4 to 301 all out, conceding a crucial 14-run first-innings lead.

RAHANE IN FINE FORM

Rahane has scored 437 runs in 12 innings in the 2024–25 Ranji Trophy season, including a century and two fifties. The star batter, who has not played Test cricket for India since July 2023, has remained consistent in domestic cricket. Earlier this season, he made an impression in the Syed Mushtaq Ali T20 tournament, amassing 469 runs in nine matches at an average of 58.62 and a strike rate of 164.56—setting the stage for the Indian Premier League 2025 season.Rahane, who represented Chennai Super Kings in the 2023 and 2024 seasons, will return to Kolkata Knight Riders for the 2025 season, which is set to commence on 21 March.

Vidarbha in driver's seat against Tamil Nadu

CHENNAI: Riding on Aditya Thakare's penetrative bowling (5/34), Vidarbha bagged a handsome first innings lead of 128 runs over Tamil Nadu on the third day of their Ranji Trophy quarterfinals being played at Nagpur on Monday. Apart from Thakare, Yash Thakur and Nachiket Bhute bowled lively spells in turns to trouble the Tamil Nadu batters. They bowled in the right areas and extracted good bounce to induce the Tamil Nadu batters to commit mistakes.

Later, an unbeaten 55 by Yash Rathod came in handy for the hosts as they were able to recover from a top order collapse to post 169 for 5 in 69 overs in their second essay. Harsh Dubey lent solid support to Rathod and was batting on 29, when bails were drawn. Their effort has put Vidarbha in a commanding position with an overall lead of 297 runs.

Earlier in the morning, Tamil Nadu's hopes relied on the last recognised pair of Pradosh Ranjan Paul and Sai Kishore to stitch a partnership and reduce the deficit. But Sai Kishore fell to Thakur and soon M Mohammed also departed. Pradosh then managed to hang around with Sonu Yadav

(32) and helped Tami Nadu breach the 200-run mark."It was a brilliant display by our attack. They were spot on and knew what lengths to bowl. Aditya used the surface to his advantage. He bowled in the right areas and could get good movement," Dubey told this daily after the day's play.

"We knew that Pradosh was the last batter for Tamil Nadu. So we were aware that the sooner we get him out bigger will be our lead. Yes, at the end of the day we have a fairly good lead," added the left-arm spinner.One expected Vidarbha to bat better in the second essay and perhaps even bat out the opposition. But that was not to be as Sai Kishore led from the front and with an aggressive approach troubled Vidarbha's top order. He was aided in the cause by Sonu Yadav and Vijay Shankar who were accurate.

Constant spotlight on Virat Kohli is quite unnecessary: Arjuna Ranatunga

New Delhi. Former Sri Lanka captain and World Cup winner Arjuna Ranatunga feels that the spotlight constantly being on Virat Kohli is quite unnecessary and the star batter should be given the freedom to make a decision about his future. Kohli hasn't had the best of times with the bat in the past few months as the failure in the Border-Gavaskar Trophy put his position in the team under scrutiny.Kohli made a return to the domestic circuit with Delhi in the Ranji Trophy, but he only scored 6 runs in his comeback. The poor run of form continued in the ODI series

against England as the star batter was dismissed for just 5 runs in the Cuttack ODI after missing the match in Nagpur due to an injury. Speaking to the Telegraph, Ranatunga said that the call on Kohli's future should be left in the hands of the player and the star batter should make his own path.

"For a player like Kohli who has scored so much of runs, I feel it's best if that's left to him. It's a call that Kohli needs to take, so let him take it. Why always have the spotlight on him? It's quite unnecessary I feel. It's his decision, so let him take that," said Ranatunga.

'Kohli needs to speak to legends'

Ranatunga also advised Kohli to talk to legends like Sunil Gavaskar, Dilip Vengsarkar or Rahul Dravid to help him arrest his poor run of form. The former Sri Lankan skipper feels that the legends can help the star batter in his bid to get back to form."I think what Kohli needs to do is speak to people like Sunil Gavaskar, Dilip Vengsarkar or a Rahul Dravid. That's what he can do. They can certainly help him out," said Ranatunga.Speaking about Kohli and Rohit Sharma regaining their form, Ranatunga felt it was just a matter of one good innings.

SL vs AUS ODIs: Vandersay in, Wickramasinghe out as Sri Lanka name strong squad

Sri Lanka have brought back Jeffrey Vandersay and decided to leave out Chamindu Wickramasinghe as they named a strong squad for the upcoming ODI series against Australia, starting on February 12.

New Delhi. The series follows Sri Lanka's 0-2 loss to Australia in the Test series. The Aussies come into the ODIs with many of their main names being ruled out of the 2-match series and the Champions Trophy. Captain Pat Cummins, Josh Hazlewood and Mitchell Marsh are all out of the upcoming matches with injuries. All-rounder Marcus Stoinis also announced his retirement from the ODI format as well. Multiple additions are expected to be made to the squad.The series between Sri Lanka and Australia will be played on February 12 and 14 and the matches will take place in Colombo.Sri Lanka squad for Australia ODIs:Charith Asalanka (C), Pathum Nissanka, Avishka Fernando, Kusal Mendis, Kamindu Mendis, Janith Liyanage, Nishan Madushka, Nuwanidu Fernando, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Dunith Wellalage, Jeffrey Vandersay, Asitha Fernando, Lahiru Kumara, Mohamed Shiraz, Eshan MalingaThe series follows Sri Lanka's 0-2 loss to Australia in the Test series. The Aussies come into the ODIs with many of their main names being ruled out of the 2-match series and the Champions Trophy. Captain Pat Cummins, Josh Hazlewood and Mitchell Marsh are all out of the upcoming matches with injuries. All-rounder Marcus Stoinis also announced his retirement from the ODI format as well. Multiple additions are expected to be made to the squad.The series between Sri Lanka and Australia will be played on February 12 and 14 and .

Champions Trophy: Saim Ayub-less Pakistan face stiff challenge to end barren run

Champions Trophy 2025 Preview: Pakistan have done well recently under Mohammad Rizwan's captaincy, but having not won an ICC title since 2017, they will be under pressure to put up a good show in front of their home crowd.

New Delhi. Pakistan will be one of the teams to watch out for when the Champions Trophy gets underway on February 19. Mohammad Rizwan has been impressive as their ODI captain after taking charge back in October 2024, but playing in the upcoming event would come with its challenges and expectations, since Pakistan are the defending champions.Babar Azam, Fakhar Zaman and Faheem Ashraf are the members of the 2017 squad who will also take part in the upcoming edition. Rizwan's men will start their campaign in the Champions Trophy against New Zealand on Wednesday, February 19 at the Gaddafi Stadium in Lahore.But before the tournament, Pakistan have certain areas to focus on after injury concerns to two of their key players. Having not won an ICC trophy since 2017, pressure will be on the hosts to deliver.

Saim Ayub major missing

Saim Ayub was in the form of his life and also featured in the ICC ODI Team of the Year. Having scored multiple hundreds on the tour of South Africa, the left-handed batter looked in ominous form. But an ankle injury against the Proteas ended his dreams of representing Pakistan in the Champions Trophy. Ayub had to be taken off on a stretcher after he sustained the injury while trying to chase the ball down during the second Test.With Ayub not there, Babar Azam is most likely to open the batting alongside Fakhar Zaman, who also made his comeback recently. Pakistan also have Usman Khan and Tayyab Tahir, who have

both played as openers in the past at various levels. There is no Abdullah Shafique either after he bagged a hat-trick of ducks in the ODI series on South African soil.

Haris Rauf 100 per cent?

Pakistan have a bunch of lethal pacers, including Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah, Haris Rauf and Mohammad Hasnain. But amongst them, the 31-year-old Rauf has had issues with injuries. He played in the first match of the tri-nation series against New Zealand, but has been ruled out of Wednesday's clash against South Africa at the National Stadium in Karachi.Rauf sustained a muscular sprain in the lower chest wall region in the match against the Black Caps. Thereafter, the PCB took a precautionary measure of leaving Rauf out for the game against the Proteas. But his injury isn't serious, and the speedster is expected to gain full fitness before the Champions Trophy.

Faheem, Khushdil worth selection?

Faheem Ashraf and Khushdil Shah's selection for the Champions Trophy raised eyebrows. But skipper Mohammad Rizwan recently said that Faheem and Khushdil made their comebacks purely on the basis of performance. Khushdil returned to playing for Pakistan in the tri-nation series, while Faheem hasn't donned the national colours since December 2023."If we talk about Faheem Ashraf, if you look at his performance over the last two years in List A cricket, his average is 46.

Ananya Panday

Is Missing Her 'Little Koala' Nephew River, Mom Alanna Panday Reacts

Ananya Panday's cousin, social media influencer Alanna Panday, welcomed her first child, River, with husband Ivor McCray in July 2024. Since then, the Call Me Bae actress has fully embraced her role as a masi, cherishing every moment with her little munchkin. However, today feels different as she dearly misses her "little koala," who is currently vacationing in Alaska with his parents.The 26-year-old posted a series of pictures with baby River on her Instagram account, which perfectly captured their adorable bond. In the first image, Ananya held her nephew in one arm and hilariously tried to mimic his exact facial expression. The next slide showed the 8-month-old sleeping peacefully on his doting aunt's lap. The most endearing moment, however, was a clip in which baby River could be seen falling asleep as Ananya held him close to her heart.

In another picture, Ananya, dressed in a striking blue hoodie, was seen cradling her baby nephew carefully in her arms while the little one gazed at the camera. Two other images showcased River sleeping peacefully with his maasi just beside him. The caption of the post read: "Missing my little koala baby nephew River." It also featured a crying face and a red heart emoji. She posted the pictures with Audrey Hepburn's song Moon River.

Ananya's endearing post received many sweet reactions from her Insta family as well as the Panday family. River's mother, Alanna commented, "The video of him falling asleep on your lap." On the other hand, Ananya's aunt Deanne Panday wrote, "Awwwwwww, I miss him too a lot." Meanwhile, the actress' mother, Bhavana Pandey, reacted to the pictures, saying, "Tooooo cute."

Speaking of Ananya's work front, the actress who made her debut in 2019 with Karan Johar's Student of the Year 2, was last seen in Vikramaditya Motwane's screenlife thriller CTRL. Starring Vihaan Samat, the film highlighted the issue of technological advancement and the dangers of artificial intelligence.

As of now, the 26-year-old actress has Chand Mera Dil starring Lakshya, Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri opposite Kartik Aaryan and an untitled film with Akshay Kumar and R Madhavan. She is also busy filming the second season of the comedy-drama Call Me Bae.

Kapil Sharma Was Not Making Losses After Fight With Sunil Grover, Rajiv Thakur Recalls Their Fight

Rajiv Thakur has opened up about Kapil Sharma's infamous fight with Sunil Grover. Thakur, who was also a part of The Great Indian Kapil Show, recently shared his thoughts on Kapil's equation with Sunil and claimed that the two really enjoy working together.

"Who doesn't fight? If their fight was so serious, how are they still mingling and shooting together today? Money can make you work together, but if you observe the atmosphere on set, you'll see they genuinely enjoy each other's company," Rajiv told Siddharth Kannan recently, as quoted by Pinkvilla.

The actor-comedian further claimed that neither Kapil nor Sunil struggled with regard to their respective careers after fighting with each other. "When Sunil wasn't on the show, Kapil wasn't facing losses, and vice versa. You can't fake this camaraderie," he added.

Why Did Kapil Sharma And Sunil Grover Fight?

Kapil Sharma and Sunil Grover's fight is not a secret. Grover became a household name with his fictional characters Gutthi and Dr Mashoor Gulati in Comedy Nights With Kapil and The Kapil Sharma Show respectively. However, he had an ugly fight with Kapil in 2018 while they were returning from a show in Australia. They got into a heated argument following which Sunil stopped working with Kapil.

Kapil and Sunil were not on talking terms for six years. However, they reunited last year for the former's The Great Indian Kapil Show.

In March 2024, Sunil opened up about his fight with Kapil and joked that it was "a publicity stunt" they did for Netflix long before the streaming giant set foot in India.

"We were seated on the flight and we learnt that Netflix was coming to India. So, kuch aisa ho ke (acha) publicity stunt ho," Sunil said, poking fun at his and Kapil's fight. Sunil even joked that Netflix India had called them to ask what could be done and thus, this idea came to them.

Ankita Lokhande Slams Rozlyn Khan For Claims About Hina Khan's Cancer: 'That Is So Cheap'

Ankita Lokhande has lashed out at Rozlyn Khan for accusing Hina Khan of using cancer as a publicity stunt. Recently, Ankita took to her Instagram stories, shared a video of Rozlyn from one of her recent interviews and expressed disappointment with her claims. She called Rozlyn's allegations "cheap" and asked Hina to stay strong.

"How could someone think so low my goodness.. That's so cheap !! Ur kind information madam this girl Hina is fighting the cancer with such bravery and I'm saying because I know that and Vikki met her few days back in the hospital where she was taking her chemotherapy where Rocky was with her and literally Vikki said this to me that he was in tears to see her!! Hina u r strong and our sherkhan. And not easy for u or anyone who's facing this !! God bless u girl This shall too pass @realhinakhan," Ankita wrote.

Recently, Rozlyn Khan has been making several allegations against Hina Khan. While Rozlyn is a stage four cancer survivor, Hina is currently fighting her stage three breast cancer.

Previously, in an interview with News18 Showsha, Rozlyn accused Hina of spreading misinformation and said, "15 hours of mastectomy is impossible. She is exaggerating it. My surgery was 8 to 10 hours long because I was at stage four and my 16 lymph nodes were removed. It was a major surgery. In fact, she (Hina Khan) only said her surgery went for 15 hours. Which surgery is she talking about? She did not give details if it was MRM or what?"

Rozlyn Khan then made a big allegation and accused Hina Khan of using her cancer treatment as a publicity stunt. "She talks about herself rather than talking about the treatments she is taking. She is keeping everything in the dark. I doubt if she is at stage 3. Every interview or byte she gives only moves it around herself or her bravery." However, Hina Khan has not reacted to Rozlyn's claims as of now.

Vicky Kaushal Rashmika Mandanna Seek Blessings At Golden Temple Ahead Of Chhaava Release

Vicky Kaushal and Rashmika Mandanna have been busy with the promotions of their upcoming film 'Chhaava'. After they dazzled Mumbaikars with their appearance at Chitra Cinema in Mumbai yesterday, the Chhaava actors have now arrived in Amritsar. As soon as they landed in the city, they visited the Golden Temple. Videos and pictures from their visit to the holy site are going viral on social media.

Videos that have surfaced on social media show Rashmika Mandanna in a wheelchair. Vicky Kaushal walks next to her as they make their way to the Golden Temple. Rashmika was seen in a fuchsia pink ethnic suit, and a matching organza dupatta that covered her head. Meanwhile, Vicky wore a white kurta pajama, and covered his head with an orange scarf. Vicky was seen helping his co-actor as they entered the temple premises. Another set of pictures that have surfaced on social media show them posing with folded hands. Check out the pictures and videos below!

Vicky Kaushal also shared several pictures from their Golden Temple visit. He wrote, "There's something about #SriHarmandirSahib! The peace, the divinity, the power of prayer. As we bring #Chhaava to the world, I hope it reflects even a fraction of the strength and devotion this sacred place inspires. Rabb meher bakshe. Satnam Waheguru."

Meanwhile, a few hours ago, Rashmika Mandanna shared a picture with Vicky as they both arrived in Amritsar. They were both seen wearing Chhaava t-shirts. "Amritsar…Ki haal aaaa!!!!" wrote the actress, expressing her excitement for the promotional event in the city.Several videos from Chhaava Mumbai promotions on 9th Feb also surfaced on social media. Rashmika, who suffered a leg injury in January, informed the paparazzi that her injured leg is better now. As she joined Vicky for the promotional event in Mumbai, the latter urged the crowd to welcome her in true 'Dadar style'. He announced that he hasn't come for the promotion alone today, and that Rashmika has specially joined him from Hyderabad.